https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

MRUNAL ECONOMY 2020

Handouts

LECTURE 1- 30

CSP 2020 Hindi

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

ECONOMICS

SPECIAL for PRELIMS (Some topics of Main)

MRUNAL SIR CLASSES

सभी प्रसिद्ध हिन्दी माध्यम के और अंग्रेजी माध्यम के CLASS NOTES & 9th, 10th, 12th NCERT को COVER करता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims

TOPICS

https://t.me/UPSC_Mains

1. राष्ट्रीय आय और उत्पादन
2. राजकोषीय नीति, बजट
3. वित्तीय समावेशन + विकास एवं संवृद्धि
4. मनी एंड बैंकिंग
5. मौद्रिक नीति
6. मुद्रास्फीति, मुद्राअवस्फीति, मंदी
7. बैंकिंग प्रणाली का विकास
8. वित्त बाजार
9. शेयर बाजार
10. कर संरचना
11. चौदहवाँ वित्त आयोग Currents 15Th FC
12. भुगतान संतुलन (BoP)
13. विदेशी निवेश — FDI, FII/FPI.
14. आयोजन एवं प्रकार
15. पंच-वर्षीय योजनाएँ
16. बेरोजगारी } मनरेगा
17. गरीबी }
18. जनसंख्या
19. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान — IMF, AIIB, ADB, BRICS BAN WORLD BANK, WTO,
20. नई विदेश व्यापार नीति
21. विनिर्माण नीति
22. खाद्य सुरक्षा — PDS.

Read Currents & govt scheme carefully

https://t.me/UPSC_Prelims

https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

राष्ट्रीय आय और उत्पादन

उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें

- भूमि
- प्राकृतिक संसाधन
  - जल, वन, खनिज
- श्रम
- भौतिक पूंजी
  - स्थायी [मशीनें हल से लेकर कम्प्यूटर तक भवन, वाहन]
  - कार्यशील
    - कच्चा माल, नकद पैसा
- मानव पूंजी
  - ज्ञान (श्रेष्ठ)

आभूषण वित्तीय पूंजी है।

* इन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है।

→ गैर-कृषि क्रियाएँ — लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी etc.

→ जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वह भी मानव पूंजी में बदल जाती है। यह भी देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है।

[9998140145]. CONTACT ME FOR ANY QUERY/DOUBT & GUIDANCE, RELATED TO THIS NOTE AND UPSC STUDY...

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

उत्पादन क्षेत्र

प्राथमिक

i) कृषि
ii) वानिकी
iii) मछली पालन
iv) खनन एवं उत्खनन

द्वितीयक

i) विनिर्माण
ii) निर्माण
iii) जल विद्युत - गैस

तृतीयक

i) होटल
ii) परिवहन
iii) संचार
iv) भंडारण
v) बैंकिंग
vi) बीमा
vii) लोक - प्रशासन
viii) प्रतिरक्षा
ix) अन्य सेवाएँ / शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन

→ ये सब आर्थिक क्रियाएँ हैं और इनसे देश में राष्ट्रीय आय बढ़ती है।

> प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र में जितना अधिक विकास होगा सेवाओं की मांग उतनी ही बढ़ेगी।

→ जमीन से उत्पादन बढ़ाने का तरीका

- बहुविध फसल प्रणाली [एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल पैदा करना]
- आधुनिक कृषि विधियाँ जैसे हरित क्रांति के समय → अधिक पूंजी की आवश्यकता

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

FREE BOOKS, NOTES & VIDEOS FOR CIVILSERVICES



EBOOKS & MAGZINES



UPSC PRELIMS MATERIALS



USPC MAINS MATERIALS



VIDEO FOR CIVILSERVICES



DAILY NEWSAPERS



SECUREIAS



UPSC PRELIMS TESTSERIES



UPSC MAINS TESTSERIES



DELHI STUDENTS



CIVILSERVICES BOOKS

OPTIONAL SUBJECTS BOOKS, TEST SERIES, VIDEOS & NOTES	STATE PCS, SSC, BANKING BOOKS, TESTS VIDEOS & NOTES		
1.GEOGRAPHY	1.UPPSC	2.SSC	3.MPSC
2.HISTORY	4.IBPS	5.RAS & RPSC	
3.MATHEMATICS	ENGINEERING BOOKS & MATERIAL		
4. SOCIOLOGY	1. IES	2. GATE	3. IFoS
5.PUBLIC ADMINISTRATION	4. COMPUTER SCIENCE		
6. POLITICAL SCIENCE	5. MECHINICAL ENGINEERING		
7. ECONOMICS	OTHER TELEGRAM CHANNELS		
8 PHYSICS	1 GOVERNMENT JOBS		
9 COMMERCE ACCOUNTANCY	2 LEARN YOGA & MEDITATION		
10 ANTHROPOLOGY	3 LEARN ENGLISH		
11 LAW	4 BEST DELAS & OFFERS		
12 PHILOSOPHY	5 IAS HINDI BOOKS		
13 CHARTERED ACCOUNTANTANCY	6 PDFs FOR ALL EXAMS		
14 MEDICAL SCIENCE	7. WORLD DIGITAL LIBIRARY		
1.CHENNAI STUDENTS	2.BANGLORE STUDENTS	3. CURRENT AFFAIRS	

CONTACT FOR ADVERTISEMENT IN ABOVE CHANNLES

ADMIN1:	ADMIN2:

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

राष्ट्रीय आय और उत्पाद की कुछ मुख्य अवधारणाएं :-

1. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) —— ⊛ CSO निकालता है (1995)

→ एक वर्ष के दौरान
→ घरेलू सीमा के अंदर
→ निवासियों द्वारा
→ अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों का समग्र योग
→ इसमें देश के घरेलू + विदेशी निवासी शामिल हैं।

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

eg:—

1 Kg गेहूँ → 1 Kg आय

↓

1 Kg ब्रेड

⊛ तो 1 Kg ब्रेड को count करना है।

2. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) ——

↓

GDP + विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय —— (Minus)
भारत में रहने वाले विदेशियों की आय

3. विशुद्ध/निवल/शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) ——

↓

GNP — मशीनों की घिसावट/मूल्य ह्रास, कर व्यय
(Depriciation)

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

4. शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI) —

↓

बाजार कीमत पर NNP_{MP} — अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी

→ आधार वर्ष 2011-12 (2004-05 के 8वां स्थान पर).

→ राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन स्थिर कीमत पर **वास्तविक** हो जाता है।

→ निगम कर को राष्ट्रीय आय से घटाना होगा, क्योंकि यह परिवारों को नहीं मिलता।

→ उल्लेखनीय है कि CSO द्वारा वर्ष 2015 में जारी निर्देश के अनुसार स्थिर बाजार मूल्य पर व्यक्त GDP जो कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के Basic मूल्य पर व्यक्त सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) का योग होगा, राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करेगा।

→ GDP को उच्च कल्याण का सूचकांक नहीं माना जा सकता क्योंकि किसी की आय बढ़ जाती है तो किसी की कम हो जाती है।

जैसे — कंपनी लगाने से GDP बढ़ेगा लेकिन कंपनी के प्रदूषण से गरीब आदमी के मछली पालन, कृषि आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

5. प्रति व्यक्ति आय (PCI) —

→ किसी भी देश में आर्थिक कल्याण का ठीक से पता लगाने के लिए PCI एक सर्वश्रेष्ठ मापदंड होती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग आर्थिक कल्याण के अच्छे स्तर पर हो।

"Largest Economies are not the Richest."

— [World Bank].

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Note: 2019, CSO+NSSO= NSO

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

6. मौद्रिक राष्ट्रीय आय

→ चालू की मूल्यों का प्रयोग किया जाता है

→ इसे प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं।

चालू मूल्य पर व्यक्त जीडीपी तथा स्थिर मूल्य पर व्यक्त जीडीपी

- जब जीडीपी की गणना बाज़ार में प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य पर की जाती है तो इसे चालू मूल्य पर व्यक्त जीडीपी या मौद्रिक (Nominal GDP) जीडीपी कहते हैं।
- इसके विपरीत जब जीडीपी की गणना में स्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिये जीडीपी को किसी पिछले वर्ष (आधार-वर्ष) के मूल्य के आधार पर व्यक्त करते हैं तो इसे स्थिर मूल्य पर जीडीपी या वास्तविक जीडीपी (Real GDP) कहा जाता है।
- सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिये आधार वर्ष की नई शृंखला 2011-12 अपनाई गई है। इसके पूर्व में यह 2004-05 थी।

राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ

उत्पादन विधि

इसमें अर्थव्यवस्था की उत्पादक इकाइयों के उत्पादन का कुल योग शामिल होता है।

- इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना वाले वर्ष में हुए उत्पादन के योग को ही शामिल किया जाता है।

आय विधि

- इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों द्वारा उत्पादन के परिणामस्वरूप प्राप्त आय के योग से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें चार साधन आय जोड़े जाते हैं-
- कर्मचारियों की क्षतिपूरक आय जिसमें मज़दूरी तथा वेतन, नियोक्ता द्वारा सामाजिक अंशदान का मूल्य शामिल होता है।
- लगान तथा रायल्टी, ब्याज तथा लाभ।

व्यय विधि *(Expenditure Method)*

- बाज़ार मूल्य पर जीडीपी (GDP_{mp}) को देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के ऊपर किये गए कुल व्यय के रूप में भी देखा जा सकता है। इन व्ययों में शामिल हैं-
- निजी अन्तिम उपभोग व्यय (C)
- सरकारी अन्तिम उपभोग व्यय (G)

राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किये जाने वाले मद

- आय गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएँ तथा सेवाएँ।
- गणना वर्ष में उत्पादित परंतु उस वर्ष का न बिका हुआ स्टॉक।
- सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएँ।
- विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय।
- सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गई नि:शुल्क सेवाएँ।
- लाभांश।
- भविष्य निधि कोष में लोगों का अंशदान।
- स्वयं उपभोग के लिये किया गया उत्पादन।
- ब्रोकर्स कमीशन (क्योंकि यह एक उत्पादक सेवा है।)
- विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की आय।

राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किये जाने वाले मद

- शेयर तथा डिबेन्चर्स चाहे ये उसी वर्ष ही निर्गत क्यों न किये गए हों।
- पूंजीगत लाभ या हानि तथा अप्रत्याशित लाभ।
- कोई भी मध्यवर्ती भुगतान शामिल नहीं होते, जैसे- फैक्ट्री का बिजली खर्च, होटल द्वारा खरीदी गई सब्जियाँ आदि।
- किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अवकाश में किया गया गृह कार्य, जैसे- फल, सब्जी उत्पादन आदि।
- किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमत में वृद्धि, विदेशों में प्राप्त उपहार।

- विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय संबंधी आँकड़ों क तैयार तथा प्रकाशित करने का कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है लेकिन रिज़र्व बैंक अपने विश्लेषण में CSO के आँकड़ों का ही प्रयोग करता है।

राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित कुछ तथ्य

- राष्ट्रीय आय संबंधी आँकड़े CSO द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है।
- प्रथम बार राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 ई. में किया था।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) की स्थापना 1971 ई. में की गई।
- भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आँकड़े CSO द्वारा तैयार किये जाते हैं।

सकल घरेलू बचत

- घरेलू बचत, सरकारी बचत एवं निगम बचत के योग को सकल घरेलू बचत कहा जाता है।
- देश के गृह क्षेत्र द्वारा की गई कुल बचत को घरेलू बचत कहा जाता है।
- देश की सरकार द्वारा की गई कुल बचत को सरकारी बचत कहा जाता है।
- देश के सार्वजनिक निगमों एवं निजी निगमों की कुल बचत को निगम बचत कहा जाता है।
- 1950-51 में यहाँ सकल घरेलू बचत 8.9 प्रतिशत थी वहीं 2013-14 में यह 30.6 प्रतिशत थी।

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

आधार वर्ष में बदलाव —

CSO ने आर्थिक विकास दर की गणना के लिए 2011-12 के नए आधार वर्ष के साथ राष्ट्रीय खातों की एक नई श्रृंखला जारी की है। जनवरी 2010 में आधार वर्ष 2004-05 के रूप में तय किया गया था।

इससे विश्लेषण के लिए आंकड़ों की समझ सरल होगी और इससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समरूप तुलना करने में भी आसानी होगी।

→ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी CSO जारी करता है, आधार वर्ष 2004-05.

ECONOMIC SURVEY —

- Draft Economic Affair द्वारा
- Input – CSO द्वारा
- अंतिम रिपोर्ट — वित्त सचिव + FM

9891401745

CONTACT ME FOR ANY QUERY/ DOUBT AND GUIDANCE RELATED TO THIS NOTES AND UPSC STUDY

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

राजकोषीय नीति

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERTS-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

1 फरवरी को

बजट

→ संविधान का अनु० 112.
→ सरकार की अनुमानित आय और व्यय के वितरण.
→ तैयार करता है – Department of Economic Affairs. (वित्त मंत्रालय)
→ दोनों सदनों में पेश करने हेतु 'राष्ट्रपति' उत्तरदायी है।

→ राज्य [redacted] बजट – अनु० - 202.

इसमें –

* आने वाले वर्ष का अनुमान
* चालू वर्ष का अनुमान
* पिछले वर्ष का वास्तविक ब्यौरा

बजट सत्र सबसे लंबा
पहला बजट – विलसन द्वारा 1860 में
लाभसराय – कैनिंग

Vote on Account

i) हर साल पेश किया जाता है।
ii) Feb. से April तक के Govt. के खर्चे पूरे करने के लिए, क्योंकि तब तक बजट पास नहीं हो पाता।
iii) सिर्फ खर्चे के लिए 1/6
iv) सामान्यतः 2 माह, अधिकतम 6 माह

Interim Budget

i) सिर्फ चुनावी साल में
ii) लोक लुभावनी घोषणाएँ नहीं की जा सकती ताकि चुनाव प्रभावित न हो।
iii) बाकि सभी प्रक्रिया सामान्य बजट जैसी
iv) Vote on A/c अंतरिम बजट ही जाता है और पास कर दिया जाता है

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

→ सरकार की आय एवं व्यय का प्रबंधन तीन खातों के माध्यम से होता है —

(अनु० - 266 और 267 बजट ढांचे का विवरण)

i) संचित निधि (CONSOLIDATED FUND) — अनु० 266(1)

↳ संपूर्ण राजस्व प्राप्तियाँ —

- राजस्व प्राप्तियाँ
- जो ऋण लिया
- दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज

→ इसमें से पैसा निकालने हेतु संसद द्वारा विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान पारित किया हो, अर्थात इसमें से धन निकालने हेतु संसद की अनुमति अनिवार्य।

→ इसी प्रकार की प्रक्रिया राज्य में भी लागू

ii) लोक लेखा खाता (PUBLIC ACCOUNT) — अनु० 266(2).

- → विनिवेश फंड
- → NDRF
- → मनरेगा फंड
- → Clean India Fund
- → राष्ट्रीय लघु बचत निधि
- → PROVIDENT FUND, POSTAL INSURANCE, MONEY ORDER etc.

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

→ यह धन सरकार के पास एक प्रकार से Bank के रूप में जमा रहता है। इसमें से पैसा निकालने हेतु संसद की अनुमति अनिवार्य नहीं।

iii) आकस्मिक निधि (CONTINGENCY FUND) — अनु० 267

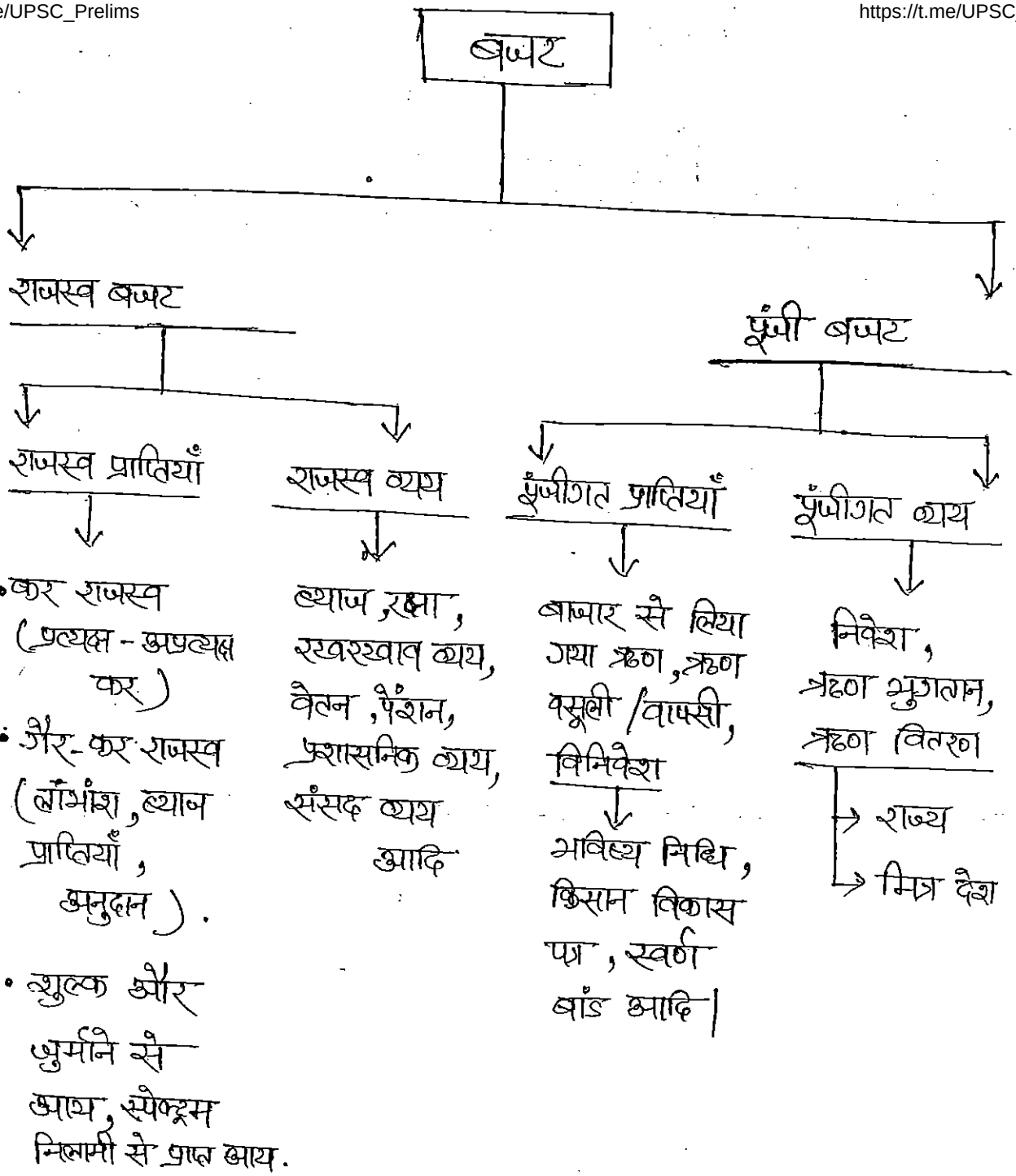
→ आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु राष्ट्रपति, राज्यपाल (क्रमशः केन्द्र एवं राज्य) की अनुमति से धन निकाला जा सकता है। बाद में संसद से अधिकृत होने पर संचित निधि से निकालकर इसमें पुनः डाल दिया जाता है।

2017 Railway budget merged with General budget

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains



Q. राजस्व प्राप्तियाँ क्या हैं?

→ वे सरकारी प्राप्तियाँ जिनकी उत्पत्ति के लिए सरकार को सार्वजनिक संपत्ति नहीं बेचनी पड़े और न ही सार्वजनिक देयताएँ बढ़ानी पड़े।

उधार लेते हैं ← जमा

Q. पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या हैं?

→ वे प्राप्तियाँ जिनकी उत्पत्ति के लिए या तो सार्वजनिक संपत्तियाँ बेचनी पड़े या सार्वजनिक देयताएँ बढ़ानी पड़े।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

सरकार के व्यय/खर्च

योजनागत व्यय (Plan Expenditure)

- केन्द्र सरकार द्वारा पंच वर्षीय, केन्द्रीय एवं राज्य की योजनाओं के लिए किया गया व्यय।
- ये उत्पादक प्रकृति के व्यय है।

गैर-योजनागत व्यय (Non-plan Expenditure)

- ब्याज अदायगी, सब्सीडी, रक्षा व्यय, वेतन, पेंशन आदि।

- राजस्व व्यय > पूंजीगत व्य
- गैर-योजनागत व्यय > योजनागत व्यय

* सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों पर सरकार ने व्यय के इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया है।

विकासात्मक व्यय –

बाँध, पुल, कारखाने, रेलवे, सड़क आदि।

गैर-विकासात्मक व्यय –

वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, रक्षा व्यय आदि।

* **योजनागत खर्च का कार्य**
  - पहले देखता था —— योजना आयोग [पुर्नसंरचना – नीति आयोग]
  - अब देखता है —— नीति आयोग नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

सरकारी घाटे

i) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) —

↓

कुल व्यय — कुल प्राप्तियाँ (ऋण ग्रहण को छोड़कर)

↓ ↓

(राजस्व + पूंजीगत) (राजस्व + पूंजीगत)

ii) राजस्व घाटा (Revenue Deficit) —

↓

राजस्व व्यय — राजस्व प्राप्तियाँ

iii) पूंजीगत घाटा (Capital Deficit) —

↓

पूंजीगत खर्च — पूंजीगत प्राप्तियाँ

iv) बजट घाटा —

कुल खर्चे — कुल प्राप्तियाँ (बाजार से उधार और अन्य देयताओं को भी सम्मिलित किया गया है।).

→ बजट घाटे को पूरा करना —

i) RBI से उधार लेकर

ii) RBI के पास पड़ा हुआ Cash Balance कम करना।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

V) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) —

↓

राजकोषीय घाटा — ब्याज भुगतान

→ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घाटे को मापने हेतु लोकप्रिय होता जा रहा है।



* भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा 1 April 1997 से लागू की गई ——— चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर।

बजट घाटे की अवधारणा की तुलना में राजकोषीय घाटे की अवधारणा बजट निर्माण प्रक्रिया में भारत में पारदर्शिता एवं जवाबदेही उत्पन्न कर रही है।

* घाटे को पूरा करना :—

→ ऋण = • विदेशी
• आंतरिक

→ विदेशी सहायता

→ नई मुद्रा छापकर

→ कर बढ़ाकर

→ सुशासन द्वारा

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

राजकोषीय घाटा कम होने/करने के कारण/प्रयास

i) केन्द्रीय योजनाओं की संख्या कम की गई है।

ii) पेट्रोल - डीजल मूल्य नियंत्रण मुक्त

iii) कच्चा तेल सस्ता हुआ है

iv) LPG, केरोसीन की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी आने से सरकार की ~~सब्सिडी~~ सब्सिडी की राशि कम हुई है।

v) DBT. for LPG + JAM

Direct Benefit Transfer

जन-धन आधार मोबाइल

कुल सब्सिडी २.5 लाख करोड़

i) खाद्य > ii) उर्वरक > iii) पेट्रोलियम

व्यय प्रबंधन आयोग (EMC) — सितंबर -2014

इसका उद्देश्य सरकार को व्यय सुधार में जानकारी देने के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को कम करने और उचित प्रबंध के संबंध में सुझाव देना है।

→ वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का बजट डिविजन ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता है।

लोक ऋण *(Public Debt)*

- सरकार के ऊपर जितना भी ऋण होता है, उसे लोक ऋण कहते हैं। ऐसी प्राप्तियाँ जो लोक ऋण को प्रभावित करती हैं, वे 'द्वितीयक प्राप्तियाँ' कहलाती हैं जो प्राप्तियाँ लोक ऋण को प्रभावित नहीं करतीं, उन्हें प्राथमिक

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Q. ऊँचे राजकोषीय घाटे के दुष्परिणाम

i) ब्याज दर बढ़ेगी
तो; नियोजित निजी निवेश कम होगा
↓
LPG वाली अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है।

ii) कल्याण पर नकारात्मक असर पड़ेगा
क्योंकि; सरकार भविष्य में अधिक खर्च करने से बचेगी।

iii) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव बढ़ सकता है (खर्च में कटौती के लिए)

iv) बेरोज़गारी बढ़ सकती है।

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

FRBM Act (Fiscal Responsibility & Budget Management)

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, *2003 (FRBM, Act)*

(i) संसद ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण तथा सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन के लिये 2003 में यह अधिनियम पारित किया था।

(ii) इसका प्रमुख उद्देश्य राजकोषीय एवं राजस्व घाटे को कम करने हेतु पर्याप्त कदम उठाने के लिये सरकार को प्रेरित करना था ताकि 2008 तक राजस्व घाटा समाप्त हो जाए और पर्याप्त राजस्व आधिक्य का सृजन हो सके।

(iii) केंद्र सरकार रिज़र्व बैंक से केवल उस स्थिति में उधार लेगी, जब नकद प्राप्तियों की अपेक्षा नकद व्यय अस्थाई रूप से अधिक हो।

(iv) सरकार संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण तथा मांग अनुदान के साथ समष्टि-अर्थशास्त्रीय अवसंरचना विवरण, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण तथा राजकोषीय नीति-रणनीति विवरण प्रस्तुत करेगी।

- इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये तृतीय केलकर समिति का गठन किया गया जिसने FRBM नियमावली का निर्माण करके कुछ उद्देश्य निर्धारित किये-

(i) 31 मार्च, 2008 तक राजस्व घाटे समाप्त करना और प्रतिवर्ष (2004-05 से शुरू करके) इसमें जी.डी.पी. के 0.5% के बराबर कमी करना।

(ii) 31 मार्च, 2008 तक राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. के 3% तक कम करना और इसके लिये प्रतिवर्ष (2004-05 से शुरू करके) इसे जी.डी.पी. के 0.3% तक कम करना।

(iii) वर्ष 2004-05 से जी.डी.पी. के 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देयताओं को सृजित न करना, जिसमें विदेशी ऋण भी शामिल है। साथ ही, आगामी वर्षों में इसमें जी. डी.पी. के 1 प्रतिशत तक की कमी करना।

- कर्नाटक FRBM नियमावली को लागू करने वाला पहला राज्य है।
- 2015-2016 के बजट में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को वर्ष 2017-18 तक जी.डी.पी. के 3% तक लाने की बात कही।

* अमेरिकी मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा एक Stimulus Package (3.86 लाख करोड़) के कारण FRBM Act अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।
* FRBM Act के कारण सामाजिक खर्च (शिक्षा, स्वास्थ्य) पर विपरित प्रभाव पड़ने से इसकी आलोचना की जाती है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

वित्तीय समावेशन

समस्त जनसंख्या, विशेष रूप से अल्पआय तथा कमजोर एवं निर्धन लोगों को वहनीय लागत पर पारदर्शी ढंग से साख सुविधाएँ अथवा बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।

ऐसे लोग जो बैंकिंग सेवाओं या साख सुविधाओं से वंचित होने के कारण गाँवों में साहूकारों, महाजनों आदि से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं और अंतत: ऋण जाल में फंस जाते हैं।

1. बैंकिंग – सेविंग, ATM
2. क्रेडिट – ऋण प्राप्त कर
3. निवेश – Pension Plan
4. बीमा – LIC, GI.

वित्तीय समावेशन हेतु किये गये प्रयास —

- बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- PSL
- स्वयं सहायता समूह की शुरुआत
- स्वाभिमान योजना (2011; 2000 से अधिक आबादी वाले 74,000 गाँवों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाई।).
- Zero-Balance account (2012)
- जन-धन योजना (28 अगस्त, 2014).

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

वित्तीय समावेशन के लिए अनिवार्यताएँ —

i) दूर-दराज के पिछड़े इलाकों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना।

ii) लोगों को बैंकिंग प्रणाली के लाभ से परिचित कराना ताकि अधिक से अधिक लोगों का खाता खोलने हेतु प्रेरित किया जा सकें।

iii) न्यूनतम लागत पर ऋण प्रदान करना, ताकि ऋण जाल में न फंसे।

iv) बैंकिंग प्रणाली में ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो जनसंख्या की विविधता हो।

वित्तीय साक्षरता —

इससे आशय उन शब्दों से है जिनका सामना किसी निवेशक को मुद्रा बाजार में प्रवेश करते समय करना पड़ता है। जैसे — किस प्रकार धन का निवेश, व्यवस्था या किसी की सहायता के लिये दान किया जाए आदि ज्ञान से है।

अधिकांश भारतीय मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर जैसी प्रमुख धारणाओं को नहीं समझते।

यही कारण है कि बहुत से लोग, विशेषकर निर्धन तथा महिलाएँ बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ रह जाते हैं।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

"विकास वह है जो स्वतंत्रता दिलाता है।"
— प्रो॰ अमर्त्य सेन

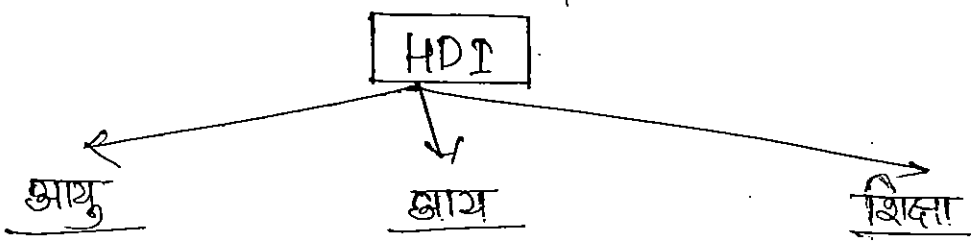
संवृद्धि (GROWTH)	विकास (DEVELOPMENT)
i) यह मात्रात्मक होती है।	i) यह गुणात्मक होती है।
ii) यह राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में होने वाले प्रसार को प्रभावित करती है।	ii) यह जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है।

कोई संदेह नहीं है, कि जीवन की अच्छी गुणवत्ता के लिए आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन वह पर्याप्त नहीं, अर्थात जीवन की अच्छी गुणवत्ता को केवल राष्ट्रीय आय द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता।

आय के साथ-साथ अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कि भी आवश्यकता होती है। विकास में इन सब आयामों को भी ध्यान में रखा जाता है।

विकास के मापक —

गुणात्मक अवधारणा होने के कारण इसे गणितीय रूप से मापा नहीं जा सकता लेकिन इसमें होने वाले परिवर्तन का पता लगाने के लिए UNDP (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) — 1965 द्वारा 1990 से एक मानव विकास सूचकांक HDI शुरू किया गया।



* सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

SUSTAINABLE DEVELOPMENT :—

→ [आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को बनाए रखना।]

इस शब्द का प्रयोग पहली बार United Nation Commission on Environment & Development द्वारा किया गया था।

इस आयोग को BRUNT LAND आयोग के नाम से भी जाना जाता है।

कुछ लोगों का मानना है कि तकनीकि का विकास करके संसाधनों की बचत की जा सकती है। लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि तकनीकि के बढ़ने से उत्पादन बढ़ती है जिससे लोगों की आय भी बढ़ती है — आय बढ़ने से लोगों का उपभोग भी बढ़ता है और इस प्रकार संसाधनों की बचत नहीं हो पाती।

CARBON CREDITS :— [इसमें 6 प्रकार की गैसों को आधार रखा गया है।].

वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यवसायिक फर्म में और विभिन्न प्रकार की अन्य संस्थाएँ, जैसे — CER (Certification Emmission Reduction) certificate प्राप्त करने का प्रयास करती है।

1 CER, 1 टन CO_2 का प्रतिनिधित्व करता है।

इसे पाने के लिए संबंधित कंपनियाँ अथवा संस्थाएँ इस प्रकार की Green Projects में निवेश करती हैं जिनसे CO_2 के स्तर को कम करने में मदद मिलती है।

वर्तमान में इनका एक बाजार विकसित हो गया है जिसमें इस प्रकार से कमाए गए Carbon Credits को बेचा जा सकता है।

इनका <u>वायदा कारोबार</u> भी चलता है।

भारत में MCX द्वारा 2008 में इस कारोबार को शुरु किया गया था।

[1 टन CO_2 Reduce हो तो संस्था को 1 CER मिलता है।].

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

HAPPY PLANET INDEX

भूयान से प्रारंभ

संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल

सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है।

खुशहाली मापने के कारक —

- आय
- स्वस्थ जीवनकाल
- सामाजिक सुरक्षा (परेशानी में कोई सहयोग मिलता है या नहीं)
- विश्वास → (सरकार और निजी कारोबार में भ्रष्टाचार को लेकर)
- आजादी (फैसले लेने की स्वतंत्रता)
- उदारता

समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तीन पहलू आवश्यक हैं

- समावेशी विकास का अर्थ है विकास की ऐसी संकल्पना जो समाज के सभी लोगों, मुख्य रूप से गरीब तथा पिछड़े लोगों को, जो विकास से वंचित हैं, को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना।
- आर्थिक विकास की ऊँची दर
- अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का समान वितरण
- वित्तीय समावेशन

भारत में 'समावेशी विकास' की अवधारणा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य रूप से चर्चा में आई। समावेशी विकास की दिशा में प्रगति हेतु निम्नलिखित उपायों पर बल देना आवश्यक है:

- रोजगार के अवसरों में वृद्धि जिससे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले तथा उनकी आय में वृद्धि हो।
- आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ जैसे- पानी, सड़क, आवास, भोजन इत्यादि तक सभी की पहुँच सुनिश्चित हो।
- कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि, जिससे इस क्षेत्र में प्रगति के अवसर बढ़ें तथा अधिक लोगों को रोजगार मिले तथा उनकी आय में वृद्धि हो।
- समाज के कमजोर वर्ग जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, निर्धन वर्ग तथा महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

→ HDI एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर भी समावेशी विकास में वृद्धि होती है।

D. K. PHOTOSTAT (M) 9268098159
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2
https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

MONEY AND BANKING

1. Bank Rate —

RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को Long term loan देने के लिए जिस ब्याज दर का प्रयोग किया जाता है उसे Bank Rate कहते हैं।

यहाँ बैंकों को Security गिरवी नहीं रखनी पड़ती।

Bank Rate एक पुनर्कटौती की दर (Rate of Re-discounting) के रूप में कार्य करती है।

Bank Rate के अंतर्गत RBI प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती करता है।

↳ Bank अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा गारंटी प्राप्त बिल

Bank Rate के प्रयोग

i) Long term loan

ii) यदि बैंक CRR, SLR नहीं जमा करवाता तो पैनल्टी इसी आधार पर लगती है।
[Bank Rate + 3% or 5%].

iii) महंगाई नियंत्रण करने में

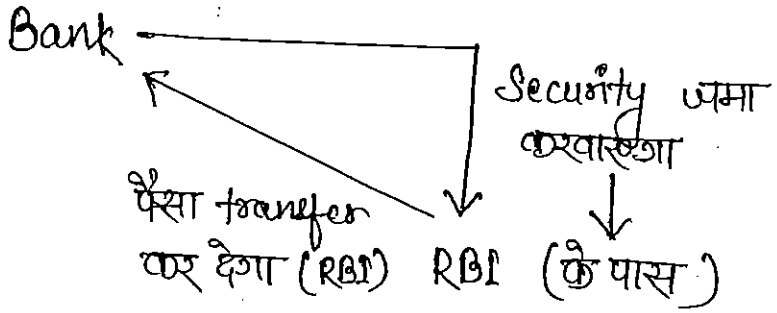
https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

2. Repo Rate —

Bank को अपने दैनिक कामकाज (1-14 दिन) के लिए, अर्थात Short Terms Loan के लिए RBI के पास Security गिरवी रखकर जो ऋण मिलता है, उस ब्याज की दर को रेपो दर कहते हैं।

मतलब RBI को जो ब्याज मिलता है = Repo Rate, इसमें Bank Security जमा करवाते समय ही बोल देता है कि मैं इतने दिन बाद Security वापस खरीद लूंगा। जैसे बैंक Security के बदले 100 करोड़ ले रहा है, बाद में वही Security 108 करोड़ में खरीद लेगा, ये 8 करोड़ (8%) इस प्रकार से Repo Rate ही है।



RRR और Repo Rate के अंतर्गत धन का लेन-देन LAF (LIQUIDITY ADJUSTMENT FACILITY) के अधीन किया जाता है (2000).

तरलता समायोजन सुविधा

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Repo Rate कम है तो —

i) RBI से बैंकों को सस्ता Loan मिलेगा

↓

ii) बैंक आगे भी लोगों को सस्ता Loan देगा

iii) इससे निवेश बढ़ेगा

- GDP बढ़ेगा
- निवेशक पैसा शेयर खरीदने में लगाएंगे

↓

फिर Sensex बढ़ेगा, जिससे रुपये (₹) की माँग बढ़ेगी — ₹

↓

iv) ₹ की माँग बढ़ने से ₹ की अधिक जरूरत पड़ेगी, फिर निवेशक डॉलर के बदले ₹ प्राप्त करेंगे।

↓

v) इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा

↓

vi) अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में भुगतान संतुलन की समस्या कम होगी।

CONTACT ME FOR ANY QUERY/DOUBT AND GUIDANCE RELATED TO THIS NOTE AND UPSC STUDY

Repo Rate बढ़ने से —

बैंकों को RBI से Loan महँगा मिलेगा — जिससे लोगों को भी Loan महँगा मिलेगा — बाजार में मुद्रा की तरलता कम हो जाएगी — जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाएगी।

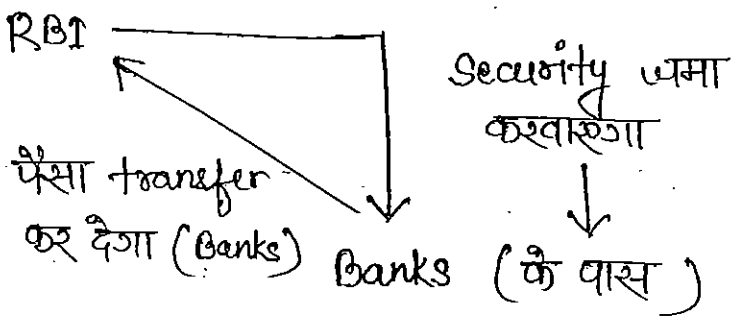
https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

3. Reverse Repo Rate —

यह Repo Rate से बिलकुल उल्टा है। इसमें Banks को अपनी जमा पर ब्याज मिलता है। यदि RBI को लगता है कि बैंकों के पास बाजार में आपूर्ति के लिए अधिक नकदी/तरलता है तो वह RRR से इसे सोखता (Absorb) है।

इसमें RBI Security को पुनः खरीदने के वादे के आधार पर बैंकों की अतिरिक्त नकदी/तरलता को जमा कर लेता है।



Reverse Repo Rate कम हो तो —

i) Bank, RBI के पास कम धन जमा करवाएँगे।
↓
ii) जिससे बाजार में तरलता अधिक रहेगी
↓
iii) Loan सस्ता होगा
↓
iv) निवेश बढ़ेगा
↓
v) GDP बढ़ेगा।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Reverse Repo Rate ऊँची हो तो —

i) Bank ज्यादा लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित होंगें। और RBI के पास ज्यादा पैसा जमा करवाएंगें

↓

ii) बाजार में तरलता कम हो जाएगी

↓

iii) मुद्रास्फीति नियंत्रण में आएगी।

यहाँ RBI, 100 करोड़ के बदले 107 करोड़ देगा। 2011 से RRR — RR से 100 Basis point मतलब 1% कम रखी जाती है।

जैसे —

RRR	RR	MSF
7%	8%	9%
(-1%)		(+1%)

2019 से यह अंतर 1% नहीं रखा जाता

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

4. MSF Rate (Marginal Standing Facility) 2011

→ इसमें RBI Overnight Lending करता है। (1 दिन-रात)

→ जब RBI से आपात स्थितियों में (सामान्य स्थिति में SLR वाली Security का प्रयोग नहीं किया जा सकता) SLR वाली Security का अधिकतम 0.75% का Loan लिया जाता है तो MSF कहलाएगा।

→ मंदी के समय Banks को तरलता प्रदान करने के लिए

MSF [सीमांत स्थायी सुविधा]	LAF
i) कम से कम 1 करोड़	i) कम से कम 5 करोड़
ii) सिर्फ अनुसूचित बैंक प्रयोग कर सकते हैं (1934 Act)	ii) सभी बैंक [सरकारी, निजी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक].
iii) ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाले बैंक	iii) NBFC भी Repo Rate पर बैंक, NBFC; सभी Loan ले सकते हैं।
iv) कर्ज लेने के लिए SLR के अंतर्गत रखी Security का प्रयोग कर सकती है।	iv) नहीं कर सकती है।

→ MSF Rate को लागू करने का लक्ष्य ⟶ Call Money Market की ब्याज दरों को नियंत्रण में रखना है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
(M) 9268098159
https://t.me/UPSC_Mains
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

5. Base Rate —

i) 2010 — दीपक मोहंती समिति

ii) बैंकों में स्वास्थ्य प्रतियोगिता को बढ़ावा देना।

iii) इसके अंतर्गत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को एक ब्याज दर की गणना करनी होती है जिसपर उन्हें कोई नुकसान न हो।

RBI के नियमानुसार कोई भी बैंक अपने BPLR (Benchmark Prime Lending Rate) को Base Rate की तुलना में नीचे नहीं रख सकता है।

6. PLR/BPLR : प्रधान ऋण दर —

जिस दर पर Bank अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को, जिसके संबंध में जोखिम शून्य हो, ऋण देने के लिए तैयार रहता है।

यह दर एक प्रकार से आधार के रूप में कार्य करती है, जिसको ध्यान में रखकर अन्य उधमियों ~~को~~ के संबंध में Bank अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है।

* 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इसे लागू किया गया।

7. Teaser Rate —

Banks द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु शुरु में निम्न ब्याज दर — भविष्य में इसे बढ़ा दिया जाता है।

↓

इस प्रक्रिया को ARM (Adjusted Rate Mechanism) कहते हैं।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

आरक्षित अनुपात

[परिवर्तनीय कोष अनुपात]

CRR (नकद आरक्षित अनुपात)

- प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यक बैंक को अपनी जमा (NDTL) राशि का एक निश्चित नकद रूप में RBI के पास जमा रखना पड़ता है।

Only Cash

SLR (वैधानिक तरलता अनुपात)

- बैंकों को कुल माँग जमा के लिए एक निश्चित नकद का अंश अपने पास बनाए रखना पड़ता है।

Cash, Gold, G-Sec.

- CRR को Bank किसी भी काम में प्रयोग नहीं कर सकते — इससे Bank को कोई लाभ नहीं होता | RBI इसपर ब्याज नहीं देता|

Profit : YES

- CRR — RBI द्वारा निर्धारित
- SLR — RBI + वित्त मंत्रालय (2007 से) ↓ का Banking विभाग लेकिन घोषणा RBI द्वारा |

*CRR, SLR पर किसी प्रकार का संसदीय नियंत्रण नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में केन्द्र सरकार RBI को दिशा-निर्देश दे सकती है तथा संसद के प्रति जवाबदेह भी है|

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

→ CRR, SLR नकद आकस्मिक अभाव से निपटने के लिए है ताकि BANK RUN से बचाया जा सके।

↳ वह स्थिति जिसमें हर आदमी Bank की आरक्षित निधि समाप्त होने से पूर्व अपना पैसा निकालना चाहता है।

→ CRR (3-15%), SLR (25-40%) की ऊपरी और निचली सीमा 2006 में समाप्त कर दी गई है।

→ SLR की इस बात को लेकर आलोचना की जाती रही है कि सरकार द्वारा इसका प्रयोग वोट वितरण के लिए करती है।

कीमत लागत अंतर —

Bank द्वारा जमाकर्ताओं को जिस दर से ब्याज दिया जाता है तथा जिस दर पर Bank अन्य लोगों को ऋण प्रदान करता है — दोनों का अंतर ही कीमत लागत अंतर है।

ब्याज दर (Interest Rate) —

Bank द्वारा जनता के जमा एवं ऋण पर प्रयोग की जाने वाली दर।

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

MPC News Update

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

जनता का पैसा

NDTL (Net Demand & Time Liabilities)

Demand Liabilities

i) Current Account
ii) Saving Account (न्यूनतम दैनिक बैलेंस)
iii) Demand Draft

- इसे हम Bank से कभी भी निकाल सकते हैं, इसमें ब्याज कम ही मिलता है, इसलिए बैंको के पास कम होता है।

Time Liabilities

i) Fixed Account
ii) Recurring Account

- इसमें निश्चित समय होता है, अधिक ब्याज मिलने के कारण लोग इसे लंबे समय तक Bank में रखते हैं, इसलिए यह बैंको के पास ज्यादा होता है।

→ NDTL के अनुसार ही CRR, SLR का प्रतिशत रखना होता है।
→ CRR और SLR के बाद Bank के पास जो पैसा बचा वही ऋण योग्य निधि है।
→ Time Liabilities में पैसा समय पर न निकाला जाए तो आगे ब्याज नहीं मिलता।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

CRAR (Capital to Risk-weighted Assets Ratio)

इसे पूंजी पर्याप्तता मानक भी कहते हैं। भारतीय बैंकों को उनकी जोखिम भारित कुल परिसंपत्तियों के एक भाग के रूप में आधार पूंजी Maintain करनी पड़ती है। भारत में यह मानक Basel – I (1992) के रूप में लागू है।

आधार पूंजी ⟶ संकट के समय इस्तेमाल पूंजी (Bank द्वारा)

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और तरलता माप के संघटक

D. K. PHOTOSTAT (M) 9268098159
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

M_0 = i) Currency in Circulation
ii) Bankers Deposit with RBI
iii) Others Deposit with RBI

Total M_0: Reserve Money

M_1 = i) जनता के पास कितना पैसा है, नोट-सिक्के (CU)
ii) DD (Current + Saving account)

M_3 = i) M_1 + Time and fixed deposit
व्यवसायिक बैंकों की निवल-आवधिक जमाएँ

अर्थात —
- जनता का पैसा
- DD + fixed and time deposit

M_2 = M_1 + Post office की Saving

M_4 = M_3 + Post office की कुल जमाएँ

M_1, M_2 को संकुचित (Narrow) मुद्रा कहते हैं
M_3, M_4 को व्यापक (Broad) मुद्रा कहते हैं।

Bill of Exchange (विनिमय पत्र) —
- ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम होती है। इसका विक्रय अंकित मूल्य से कम मूल्य पर होता है। इसमें बट्टा राशि को ही अंतर्निहित ब्याज राशि माना जाता है।

तरलता

$M_1 > M_2 > M_3 > M_4$

Money — Coins, Currency, Note, DD.

Near Money — Financial Asset, Bond, Time Deposit,

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

मुद्रा के कार्य

- विनिमय का माध्यम
- मुद्रा नाशवान नहीं है।
- सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे तरल है।
- सार्वभौमिक स्वीकार्यता है। भूमि, मकान, बॉण्ड, सोना आदि की सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं है।

Currency + नोट + बचत खाते + चालू खाते ; ये सब वैध मुद्रा है।

- Currency + नोट → कागजी मुद्रा
- बचत खाते + चालू खाते → मांग जमा मुद्रा [इन्हें किसी के द्वारा भी अस्वीकार्य किया जा सकता है इसलिए ये वैध मुद्रा नहीं है।] [चेक]

→ मुद्रा का संचलन वेग → मुद्रा की एक इकाई का अधिक बार हस्तांतरण

→ वस्तु विनिमय → मुद्रा के बिना आर्थिक विनिमय।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

MONETARY POLICY

MPC RBI द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से साख नियंत्रण के तरीके

1. Quantitative, General, Indirect
[परिमाणात्मक, सामान्य, अप्रत्यक्ष, मात्रात्मक] —

i) CRR, SLR
ii) OMO
iii) Policy Rate (Bank Rate, RR, RRR, MSF)

• ये अधिक प्रभावी है।

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

2. Qualitative, Selective, Direct
[गुणात्मक, चयनात्मक, प्रत्यक्ष] —

• इसमें केन्द्रीय बैंक लगभग सीधा हस्तक्षेप करता है।
i) PSL, Down Payment को निर्धारित करना
ii) उपभोक्ता साख नियमन (Regulation of Consumer Credit)
iii) साख राशनिंग (Rationing of Consumer Credit)
iv) प्रत्यक्ष कार्यवाही
v) सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन
vi) नैतिक दबाव
vii) डिफरेंट ब्याज दर
viii) SHG – Bank Linkage कार्यक्रम
ix) Margin Rate — जिस मात्रा तक किसी भी वित्तीय संस्था या Bank को ऋण देने से मना किया जाता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

OMO (OPEN MARKET OPERATION)

(खुले बाज़ार की क्रियाएँ)

- RBI द्वारा Govt. Security का बाज़ार में क्रय-विक्रय करना OMO कहलाता है। सरकार को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वह RBI के पास Govt. Security जमा करवाती है, जिसके बदले RBI नोट छापकर देता है। इससे RBI के पास बहुत सारी Security जमा हो जाती है। RBI यह Security दूसरे बैंकों को बेच देता है तो बैंकों के पास कम पैसा बचने से मंहगाई नियंत्रण में हो जाएगी।

- मंदी में RBI अन्य बैंकों से Security खरीदेगा तो बैंकों के पास बाज़ार में Loan देने के लिए अधिक पैसा हो जाएगा।

- OMO, Bank Rate से कहीं अधिक श्रेष्ठ है (साख नियंत्रण में) क्योंकि इसमें RBI को अन्य बैंकों के सहयोग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।

- OMO से तरलता का Repo Rate की तुलना में दीर्घकालिन समायोजन होता है।

* कैसे भी, किसी भी प्रकार से RBI के पास से पैसा जाएगा तो Money आपूर्ति बढ़ेगी।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

मुद्रास्फीति (INFLATION)

- वस्तुओं की आपूर्ति कम होने से माँग बढ़ जाती है जिससे वस्तु के मूल्य स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है ——— यह मुद्रास्फीति कहलाता है।

- मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय में असंतुलन होने के कारण मुद्रास्फीति होती है।

- दो तरह की मुद्रास्फीति —

1. मांग जनित मुद्रास्फीति (Demand Pull) —
   पूर्ति के मुकाबले वस्तु की मांग बढ़ने से।
   (भारत जैसे देश में)

2. लागत जनित मुद्रास्फीति (Cost Push) —
   उत्पादन लागत बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ना।

भारत में मुद्रास्फीति का मापन —

WPI – थोक मूल्य सूचकांक

1. → WPI का प्रयोग किया जा रहा है।
   → 676 वस्तुएँ सूचकांक में शामिल
   → आधार वर्ष 2011-12 (पहले था 2004-05).
   → सूचकांक का संकलन उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा होता है।

* भारत में मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए WPI का प्रयोग सही नहीं माना गया है, क्योंकि ——
  1) इसमें सेवाओं को नहीं जोड़ा गया है, जबकि सेवाओं

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

की भूमिका भी अर्थव्यवस्था में होती है।
[सेवाओं का थोक स्तर नहीं होता, इसलिए WPI में शामिल नहीं किया जाता।].

ii) उपभोक्ता Retail स्तर से जुड़े होते हैं जबकि WPI थोक स्तर को ध्यान में रखता है।

इसी कारण भारत में CPI का प्रयोग अधिक उचित माना गया है, क्योंकि CPI में Retail स्तर और सेवाओं का समावेश होता है।

→ RBI महंगाई दर के लिए CPI को आधार बना रहा है WPI को नहीं।

II. CPI – उपभोक्ता मूल्य सूचकांक –

- प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है।
- आधार वर्ष – 2012
- CSO यह सूचकांक जारी करता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

→ Point-to-Point विधि —

• भारत में मुद्रास्फीति निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग जैसे — आज की मुद्रास्फीति की दर देखनी है तो 1 वर्ष पूर्व की मुद्रास्फीति की दर से तुलना करनी पड़ेगी।

आधार प्रभाव —

• कभी-2 सांख्यिकीय रूप से मुद्रास्फीति की दर अनावश्यक रूप से अधिक ऊँची/कम दिखाई देती है — इसे आधार प्रभाव कहा जाता है।

• आधार प्रभाव उत्पन्न करने वाली वस्तुएँ —

खाद्य वस्तुएँ, जिनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव मानसून की स्थिति पर निर्भर करती है। (भारतीय कृषि का लगभग 60% भाग मनसून पर निर्भर)

ऊर्जा से संबंधित वस्तुएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में उतार-चढ़ाव (भारत कच्चे तेल को लेकर आयात पर निर्भर है)

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

भारत में मुद्रास्फीति के कारण —

i) मांग जनित कारक —

- लोगों की आय में वृद्धि होने से ~~सरकारी~~ (मनरेगा)
- सरकारी व्यय में वृद्धि होने से
- बैंको द्वारा लोगों को अधिक ऋण दिए जाने से
- बैंको द्वारा ब्याज दर कम करने से (निवेश और व्यय दोनों में वृद्धि)
- सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर की दर में कमी होने से लोगों के पास अतिरिक्त पैसा बचने से
- परोक्ष/अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि होने से वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि।
- सब्सिडी लिमेज

ii) लागत प्रेरित अथवा पूर्ति की कमी जनित कारक —

- आपूर्ति संकट (खाद्यानों की पूर्ति में कमी, प्राकृतिक आपदा, EL-NINO)
- आयात में कमी होने से घरेलू बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

STUDY MATERIAL ★ IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL ★ 07680981159 COURIER D.K. PHOTOSTAT FACILITY

iii) वैश्विक कारक —

- कच्चा तेल मूल्य वृद्धि
- जिस देश से हम वस्तुएँ आयात कर रहे हैं यदि उसमें मंदी आ जाए तो हमारे देश में उन वस्तुओं की कमी हो जाएगी जिससे कीमत वृद्धि पर असर पड़ेगा।

iv) अन्य महत्वपूर्ण कारक —

- MSP में वृद्धि
- आधारभूत उद्योग की आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि (Steel, Cement, कोयला, बिजली के मूल्य में वृद्धि)।

REAL INTEREST RATE = NOMINAL – महंगाई
Bank या शेयर मार्केट से हमें जो ब्याज मिल रहा है उसमें महंगाई घटाने से Real Interest Rate मिलेगा।
यदि यह Rate –ve है तो हमारी क्रय क्षमता शक्ति कम हो गई है तो फिर जनता सोना और Real estate में निवेश करती है।

मुद्रास्फीति का प्रभाव —

i) लाभान्वित वर्ग —

- ऋणी लोग इस वक्त लाभ में रहते हैं, क्योंकि अपनी कम मूल्य वाली मुद्रा को ऋणदाता को लौटाकर मुक्त हो जाते हैं। (अपस्फीति में मुद्रा महँगी होने के कारण ऋणी में रहते हैं।)
- कृषक, उत्पादक, व्यापारी वर्ग
- रोजगार में वृद्धि होती है
- परिवर्तनशील आय समूह वाले लोग
- आयात बढ़ेगा।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

ii) प्रभावित वर्ग (हानि) —

काला बाजारी भी बढ़ती है।

- ऋणदाता
- उपभोक्ता
- जिनके पास सरकारी बांड, जीवन बीमा पॉलिसी है।
- स्थिर आय वाले समूह
- बैंकों में जमा कोष वाले लोग (स्फीति की दर बैंकों से प्राप्त होने वाले ब्याज दर से अधिक होगी)
- सार्वजनिक बचत में कमी आएगी
- निर्यात घटेगा।

खाद्य मुद्रास्फीति के कारण —

i) अनियमित मानसून
ii) किसान और उपभोक्ता के बीच मध्यस्थ की मौजूदगी
iii) उपभोक्ता की आय बढ़ने से प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ की बढ़ती माँग

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय —

i) RBI द्वारा संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाकर (Bank Rate, CRR, SLR में वृद्धि करके)

ii) OMO बेचने पड़ेंगे

iii) संकुचनकारी राजकोषीय नीति का प्रयोग (कर में वृद्धि करके)

iv) सार्वजनिक व्यय में कमी करना, ताकि महंगाई न बढ़े, महंगाई बढ़ी तो ब्याजदर फिर से बढ़ानी होगी।

v) घाटे की वित्त व्यवस्था से बचना

vi) Debt Creation को स्थगित करना

vii) वस्तुओं की आपूर्ति को संतुलित करना

viii) कालाबाजारी पर रोक लगाना

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सरकारी प्रयास —

- सभी राज्यों में फल एवं सब्जियों को APMC Act से हटाकर मुक्त आवाजाही की अनुमति प्रदान की गई है।
- प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सीमा में लाया गया है।
- भारत सरकार और RBI के बीच महंगाई नियंत्रण हेतु समझौता —— स्फीति को 6% से नीचे बनाए रखना RBI के जवाबदेही होगी।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

→ Growth Rate बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ेगी।

→ बेरोजगारी की दर कम होती है तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी।

<u>जैसे</u> — रोजगार मिलने से लोगों की आय बढ़ेगी जिससे व्यय बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ेगी। दूसरी तरफ रोजगार देने वाली कंपनी की लागत वेतन के रूप में बढ़ेगी जिससे वस्तु की लागत बढ़ेगी और वस्तु महंगी हो जाएगी।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

मुद्रा अपस्फीति (DEFLATION)

- यह मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति है।
- जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में तीव्र गिरावट होती है तो उसे मुद्रा अपस्फीति या संकुचन कहा जाता है। मुद्रा के संकुचन के कारण मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय में असंतुलन उत्पन्न होता है जब मौद्रिक आय उत्पादन की मात्रा से कम होती है तथा इसके कारण मूल्य नीचे गिरने लगता है।

मुद्राअपपात (STAGFLATION)

- इसमें महंगाई के साथ-साथ बेरोजगारी भी बढ़ती है।
- इससे निपटना चुनौतीपूर्ण होता है।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में इस प्रकार की मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई थी।
- इसमें उत्पादन भी रहता है और मूल्य स्तर भी बढ़ता है।

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

GROWTH से जुड़े कुछ TERMS :—

1. SLOWDOWN —

- यह स्थिति जिसमें GDP के बढ़ने की दर (GROWTH RATE) कम होती जाती है।
- GDP कम नहीं होता GROWTH RATE कम होती है।

2. CONTRACTION —

- इसमें GDP की GROWTH RATE तिमाही में नकारात्मक हो जाती है।
- पहले की तुलना में GDP नीचे चला जाता है।

3. RECESSION —

- कम से कम दो तिमाहीयों में लगातार GDP की GROWTH RATE नकारात्मक हो।

4. DEPRESSION —

RECESSION + DEFLATION

5. STIMULUS —

अर्थव्यवस्था को RECESSION/DEPRESSION आदि, से निकालने के लिए सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक Package (पैकेज).

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

मंदी (RECESSION)

एक तरफ लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं रहती दूसरी तरफ कंपनी माल को एक हद से ज्यादा सस्ता भी नहीं कर सकती | इससे कंपनी

- या तो बंद होगी
  - ↓
  - कंपनी बंद होने से बैंको का Loan नहीं चुका पाएगी जिससे Bank NPA बढ़ेगा |
- या कुछ लोगों को नौकरी से निकालेगी
  - ↓
  - बेरोजगारी बढ़ेगी
  - ↓
  - बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा
  - ↓
  - DEMOGRAPHIC DIVIDEND नहीं प्राप्त कर सकेंगे |

* अर्थात मंदी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है |

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

मौद्रिक उपाय

महंगाई से लड़ना

- CRR, SLR बढ़ेगी
- BANK RATE बढ़ेगी
- REPO RATE बढ़ेगी
- OMO बेचने पड़ेंगें

↓

बैंको के पास कम पैसा बचेगा | बैंक कम से कम पहले जितना लाभ कमाने के लिए ब्याज दर बढ़ाएंगें |

↓

इससे LOAN महंगा होगा

↓

फिर लोग कम LOAN लेंगें | जिससे बाजार में पैसा कम होने से Demand कम होगी और इस प्रकार महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी |

- Tight Money Policy, अर्थात पैसे की आपूर्ति कम करनी पड़ेगी |
- Dear Money Policy, अर्थात महंगी ब्याज दर करनी पड़ेगी |

मंदी से बचना

- CRR, SLR कम करना
- BANK RATE कम करना
- REPO RATE कम करना
- OMO खरीदने पड़ेंगें |

↓

बैंको के पास अधिक पैसा आएगा | फिर सस्ती दर पर अधिक LOAN देंगें |

↓

फिर लोग अधिक LOAN लेंगें | बाजार में ज्यादा खरीददारी के लिए जाएंगें और बाजार मंदी से उभरने लगेगा |

- Easy Money Policy, अर्थात पैसे की आपूर्ति ज्यादा करना |
- Cheap Money Policy, अर्थात सस्ती ब्याज दर करना |

CRR की तुलना में अर्थव्यवस्था में आपूर्ति संबंधी नकदी को प्रभावित करने में RR, RRR अधिक स्वे

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

राजकोषीय उपाय —

i) सरकारी खर्च को बढ़ाना (मंदी से निपटने हेतु)

ii) सरकारी खर्च को कम करना (महंगाई से लड़ने हेतु)

iii) प्रत्यक्ष करों में कटौती करना (मंदी से निपटने में सहायक किन्तु महंगाई भी बढ़ सकती है)

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

* SLR, CRR यदि High है तो

↓

बैंकों के पास ऋण देने के लिए पैसा कम बचेगा

↓

ऋण महंगा (क्योंकि लाभ कमाना तो है ही)

↓

निवेश, नौकरी कम हो सकते हैं ← निर्यात कम हो सकता है लेकिन आयात तो होता रहेगा (कच्चा तेल)

↓

सरकार को कम कर मिलेगा

↓

चालू खाता बढ़ेगा

↓

राजकोषीय घाटा बढ़ेगा

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

बाजार संतुलन की स्थिति (मांग-पूर्ति बराबर स्तर पर हो)

कुछ वस्तुएँ एवं सेवाएँ ऐसी होती हैं कि उनमें गिरावट वांछनीय नहीं होती, इसलिए सरकार इनकी न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है, जैसे— MSP और न्यूनतम मजदूरी।

परंपरागत तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि जब सरकार करों में कटौती करती है तो घाटे का बजट बनता है। इससे उपभोक्ता कर से बचने वाली अतिरिक्त आय का व्यय करते हैं। इसकी आलोचना इसलिए की जाती है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ती है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

बैंकिंग प्रणाली का विकास

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

- 1806 Bank of Bangal
- 1840 Bank of Bombay
- 1843 Bank of Madras

इनमें शेयर थे — सरकार + जनता

इन तीनों को 1921 में मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया।

1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण करके SBI बना दिया।

→ अवध बैंक – 1881 ; सीमित देयता वाला भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक।

→ 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण — पूंजी 50 करोड़

→ 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण — पूंजी 200 करोड़

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

RBI

- RBI Act, 1934; 1 अप्रैल 1935 को स्थापना (हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर).
- स्थापना कलकत्ता में हुई थी, 1937 में बम्बई में स्थानान्तरित।
- 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण
- इसकी संरचना —

  i) भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में

  ii) केन्द्रीय निदेशक बोर्ड इसके कार्य का पर्यवेक्षण करता है

  → 1 गवर्नर और
  4 उपगवर्नर

- इसके कार्य —

  i) मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन, जो RBI के मौद्रिक विभाग द्वारा तैयार की जाती है —
  - अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखना
  - आर्थिक विकास एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखना

  ii) मुद्रा जारीकर्ता —
  - 2 ₹ से ऊपर के नोटों को जारी करता है।
  - RBI द्वारा 1957 में अपनाई गई मूलतः

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

EXIM BANK, NABARD, National Housing Bank, SIDBI का नियमन RBI द्वारा होता है।

आरक्षित मानक पद्धति (MRSS) के अनुसार RBI के पास 200 करोड़ का सोना या डॉलर रहना अनिवार्य है — इसी आधार पर वह मुद्रा जारी करने का अधिकार रखता है।

- RBI द्वारा जारी प्रत्येक नोट की अंतिम देयता सरकार की होती है बेसक भुगतान का वादा RBI करें।

→ 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपये के नोट और सिक्को के वितरण का कार्य RBI करता है।

iii) सरकार का बैंक —

- RBI सरकार के खातों का देख-रेख करता है।
- सभी मुद्रा एवं बैंक व्यवस्था संबंधी मामलों में सरकार को परामर्श देता है।
- यह राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारों को भी ऋण देता है।

इन्हीं खातों में धन प्राप्त करता है और खातों से भुगतान करता है।

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

iv) बैंकों का बैंकर एवं अंतिम ऋणदाता

v) साख का नियंत्रक

vi) बैंकिंग प्रणाली का नियामक

vii) विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन —

- 1946 में भारत को IMF की सदस्यता प्राप्त हुई। विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय - विक्रय करता है तथा देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण करता है।

- IMF में भारत का प्रतिनिधि, FEMA को Regulate करता है (1999).

viii) अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका

RBI द्वारा स्थिरीकरण -

RBI प्रायः अर्थव्यवस्था में बाहरी आघातों से मुद्रा के Stock Stabilization करने के लिए मुद्रा सृजन करने में अपने उपकरणों का प्रयोग करता है।

बाजार में मुद्रा की बढ़ी हुई पूर्ति अच्छी नहीं होती क्योंकि सेवाएँ, वस्तुएँ कम हैं तो महंगाई बढ़ेगी। RBI इसे रोकने हेतु Govt. Security बेच देगा — जिसे Called Stabilization.

उच्च शक्तिशाली मुद्रा —

RBI की देश की मौद्रिक प्राधिकरण की संपूर्ण देयता को मौद्रिक आधार या उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। इसमें — आम जनता का पैसा + व्यवसायिक बैंकों की नकदी + सरकार की RBI में रखी जमा।

बाजार स्थिरीकरण स्कीम (2004) — सरकार द्वारा अतिरिक्त तरलता प्राप्ति की दृष्टि से जारी की गई प्रतिभूति है। इन प्रतिभूतियों के विक्रय से प्राप्त राशि संचित निधि में नहीं दर्शाई जाती।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

BASEL — स्विट्जरलैंड का एक शहर जो BIS (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट) का मुख्यालय है जिसका लक्ष्य वित्तीय स्थिरता तथा बैंकिंग विनियमनों का एक समान मानक है। भारत ने Basel को स्वीकार किया है।

BANK

अनुसूचित बैंक

(RBI Act, 1934 की अनुसूची-2 में Registered).

- CRR, RBI के पास रखते हैं।

गैर-अनुसूचित बैंक

(Registered नहीं अनुसूची-2 में)

- इस प्रकार का पालन नहीं करते

वाणिज्यिक बैंक

(सरकारी, निजी, विदेशी, RRB)

i) संसद, बैंकिंग विनियमन - 1949

ii) CRR, SLR अनिवार्य

iii) PSL — हाँ

iv) उद्देश्य लाभ कमाना

v) अनेक राज्यों में शाखाएँ - हाँ

vi) कार्य —

- जमा स्वीकार्य करना, ऋण देना, बीमा की किस्त, करों की अदायगी करते हैं।

सहकारी बैंक

i) राज्य अधिनियम द्वारा

ii) CRR, SLR अनिवार्य

iii) PSL — नहीं (क्योंकि ये पहले से ही विशेष क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं)

iv) No profit no loss motive.

v) क्षेत्र निर्धारित

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंक

नाबार्ड ऋण ↓

- RBI से ऋण लेती है।
- केन्द्रीय और प्राथमिक को ऋण देती है और नियंत्रित भी करती है।

केन्द्रीय (जिला) सहकारी बैंक

- ऋण अवधि 1-9 वर्ष

प्राथमिक (ग्रामीण) सहकारी बैंक

- कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर इसे शुरू कर सकते है।
- अल्पकालिन ऋण

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Priority Sector Lending [PSL]

(प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान)

→ इसमें बैंकों को किसी विशेष क्षेत्र को न्यूनतम ऋण देना अनिवार्य है।

भारतीय बैंक / विदेशी बैंक (+20 शाखा)

i) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग — 18%.
ii) कमजोर वर्ग — 10%.
iii) शिक्षा, आवास, निर्यात ऋण
iv) लघु एवं मध्यम उद्योग
v) गैर-परम्परागत ऊर्जा
स्वास्थ्य

सभी कुल — 40%.
ब्याज दर अधिकतम — 11%.

→ यदि ये बैंक 40% ऋण क्षेत्र विशेष को नहीं देते तो वैसा Rural Infrastructure Development Fund में चला जाता है जिसे NABARD Manage करता है।
इसे राज्य सरकारें कम ब्याज पर Loan पर लेती है।

विदेशी बैंक (20 से कम शाखा वाले)

i) अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित नहीं है।
ii) अभी 32% दे रहे हैं, लेकिन 2019-20 तक 40% करना होगा।
[2016 से हर साल 2% बढ़ेगा].

→ यहाँ Small Enterprises Development Fund में चला जायेगा जिसे SIDBI Manage करता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

→ PSL लागू है —

सरकारी, नीजि, वाणिज्यक, विदेशी और RRB पर।

→ लागू नहीं है —

सहकारी एवं NBFC संस्थाओं पर।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

BANK

i) बैंकिंग Regulation से लाईसेंस

ii) RBI विनियमन करता है।

iii) पैसा जमा ले सकते है।

iv) CRR, SLR अनिवार्य

v) PSL - हाँ

vi) पूंजी - Minimum ~~5 करोड़~~ 500 करोड़

vii) शेयर बाजार में बिना घुसे पैसा नहीं लगा सकते

viii) Loan Rate, Base Rate से जुड़ा रहता है।

NBFC

i) कंपनी एक्ट, 1956

ii) इसमें अलग² क्षेत्र है लेकिन कुछ का RBI विनियमन करता है।
- IRDA - बीमा
- SEBI आदि

iii) सिर्फ Time Deposites ले सकते है Current, Saving नहीं

iv) अनिवार्य नहीं (यदि Time Deposit है तो SLR - 15%.)

v) PSL - No.

vi) पूंजी - 5 करोड़

vii) इनका तो काम यही है।

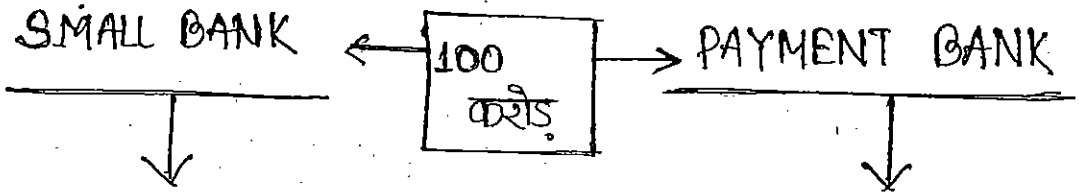
viii) जुड़ा नहीं रहता

* NBFC; Govt. Security खरीद सकती है क्योंकि Repo Rate के माध्यम से लेन ले सकती है।

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains



i) Deposit ले सकता है ।
ii) Loan देने का क्षेत्र दायरा छोटे किसान, अनौपचारिक क्षेत्र
iii) Micro finance और NBFC Convert नहीं हो सकते
iv) 25% शाखा ग्रामीण
v) NRI – हाँ
vi) सहकारी बैंक Convert नहीं
vii) PSL लागू (3 वर्ष में 40%).
viii) 50% Loan लघु-सूक्ष्म क्षेत्र को

i) Current, Saving
ii) Loan नहीं Deposit Fixed.
iii) Net Banking की सुविधा
iv) NRI-नहीं
v) पैसा Govt. Security में लगाएगा (25%)
vi) गरीब लोग कम कमीशन पर पैसा भेज सकेंगे ।
vii) क्रेडिट कार्ड नहीं ।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains Merged with SBI

महिला विकास बैंक —

Board of Directors में सभी महिलायें किन्तु Staff में पुरुष भी होंगें।

i) भारत सरकार का Bank.
ii) CRR, SLR रखना पड़ेगा
iii) Depoit → Male + female
iv) ऋण महिलाओं को
v) 25% शाखा ग्रामीण अनिवार्य नहीं
vi) लिंग विषीय असंतुलन दूर करना
vii) जमा पर पुरुष, स्त्रियों को ब्याज बराबर मिलेगा।
viii) ऋण दर, Base Rate से तय न कि भारत सरकार द्वारा

अभी [illegible]

किसान विकास पत्र - 2014 —

i) डाकघर में भी मिलेंगें।
ii) 100 माह में दुगुणा (पहले 5½ वर्ष में था; 1998 - 2011).
iii) पैसा किसान कल्याण योजनाओं में लगाया जायेगा।
iv) 1,000 से 50,000 तक खरीद सकेंगें।
v) 8 - 9 % रिटर्न
vi) ID अनिवार्य
vii) बैंक ऋण लेने में गिरवी रख सकते हैं।
viii) एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (KCC Scheme)

...ड स्कीम की शुरुआत की गई।
...ोजना का क्रियान्वयन में वाणिज्यिक बैंक,
... ग्रामीण बैंक (RRBs) तथा सहकारी
...को शामिल किया गया।
...ोजना का उद्देश्य था प्राकृतिक आपदा
...ी या कीटों द्वारा फसल खराब होने की
...ा में किसानों को वित्तीय मदद देने के
... बीमा उपलब्ध कराना।
...ड किसानों को उनकी भूमि जोत के
...र पर जारी किये जाते हैं।
...ती गई राशि का भुगतान 1 वर्ष में
होता है।
...यतः कार्ड 3 वर्ष के लिये जारी किये जाते
...ा इनकी वार्षिक समीक्षा की जाती है।
...कार्ड वितरण में वाणिज्यिक बैंकों का
45.6%, सहकारी बैंकों का 39.4%
...क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 15.1% है।

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

बैंकिंग लोकपाल – 1995 — RBI द्वारा

i) उपभोक्ता बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकता है।
ii) सभी बैंकों पर लागू, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर
iii) ऋण देने वाले NBFC
iv) 10 लाख तक के विषय सुनता है।
v) इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं निशुल्क होती है।
vi) इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा।

NABARD (राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक) —

i) नाबार्ड की स्थापना कृषि एंव ग्रामीण विकास हेतु वित उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी।
ii) सरकार — 100% Capital
iii) कृषि में उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
iv) ऋण देता है — सहकारी बैंक, RRB, NBFC, अनुसूचित बैंक।
v) राशि प्राप्त करता है — भारत सरकार, World Bank और अन्य Agencies से।
vi) Long-term Loan देता है — 10-15 वर्ष

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

MUDRA BANK [संसद के अधिनियम के तहत स्थापित].

[Micro Units Development & Refinance Agency].

भारत में Micro Finance का कार्यक्रम नाबार्ड की देख-रेख में है। 1992 में SHG – Banking Linkage programme के नाम से शुरू किया गया। इसके अंतर्गत बैंक निर्धनों द्वारा बनाए गए SHG के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करते हैं।

यह भारत का सर्वाधिक सूक्ष्म – वित्तीयन का लाभप्रिय कार्यक्रम है।

अप्रैल - 2015 में भारत सरकार द्वारा MUDRA की स्थापना की गई। भविष्य में यह संस्था Micro-finance Institutes का नियमन करेगी। वर्तमान में इसे SIDBI के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

यह उन सभी वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो Micro units को वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हैं। इस Bank से छोटे कारोबारियों, छोटी विनिर्माण इकाईयों, दुकानदारों, सब्जी विक्रेता आदि को लाभ होगा।

इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण प्रदान किये जायेंगें –

1. शिशु उद्योग – ₹ 50,000 तक
2. किशोर उद्योग – ₹ 50,000 – ₹ 5,00,000 तक
3. तरुण उद्योग – ₹ 5,00,000 – ₹ 10,00,000 तक।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) —
(1990 — लखनऊ)

i) उद्देश्य — छोटे स्तर की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना, वित्त पोषण तथा विकास करना।

ii) सरकार, निजी आदि इसके कई शेयर होल्डर हैं।

विभेदात्मक ब्याज दर
(Differental Interest Rates)

- यह स्कीम 1972 में शुरू की गई थी।
- इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने समग्र ऋण का कम-से-कम 1% अंश निर्धन व्यक्तियों को 4% ब्याज दर पर आवंटित करें।
- 1992 में गरीबों के लिये एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया जिसे स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम (Self Help Group Bank Linkage Programme) कहा गया। यह कार्यक्रम विभेदात्मक ब्याज दर वाली स्कीम के अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाने के कारण ही प्रारंभ किया गया था।

RRB (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) —
(2 October 1975)

RRB Act 1976 द्वारा मान्यता प्राप्त

i) दूर-दराज के क्षेत्रों में, जहाँ बैंकिंग सुविधा नहीं है रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना।

ii) केन्द्र सरकार — 50%, राज्य सरकार — 15% और Sponsor Bank — 35%.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण *(PFRDA)*

- पीएफआरडीए की स्थापना 2003 में की गई थी।
- इसकी स्थापना देश में पेंशन क्षेत्र को विकसित और विनियमित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनवरी 2004 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) प्रारंभ की गई थी।
- एनपीएस का लक्ष्य पेंशन सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिये बचत की आदत को बढावा देना है।

एक्जिम बैंक *(EXIM Bank)*

- एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इण्डिया (EXIM Bank) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये भारतीय आयातकों तथा निर्यातकों के संदर्भ में दिये जाने वाले वित्त के लिये प्रमुख संस्था है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी।
- एक्जिम बैंक द्वारा विदेशी निवेश में प्रोत्साहन के लिये वित्त कार्यक्रम चलाया जाता है।
- विदेशी आयातक भी भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात के लिये भुगतान शर्त सहित यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims

https://t.me/UPSC_Mains

व्हाइट लेबल ए.टी.एम. (White Label ATM)

- ऐसे ए.टी.एम. जिनके साथ किसी प्रवर्तक बैंक का नाम नहीं जुड़ा होता, व्हाइट लेबल ए.टी.एम. कहलाते हैं।
- आर.बी.आई. इस प्रकार के ए.टी.एम. को खोलने के लिये लाइसेंस देती है।
- ए.टी.एम. सुविधा के ग्रामीण क्षेत्र में प्रसार के लिये यह उपयोगी है।

NATIONAL HOUSING BANK —

i) 100% : भारत सरकार

ii) उद्देश्य – आवासिय संपत्तियों की कीमत में उतार-चढ़ाव को देखना।

iii) RESIDEX INDEX भी चलाता है।

कन्सोर्टियम ऋण (Consortium Loan)

दो या अधिक ऋणदाताओं या बैंकों में अस्थायी आपसी समझौते के आधार पर दिये गए बड़े ऋण को कन्सोर्टियम ऋण कहते हैं।

सिंडिकेट ऋण (Syndicate Loan)

दो या दो से अधिक बैंकों द्वारा आपसी स्थायी समझौते के आधार पर दिये गए ऋण को सिंडिकेट ऋण कहते हैं।

भूमि विकास बैंक —

↓

Long-term Loan.

SEBI (Security Exchange Board of India) Head office Mumbai

i) Statutory body, संसद द्वारा कानून

ii) स्थापना – 1988

iii) 1992 में SEBI Act द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया है।

iv) कार्य —

- शेयर बाजार
- Security Market को नियमित करना है
- निवेश बैंक, Merchant Bank, वेंचर बैंक को भी Regulate करता है।
- Mutual Fund के निवेश की योजनाओं को

https://t.me/UPSC_Prelims

https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है।

नियमित एवं पंजीकृत करता है।

- शेयर मार्केट को मान्यता प्राप्त करने का भी अधिकार है।
- 100 करोड़ / 50 व्यक्तियों वाले निधि, चिट फंड इसके दायरे में है।
- Red डाल सकता है, गिरफ्तार कर सकता है तथा Property attach कर सकता है।
- Fast Track Court गठित करने का अधिकार है।

v) इसके फैसले के खिलाफ अपील SAT (Securities Appellate Tribunal) में की जा सकती है।

vi) FMC (Forward Market Commission) का विलय Sept. 2015' में SEBI में कर दिया है। (FMC पहले FM के अंदर आता था)

FMC, 1958 से ही जिंस बाजार की निगरानी करता था। इस विलय के बाद बाजार में पारदर्शिता आएगी। इस विलय से अब कोमोडिटी मार्केट भी SEBI के दायरे में आ गए है।

- (सोना, चाँदी, कच्चा तेल, अनाज – गेहूँ, दलहन, तिलहन) का व्यापार होता है
- इसमें शेयर की खरीद - बिक्री नहीं होती।
- भारत में कुल ~~6~~ → 6-1=5.
- यह भविष्य में मूल्यों का निर्धारण कर किसानों को बिचौलियों की मनमानी से बचाता है।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

MCX (Multi Commodity Exchange) — Mumbai.

i) भारत का सबसे बड़ा
ii) Stock Market पर सूचीबद्ध भारत का पहला Commexes है।
2018 में राष्ट्रीय स्तर के Universal Commodity Exchange को बंद कर दिया गया है।

- IRDA विनियामक
- FDI – 26% से 49% बीमा क्षेत्र में।

→ **भारतीय बीमा उद्योग**
(Indian Insurance Industry)

बीमा उद्योग के अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं-
1. जीवन बीमा
2. सामान्य बीमा

जीवन बीमा *(Life Insurance)*
- सितंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत पाँच करोड़ रुपये की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना की गई थी।
- 1956 ई. में ही सरकार द्वारा उस समय कार्यरत सभी 246 भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में लेकर राष्ट्रीयकरण किया गया।

सामान्य बीमा *(General Insurance)*
- 1972 ई. में सरकार द्वारा साधारण बीमा निगम (General Insurance Corporation - GIC) के नाम से एक सरकारी कंपनी की स्थापना की गई।
- भारत में प्रमुख साधारण बीमा कंपनी हैं-
  - नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - मुख्यालय - कोलकाता
  - न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - मुख्यालय - मुंबई
  - ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - मुख्यालय - दिल्ली
  - यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

BANK COMMITTEE — 2013

- → अर्जित पटेल — मौद्रिक नीति
- → नचिकेत मोर — वित्तीय समावेशन
- → विमल जालान — बैंक लाइसेंस

नरसिम्हन समिति I, II
- 1990 के दशक में।
- दैन – Bank और NBFC में अंतर। इस समय 6+2 बैंकों को लाइसेंस मिला था।

बैंक लाइसेंस Banking Regulation Act - 1949 के तहत मिलता है।

- पूंजी – 500 करोड़
- 25% शाखा ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य
- Net worth – 1000 करोड़

हाल ही में बंधन और IDFC को मिला है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

NPA (Non-Performing Assets)

वर्तमान में भारत की Banking प्रणाली बढ़ते हुए NPA की समस्या का सामना कर रही है। इसके दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं —

i) बैंकों की भुगतान क्षमता कमजोर हो जाती है।
ii) नए ऋण देने के लिए संसाधन कम हो जाते हैं, इससे Growth पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

NPA, बैंकों द्वारा दिए गये वे ऋण होते हैं जिनको लेकर ब्याज अथवा किस्त भुगतान में 90 दिन से अधिक का विलंब हो जाता है। (और कृषि में NPA 2 फसलों बाद से)

इसके तीन प्रकार के वर्गीकरण हैं —

1. Substandard → एक वर्ष तक NPA
2. Doubtful → एक वर्ष से अधिक के लिए NPA
3. Lost → जिन्हें खोया मान लिया गया है।

RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बैंकों का NPA, 5% ; अर्थात 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यदि यह राशि वसूली जाती है तो सरकारी बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि, नीतिगत दरों में कटौती, निवेश में बढ़ोतरी, आधारभूत संरचना का निर्माण, कृषि को बढ़ोतरी, रोजगार, अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा विकास को गति प्रदान करना संभव हो सकेगा।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims

[पाल रोगन – यू सम्मलन
सार्वजनिक बैंको की हालत
सुधारने के लिये] .

https://t.me/UPSC_Mains

NPA बढ़ने के कारण —

i) बड़ी परियोजनाओं व सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की सफलता को सुनिश्चित करने के लिये दिया गया कर्ज।

ii) सरकारी बैंको में राजनीतिक हस्तक्षेप जबकि निजि बैंक इस प्रकार के दबाव से मुक्त रहते हैं।

iii) अंतर्राष्ट्रीय झटकों के कारण ।

iv) विकास को प्रोत्साहित करने के लिये बैंक शुरू से ही बड़े कॉर्पोरेट समूहों का साथ देते रहे हैं।

v) घोटालों और कॉर्पोरेट की मिलीभगत के चलते भी ऋण अदायगी में कोताही हुई ।

vi) मानसून की कमी के कारण कृषि NPA में वृद्धि

vii) निवेश मूल्य में बढ़ोतरी, कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, औद्योगिक मंदी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी परियोजनाओं का रुकना

https://t.me/UPSC_Prelims

https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

NPA से निपटने के उपाय

i) हाल ही में S.C ने NPA का संज्ञान लिया है और RBI से उन कंपनियों की सूची माँगी है जिनपर 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया है

ii) वित्त मंत्रालय ने बैंको को एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें बैंक अधिकारियों से भय अथवा पक्षपात के बगैर निर्णय लेने, व्यवसायिक फैसलों में बाहरी विचारों के अनदेखी करने तथा प्रोफेशनल ढंग से काम करने को कहा है।

iii) न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अनुकूल माहौल के जरूरत है।

iv) ऋण वसूली के लिये विधिक ढांचे को मजबूत करना।

v) ऋण छूट को विवेकशीलता के साथ सुनिश्चित करना।

vi) सरकार 'इंद्रधनुष' योजना लेकर आ रही है बैंको को समस्या से उभारने के लिये।

• बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंकों की एक अलग स्वामित्व कंपनी का निर्माण की दिशा में भी कार्य करेगा। इस अलग स्वामित्व वाली कंपनी के गठन का उद्देश्य बैंकों की कार्यप्रणाली को सरकारी हस्तक्षेप से दूर रखना है। साथ ही यह सरकार तथा बैंकों के मध्य एक कड़ी का कार्य करेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक सार्थक प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत इन बैंकों को कुछ मात्रात्मक लक्ष्य दिए जाएंगें तथा प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति पर अंक मिलेंगें। ये अंक उनके लक्ष्य एन.पी.ए.(गैर निष्पादनकारी अस्तियां) प्रबंधन, वित्तीय समावेशीकरण, व्यापार वृद्धि तथा ऋण का विविध क्षेत्रों में प्रसार आदि के आधार पर दिए जायेंगें। इसी क्रम में बैंक को कुछ गुणात्मक लक्ष्य भी दिए जाएंगें, जोकि मानव संसाधन तथा संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों पर आधारित होंगें।

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

CORPORATE SECTOR RESPONSIBILITY [CSR].

i) New company act - 2013 की अनुसूची - 7 में बताए गए क्षेत्रों में, कंपनी को पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2% भाग खर्च करना होगा।

5 करोड़ से ज्यादा लाभ वाली कंपनी; 500 करोड़ से अधिक विशुद्ध संपत्ति वाली कंपनी तथा 1000 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाली कंपनी इसमें शामिल है।

क्षेत्र —

- भूख एवं गरीबी
- शिक्षा
- लिंग समानता
- महिला सशक्तीकरण
- पर्यावरण
- SC / ST
- पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के लिए गठित कोष में योगदान करना शामिल है।

उपर्युक्त प्रावधान की आलोचना इसलिए की जाती है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से कंपनियों पर अनिवार्य लागू नहीं किया गया है। यदि कंपनी इसे लागू नहीं करती तो इन्हें उचित स्पष्टीकरण देना होगा।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
CONTACT ME FOR ANY QUERY / DOUBT AND GUIDANCE RELATED TO THIS NOTE AND UPSC STUDY
https://t.me/UPSC_Mains

NEW COMPANY ACT, 2013 —

- भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लेगा।
- Corporate Governance पर बल देता है।
- स्वतंत्र निदेशक को परिभाषित किया गया है। इसकी नियुक्ति से जुड़े प्रावधान स्पष्ट किये है।
- One man company की अवधारणा को लागू करता है।
- कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण को सुगम बनाया गया है।
- CSR की संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया गया है।
- निजी कंपनियों में सदस्य की संख्या 50 के जगह 200 की गई है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

वित्त बाजार

बाजार —

जहाँ किसी संशाधन के क्रेता एवं विक्रेता आपस में विनिमय कर सकें —— बाजार कहलाता है।

- **वस्तु बाजार** → वस्तुओं की खरीद-बिक्री
- **सेवा बाजार** → सेवाओं का क्रय-विक्रय

वित्त बाजार —

i) राष्ट्र के विकास में निर्णायक भूमिका
ii) बचत - निवेश को बढ़ावा देना
iii) आर्थिक संशाधनों का कुशलतम उपयोग, जिससे देश में पूंजी निर्माण, राष्ट्रीय आय, रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
iv) गरीबी से निपटने में सहायता मिलती है।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

भारतीय वित्त बाजार की संरचना

मुद्रा बाजार (MONEY MARKET)
[विनियमन RBI करता है].

i) Short-term लेन-देन
ii) एक वर्ष से कम अवधि के लिए व्यापार
iii) मुद्रा बाजार की श्रेणी

- संगठित
  - RBI
  - सरकारी नीजि बैंक
  - Treasury Bill भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा
- असंगठित
  - साहूकार
  - रिश्तेदार आदि
  - हुण्डी

[RBI के विनियमन से स्वतंत्र]

पूंजी बाजार (CAPITAL MARKET)
[SEBI द्वारा].

i) Long-term लेन-देन
ii) एक वर्ष से अधिक

- PRIMARY
  - Govt. Security
- SECONDARY
  - Registered Stock Exchange

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

मांग मुद्रा बाजार (CALL MONEY MARKET) —

- बैंको के बीच होने वाला एक दिवसिय व्यापार

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

नोटिस मुद्रा बाजार —

- 1-14 दिन बैंको के बीच होने वाला व्यापार

अंतर-बैंक अवधि मुद्रा बाजार —

- 14 दिन से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक बैंको के बीच होने वाला व्यापार

वाणिज्यक बिल —

- 3 माह के लिए व्यापारियों द्वारा एक-दूसरे को साख देने के लिए जारी किये जाते हैं

प्रगति के आरंभिक चरण में ICOR का मूल्य बढ़ता है क्योंकि इस समय कई परियोजनाएँ लंबित होती हैं।

1) बड़ी परियोजनाओं की क्रियान्वयन अवधि लंबी होती है इसलिये अल्पकाल में ICOR का मूल्य बढ़ जाता है।
2) वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का ICOR लगभग 4 है।
3) ICOR को प्रभावित करने वाले अंतर्जात कारकों में श्रम की उत्पादकता, प्रबंधन की उत्पादकता तथा पूंजी की उत्पादकता महत्त्वपूर्ण हैं तथा बहिर्जात कारकों में आधारभूत संरचना में सुधार, नीतिगत शासन में सुधार तथा वित्त क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की अच्छी स्थिति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कॉल मनी *(Call Money)*

- अगले दिन की वापसी की शर्त पर दिये जाने वाले ऋण को कॉल मनी कहते हैं।
- कॉल मनी का विनिमय प्रायः बैंकों के बीच होता है और वे आपसी सौदेबाज़ी द्वारा कॉल मनी का रेट तय करते हैं। इसे कॉल रेट कहते हैं।
- कॉल मनी के विनिमय के लिये स्थापित जगह को कॉल मनी मार्केट या इण्टर बैंक कॉल मनी मार्केट कहते हैं।
- कॉल मनी मार्केट का विश्व में सबसे बड़ा केन्द्र लंदन है, इसे लिबोर (London Inter bank offered Rate-LIBOR) कहते हैं।
- जिस ब्याज दर पर भारत में अंतर बैंक बाज़ार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंक को मांग के अनुसार धन दिया जाता है उसे मुम्बई अंतर बैंक प्रस्ताव वित्त दर (MIBOR) कहा जाता है।
- लिबोर को विश्व अर्थव्यवस्था की संदर्भ ब्याज दर भी कहा जाता है। चूँकि इसी के आधार पर बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) तय होती है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

TREASERY BILL

i) भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किये जाते है।

ii) अवधि – (1 वर्ष तक)
- 91 दिन
- 182 दिन
- 364 दिन

iii) ब्याज भुगतान की जानकारी नहीं होती है।

iv) इसे खरीदने वाले को नुकसान नहीं होता, क्योंकि वास्तविक Rate वाला Discount पर मिलता है।

v) वाणिज्यक बैंक, बीमा कंपनियाँ, Mutual Fund, FPI, NRIs आदि इन्हें खरीद सकते है।

GOVT. SECURITY

i) 1-20 वर्ष

ii) ब्याज भुगतान की जानकारी होती है।

iii) यदि Govt. Security भी Discount पर बेची जाये तो उसे ZERO COUPON BOND कहते है।

- अर्थात Treasery Bill भी Zero Coupon Bond है।
- Treasery Bill ब्याज भुगतान नहीं करता।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

MBFC [MUTUAL BENEFITS FINANCE COMPANIES]

ऐसी संस्थाएँ जो अपने सदस्यों के लिए कार्य करती है।

निधि कंपनियाँ इनमें शामिल है। दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। इसका नियमन Ministry of Corporate Affairs द्वारा किया जाता है। कार्यप्रणाली चिट फंड के समान है लेकिन बेहतर नियमन के कारण चिट फंड की तरह विवादास्पद नहीं है।

MNBC [Miscellaneous Non-Banking Companies]

इसमें चिट फंड को शामिल किया जाता है। यह समवर्ती सूची में है।

केन्द्रीय कानून (1978), राज्य कानून (1982).

हाल ही में RBI द्वारा NRIs को बिना किसी सीमा के चिट फंड में निवेश की अनुमति दी गई है।

चिट फंड में लोगों के फसने का कारण —

i) वित्तीय शिक्षा का अभाव
ii) आकर्षक प्रतिफलों का वादा एवं लालच
iii) वित्तीय समावेशन का अभाव।
iv) बैंकों द्वारा जमाओं पर अपेक्षाकृत कम प्रतिफल देना।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

→ 100 करोड़ / 50 व्यक्तियों वाले चिट फंड का नियमन SEBI करता है लेकिन विभिन्न चिट फंड स्थानीय स्तर पर कम धनराशि वाले मामले में लेन-देन करते हैं जो इसके नियमन में सबसे बड़ी कठिनाई है।

P. NOTES (PARTICIPATORY NOTES) —

काले धन पर गठित SIT, जिसके अध्यक्ष — एम॰ बी॰ शाह द्वारा SEBI को यह कहा गया कि P. Notes कालेधन से जुड़े रहते हैं।

2007 के आस-पास कुल FPI में P. Notes की भूमिका 50% थी। इसका कारण था कि FII को P. Notes के माध्यम से किये गए निवेश के बारे में जानकारी देने से छूट प्राप्त होगी [SEBI से]. हाल ही में SEBI द्वारा इस बात को जरूरी कर दिया गया है कि P. Notes के निवेशकों के बारे में उसे जानकारी देनी होगी। इससे FPI में P. Notes की भूमिका लगभग 10% रह गई है।

भारतीय बाजार में किया जाने वाला यह निवेश SEBI के पास Registered विदेशी ब्रोकर हाऊस के जरिये किया जाता है। P. Notes को विदेशी निवेशकों के लिए शेयर बाजार में सुविधाजनक एवं फायदेमंद दस्तावेज भी कहा जाता है। P. Notes का इस्तेमाल High Networth Individuals Hedge Fund एवं विदेशी संस्थानों के जरिये किया जाता है। अर्थात जो निवेशक SEBI के पास Registration कराये बिना शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं वे P. Notes का उपयोग करते हैं।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Mains

EURO ISSUES

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाज़ारों में पूंजी एकत्रित करने के लिये लाये जाने वाले ISSUES.

प्रकार

- ADR (American Depository Receipts) → अमेरिका में लाये जाते है
- GDR (Global Depository Receipts) → यूरोप में लाये जाते है

[कालेधन की जाँच के दायरे में]

विदेशी कंपनियाँ भी भारत में Euro Issues ला सकती है। इसके लिए Bharat Depository Receipts जारी करने पड़ते है [अभी लोकप्रिय नहीं हुए है]].

भारतीयों द्वारा विदेशों में निवेश के मार्ग —

1) Automatic Route — 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक।
2) ADR, GDR में
3) विशेष आर्थिक क्षेत्र।

https://t.me/UPSC_Prelims

https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

SHARE MARKET

निवेशकों के लिए तरलता बनाए रखने के लिए शेयर बाजार जरूरी है ताकि निवेशक शेयर की खरीद - बिक्री कर सकें।

शेयर विभाजित कंपनी या टुकड़ों में कंपनी

- शेयर आसानी से बेचा जा सकता है।
- दूर-दराज के लोग भी भागीदार हो सकते हैं।
- It doesn't means कि कंपनी की Value बढ़ रही है और Companies Market Compitalization हो रहा है, क्योंकि शेयर के सिर्फ टुकड़े किये हैं।

देश में कुल 21 Stock Exchange लेकिन 17 में पिछले 5 वर्षों से कोई Trading नहीं हुई है।

भारत के प्रमुख शेयर बाजार

1. फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में स्थापित (मुम्बई) (राष्ट्रीय शेयर बाजार, NSE) → Promotor - IDBI.
2. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE → एशिया का सबसे पुराना, 1875 स्थापना, 5000 से अधिक भारतीय कंपनियाँ पंजीकृत। इसका सेंसेक्स 30 अग्रणी कंपनियों का औसत होता है।
3. MCX-SX - 2013 → BSE, NSE के बाद देश में राष्ट्रीय स्तर का तीसरा Online Stock Exchange

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

[illegible] पर भागीदारी एक मिलता है और Bond पर धारक को ब्याज देने का वादा किया जाता है।

→ शेयर केवल कंपनियाँ ही जारी कर सकती हैं, न कि कोई संप्रभु संस्थान (प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद)

संप्रभु + कंपनियाँ → Bond (बॉण्ड) — प्रकार → Corporate (विकसित नहीं है)
सरकारी (विकसित)

एक पेपर का टुकड़ा होता है जिसपर कुछ Amount (100, 200, 500 आदि) लिखा रहता है। जिसमें ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक हो, सामान्यतः कंपनियाँ बॉण्ड बेचकर अपनी क्षमता का विस्तार करती हैं। समय पूरा होने पर पेपर का टुकड़ा जमा करवाने वाले को पैसा ब्याज के साथ मिल जायेगा।

बॉण्ड का दाम गिरेगा तो बॉण्ड यील्ड (Bond Yield) और Interest Rate बढ़ता जायेगा

SHORT COVERING —

शेयर कम हो जाने की स्थिति में Market से खरीदकर शेयर की Delivery देना।

सूचकांक बढ़ने के कारण — ↓
i) Soft मौद्रिक नीति
ii) FDI में रियायत

घटने के कारण — ↓
i) युद्ध, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

कंपनी अथवा अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार के कारण

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

विश्व के विभिन्न शेयर बाजार —

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

(1.) निक्की — जापान
(2.) Dow Jones — न्यूयॉर्क
(3.) शंघाई इंडेक्स — चीन
(4.) FTSE — लंदन
(5.) नैसडैक — संयुक्त राज्य अमेरिका

GREENEX —

i) BSE से संबंधित सूचकांक
ii) कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा के उपयोग में सर्वाधिक कुशलता रखने वाले Top-most 25 कंपनियों की Equity के मूल्य पर आधारित।

NIFTY —

i) NSE में सूचीबद्ध Top 50 कंपनियों का औसत।

ZERO COUPON BOND —

ये Discount पर जारी किये जाते हैं, ब्याज दर शून्य होती है, समय अवधि पूरी होने पर अंतिम मूल्य दे दिया जाता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

GREEN BOND —

इस प्रकार के बॉंडो से चुकाये गए धन का प्रयोग पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाता है।

वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक जैसी संस्थाएँ इसे प्रोत्साहित कर रही है।

हाल में भारत में इन्हें जारी करने की पहल की गई।

PERPETUAL BOND —

इनकी समयावधि कभी समाप्त नहीं होती।
इनमें Bond और Equity दोनों के गुण होते है।

भारत में इनको हाल में ही जारी करने की अनुमति दी है ताकि भारतीय बैंक पूंजीकरण के लिए इन्हें जारी कर सकें।

→ Bond and Debenture (ऋणपत्र) दोनों ऋण जुटाने के उपकरण होते है।

शेयरों का पुनर्क्रय *(Buy back of Shares)*

1. किसी कंपनी द्वारा अपने ही शेयरों को शेयरधारकों से वापस क्रय करने की प्रक्रिया को शेयरों का पुनर्क्रय कहा जाता है।
2. इससे शेयरधारकों का कंपनी के प्रति विश्वास कायम रहता है।
3. शेयरधारकों के शेयर ज्यादा मूल्य में खरीदकर पुनर्क्रय द्वारा कंपनियाँ अपने शेयरधारकों को लाभ पहुँचाती हैं।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

सट्टा
(Speculation)

भविष्य में होने वाले कीमत परिवर्तनों के अनुमानों के आधार पर वर्तमान में खरीदने अथवा बेचने के सौदे करना।

यह हमेशा अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुँचाता।

तेजड़िया (Bull)

↓

वह सट्टोरियाँ जो भविष्य में तेजी के अनुमान के कारण वर्तमान में Equity आदि को खरीदता है।

मंदड़िया (Bear)

↓

मंदी के अनुमान के कारण वर्तमान में Equity आदि को बेचता है।

Mutual Fund —

वे संस्थाएँ जो छोटे निवेशकों से बचते एकत्रित करती है तथा इनका वित्त बाजार में निवेश करती है।

इनके द्वारा कम राशि की यूनिट जारी की जाती है (5, 10, 15, 20 रुपये आदि)

इसके लाभ —

i) सुरक्षित निवेश की अधिक संभावनाएँ।

ii) अधिक प्रतिफल मिलना

iii) बाजार में तरलता आना।

iv) वित्तीय समावेशन तथा समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Hedge Funds —

कार्यप्रणाली Same Mutual Fund जैसी होती है लेकिन — Mutual Fund छोटे निवेशकों के लिए होते है जबकि Hedge Fund Net-worth individuals के लिए कार्य करते है।

Mutual Fund; Short Sale (किसी वस्तु को रखे बिना उसे बेचने का सौदा करना) नहीं कर सकते है। इसलिए ये गिरते हुए बाजार से लाभ नहीं उठा सकते लेकिन Hedge Fund ; Short Sale कर सकते है।

Hedging —

Equity आदि में निवेश अथवा व्यवसाय आदि से जुड़ी हुई जोखिमों को कम किया जाता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

कर संरचना

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

करों के अनिवार्य लक्षण —

- सरकार का विशेषाधिकार
- देश की जनता को अपनी आय में से देना ही पड़ता है। इसके बदले में सैद्धांतिक अथवा वैधानिक आधार पर राज्य द्वारा किसी वस्तु या सेवा को देना आवश्यक नहीं है।
- करों से राजस्व एकत्रित होता है
- कर आर्थिक समता लाने के लिए लगाए जाते हैं।

करापात —

यह बिन्दु जहाँ कर लगता हुआ दिखता है, जैसे — VAT का व्यापारी पर लगना।

करघात —

जिसके द्वारा भुगतान किया जाता है।

करों के प्रकार —

i) प्रत्यक्ष (Direct)
ii) अप्रत्यक्ष (Indirect)

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए कर

प्रत्यक्ष कर

ऐसा कर जिसमें कराघात और करापात दोनों एक ही बिन्दु पर हो, अर्थात जिन लोगों पर ये कर लगाए जाते हैं उसे ही चुकाना पड़ता है।

इस प्रकार के कर के भार को अन्य लोगों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

- आय कर
- निगम कर
- MAT – छोटी कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला tax जो विभिन्न प्रकार की कटौतियों का लाभ उठाकर Corporate tax देने से बच जाते हैं।

- संपत्ति कर
- उपहार कर
- ब्याज कर
- एस्टेट ड्यूटी (Estate Duty) ये अब नहीं लगते।

- Capital Gain Tax
- प्रतिभूति लेन-देन कर (राजस्व के सही को सुनिश्चित करता है)

अप्रत्यक्ष कर

करापात और कराघात दोनों अलग-अलग बिन्दुओं पर होते हैं। लगता किसी पर है चुकाता कोई और है।

चेलैया समिति की सिफारिश पर 88 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संघ सूची में शामिल इस कर की शुरुआत 1994-95 में की गई थी।

नकारात्मक सूची के दायरे में आने वाली सेवाओं पर

- सेवा कर
- सीमा शुल्क – आयातों पर लगता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा माना जाता है। WTO इसे आयात पर शुल्क कहता है। परंतु उद्योगों का संरक्षण इसका उद्देश्य होता है न कि राजस्व संग्रहण
- केन्द्रीय बिक्री शुल्क
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
- समाचार पत्र पर कर

* ये कर सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं इसलिए इनका भार निम्न वर्ग पर भी पड़ता है जिस कारण इनकी आलोचना भी होती है।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

→ राज्यों द्वारा कोई प्रमुख प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जाता। लेकिन भू-राजस्व और कृषि आय पर कर राज्यों द्वारा लगाये जाते हैं।

राज्यों के अप्रत्यक्ष कर —

- राज्य उत्पाद कर —
  - शराब के उत्पादन पर
  - दवा या प्रशाधन सामग्री जिसमें Alcohol का प्रयोग होता है।
- बिक्री कर
- प्रवेश कर —
  - वस्तुओं एवं यात्रियों के प्रवेश पर कर

VAT (VALUE ADDED TAX) —— (अप्रत्यक्ष कर)

वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन श्रृंखला तथा विक्रय की प्रक्रिया में जोड़े जाने वाले मूल्य पर लगने वाला कर। (वस्तुओं के मूल्य-वर्धन के प्रत्येक चरण पर लगता है)

भारत के ज्यादातर राज्यों में बिक्री कर की जगह VAT ने ले ली है।

केन्द्र अथवा राज्य सरकारें किसी कर को VAT में बदल सकती है।

1954 में सर्वप्रथम फ्रांस में।

2003 में हरियाणा अपनाने वाला पहला राज्य।

उपभोक्ता वर्ग पर VAT का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि पूर्ति श्रृंखला कर भार कम होने से वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं और उपभोग बढ़ता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

SPECIFIC TAX (विशिष्ट कर) —

जब ~~किसी~~ किसी वस्तु या सेवा पर कर का आकलन उसकी लंबाई, भार या आयतन के आधार पर लगाया जाता है।

PROTECTIVE TAX (संरक्षा कर) —

बाजार में किसी विशेष आर्थिक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए लगाया जाने वाला कर।

- Countervailing Duty — यह उन वस्तुओं पर अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में लगाया जाता है जिनपर उत्पादक को सरकार से सब्सिडी मिल रही है।

  इसके चलते वस्तुएँ कम कीमत पर बेचे जाने के कारण देशी उत्पादकों को नुकसान हो रहा था।

- Anti Dumping Duty — लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु या सेवा को बेचना ताकि प्रतियोगी उत्पादकों के हितों को नुकसान पहुँचे तो Dumping कहलाता है।

  इसे अपराध माना जाता है। ऐसी वस्तुओं या सेवाओं पर लगने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क को — Anti Dumping Duty कहते हैं।

Dumping के कारण

i) अति उत्पादन को खपाना
ii) निम्न गुणवत्ता वाला माल दूसरे देश के बाजार में खपाना।
iii) दूसरे देश के बाजार का अधिग्रहण करना।

जिस देश में Dumping की जाती है उस देश के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

NET TAX = GROSS TAX − (NDRF + STATE

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCE... S-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

करारोपण की विधियाँ :—

i) Progressive / प्रगामी / प्रगतिशील —

इस प्रणाली में आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ जाती है, अर्थात अमीर लोग ऊँची दर का भुगतान करें जबकि कम आय वाले लोग कम दर का भुगतान करें।

इस व्यवस्था में अधिक आय वाले लोग कर चोरी करने लगते हैं। इसको बेहतर बनाने के लिए कर चोरी रोकने संबंधी मजबूत तंत्र की आवश्यकता होती है। भारत में आयकर इसका उदाहरण है और प्रत्यक्ष करों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

विश्व में सबसे प्रचलित कराधान का तरीका। इसलिए प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं।

ii) प्रतिगामी / Regressive —

इसमें कर की दर, आय या मूल्य में वृद्धि के साथ घटती जाती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में समाहित हो जाने से ये अमीर और गरीब दोनों पर समान रूप से लगते हैं। कमजोर वर्गों पर इनका भार अधिक पड़ जाता है जबकि अमीरों पर कम। ये अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

iii) समानुपाती / Proportional —

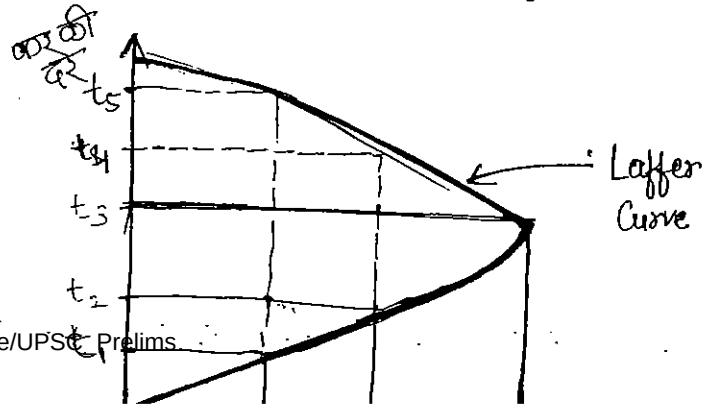
इस प्रणाली में आय में परिवर्तन के साथ कर की दर में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कर की दर एक समान होती है। यह फर्मों पर लगता है।

प्रत्यक्ष कर अर्थव्यवस्था में संसाधन आबंटन की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते जबकि अप्रत्यक्ष कर इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर के कारण वस्तुओं की कीमत बदल जाती है जिससे Public Choice भी बदल जाती है।

हम सब जानते हैं अर्थव्यवस्था में उत्पादन Public Choice को ध्यान में रखकर किया जाता है।

प्रत्यक्ष करों को लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि लोग इसकी दर चुका सकें, नहीं तो —

- कर राजस्व कम हो जाएगा (कर की ऊँची दर होने से लोगों का काम के प्रति मनोबल कम - कर चोरी करने लगेंगे।)
- GDP कम हो जाएगा



https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Laffer Curve आखिर है क्या ?

↓

यह वक्र कर से प्राप्त राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच संबंध को दिखाता है।

इसमें कर की दर एक हद से ज्यादा कम होने पर भी राजस्व में कमी आती है और एक हद से ज्यादा ऊँची होने पर कर वंचना/कर-चोरी की प्रवृत्ति बढ़ती है।

अर्थात कर की दर ऐसे Level पर होनी चाहिए कि कर की अधिकतम प्राप्ति हो सके।

→ 100% कर छूट-चंदा देने पर —

- स्वच्छ भारत कोष [F.M]
- गंगा सफाई [F.M]
- Drugs नियंत्रण [F.M]

→ अच्छी कर प्रणाली के गुण —

सरलता, निश्चितता, मितव्ययता, न्यायशीलता, अंतर-क्षेत्रीय समता और प्रशासनिक कुशलता।

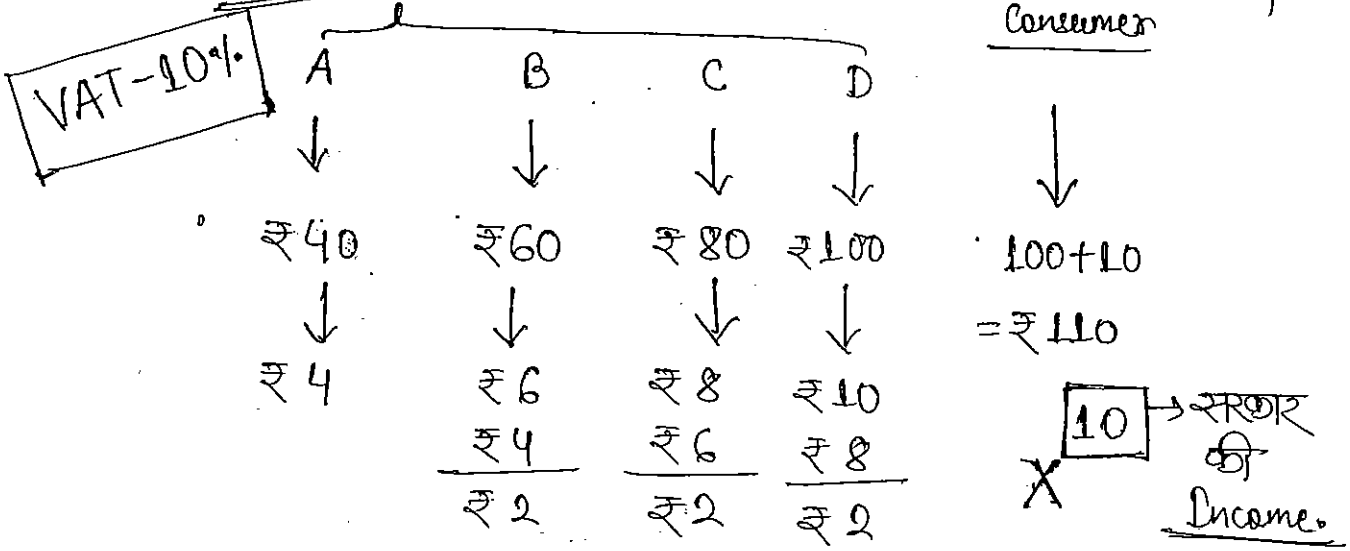
https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

VAT की कार्यप्रणाली —

VAT की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार ITC (Input Tax Credit) है, जिसमें आगतों पर लगे कर को वापस लौटा दिया जाता है।

Sellers/Manufacturers — Consumers ITC के अधिकारी नहीं होते हैं।



VAT के लाभ —

i) करो पर कर से बचाव
ii) आगतों पर कर से बचाव
iii) वस्तुओं की कीमतें कम
iv) निर्यात प्रतिस्पर्धी बनते हैं
v) पिछे के कर आगे नहीं जाते
vi) कर चोरी रुकती है।

केन्द्र और राज्य स्तर पर अभी भी कुछ अप्रत्यक्ष कर जैसे – विलासिता कर, क्रय कर आदि VAT से अलग लगाए जा रहे हैं, इनसे Cascading उत्पन्न होती है।

चुनौतियाँ —

i) कुशल एवं ईमानदार कर प्रशासन
ii) बेहतर electronic प्रणाली

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Capital Gain Tax (CGT)
पूंजीगत लाभ कर

- यह एक प्रत्यक्ष कर है
- यदि हम कोई संपत्ति लाभ पर बेचते हैं तो यह उसपर लगता है।
- मुख्यत: शेयर बाज़ार (शेयर, बांड, सोना, Real Estate) पर लगता है।
- लगता संपत्ति बेचने वाले पर है लेकिन खरीदने वाला सरकार को कर पहले से ही काटकर बेचने वाले को देता है। उदा० – किसी व्यक्ति ने 100 करोड़ की संपत्ति लाभ पर बेची, मान लेते हैं उसपर कर हुआ 20%.

जिसने संपत्ति खरीदी है
100 करोड़ → 80 करोड़ बेचने वाले को
→ 20 करोड़ कर भुगतान

भारत द्वारा दोहरे कराधान समझौते को अपनाए जाने से (Double Taxation) Tax-Haven Country मॉरिशस, हांगकांग जैसे देशों के निवेशकों द्वारा भारत के शेयर बाज़ार में प्राप्त किये गए पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगेगा। इस प्रावधान का लाभ उठाने के लिए अन्य विदेशी निवेशक मॉरिशस (DTAA) के मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

भारत में Vodafone ने इसी प्रकार का कर नहीं चुकाया था जब उसने Hutch (2007) को खरीदा था। Vodafone ने हांगकांग के माध्यम से Hutch को खरीदा था तो Vodafone ने यह तर्क दिया कि हमने Hutch को नहीं उसके मालिक को खरीदा, इसलिए CGT भुगतान नहीं करेंगें।

S.C ने भी कहा यह भारत से बाहर लागू नहीं होगा। फिर सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिये

कारण, निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए ताकि कर आतंकवाद (Tax Terrorism) को नकारा जा सके और Make in India को सफल बनाया जा सके।

EVASION

i) स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए संपत्ति कम दिखाना ताकि सरकार को कम स्टैंप ड्यूटी भुगतान करनी पड़े। (उदा०-- जमीन, मकान)

ii) ये काला धन है।

AVOIDANCE

i) ये खुलेआम होता है, लेकिन तकनीकी कमियों के माध्यम से बच निकलते हैं, जैसे Vodafone बच निकली इसी से निपटने के लिए GAAR लेकर आ रहे हैं।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims

(M) 9268098159
https://t.me/UPSC_Mains
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

GST

[वस्तु एवं सेवा कर]

वस्तु एवं सेवा कर को अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली में सबसे अहम सुधार माना जा रहा है। इसके लागू होने पर सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर एक ही कर में समाहित होंगें। इसमें VAT, सेवा कर, उत्पाद शुल्क शामिल हैं।

मार्च 2011 में 115 वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन राज्यों की असहमति से अधर में लटक गया था। वर्तमान सरकार द्वारा इस संदर्भ में 122 वाँ संविधान संशोधन बिल लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है।

इस विधेयक को पास कराने के लिये दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत और उसके बाद आधी विधानसभाओं की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी।

इसका स्वरूप —

i) Centre GST [केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, Custom Duty,].
ii) State GST. (VAT, सेल्स, मनोरंजन और प्रवेश कर)

केन्द्र और राज्य दोनों स्वतंत्र रूप से उत्पादन और विक्रय की सभी अवस्थाओं पर GST

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

वसूल कर सकेंगें |

शराब को GST से बाहर रखा गया है|

पेट्रोलियम उत्पाद, Alcohol और तंबाकू के बारे में GST परिषद निर्णय करेगी |

प्रस्तावित GST, Destination based होगा, जिसका अर्थ है कि अंतरराज्य व्यापार में जिस राज्य में उस वस्तु का उपभोग होगा SGST उसे ही प्राप्त होगा |

GST परिषद एवं इसके कार्य —

अध्यक्ष — वित्त मंत्री
सदस्य — सभी राज्यों के वित्त मंत्री या अन्य मंत्री जो राज्य का प्रतिनिधित्व करें |

केन्द्र सरकार के पास कुल मताधिकार का 1/3 भाग, राज्यों के पास 2/3 भाग होगा लेकिन सभी निर्णय मताधिकारों के 3/4 भाग से किये जायेंगें |इस स्थिति में परिषद में आम सहमति बनना या 3/4 से निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा |

कार्य

- GST की सीमा तय करना, अपवंचन के मॉडल की सिफारिश करना, संबंधित वस्तुओं को GST के अधीन करना या उनपर छूट देने के लिए सिफारिश करना, राज्यों के बीच विवादों के

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims

GST के लाभ :—

https://t.me/UPSC_Mains

दायरे से बाहर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था को यदि सही ढंग से लागू किया गया, तो कम समय में ही देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बड़ी राशि शामिल होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था 20 खरब डॉलर के आसपास पहुँच जाएगी। एक पक्ष यह भी है कि भारत की आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा आधिकारिक आकलन (गणना) से अछूता रहता है। लेकिन जीएसटी वस्तुओं एवं सेवाओं की पूरी मूल्य शृंखला का पता लगाएगा यानि उसे आधिकारिक गणना की सीमा के अंदर ले आएगा। इस दृष्टि से जीएसटी आर्थिक गतिविधियों का स्वाभाविक ट्रैकिंग उपकरण साबित होगा। इससे न केवल कर दक्षता व क्षमता बढ़ेगी बल्कि जीडीपी में भी उछाल आएगा। (1-1.5%).

बाजार में आएगी एकरूपता

जीएसटी सम्पूर्ण भारत में एक साझा बाजार निर्मित करेगा। इसका कारण यह है कि सभी राज्यों में कर की दर समान होगी जिसके कारण देश के सभी राज्यों में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्बाध प्रवाह का अवसर प्राप्त हो जाएगा। जीएसटी का सबसे सीधा-सादा पक्ष यह है कि सम्पूर्ण देश में 'एक वस्तु या एक सेवा और एक कर'। उदाहरण के तौर पर यदि आज एक व्यक्ति को कार खरीदनी हो तो उसकी कीमत दिल्ली में अलग, लखनऊ में अलग या किसी अन्य शहर में अलग होगी। यदि मार्केट मैकैनिज्म के आधार पर निष्कर्ष निकालें तो कार की मांग वहाँ अधिक होती जहाँ वह सस्ती होगी। समान मांग न होने के कारण प्रांतों को समान कर प्राप्तियाँ नहीं हो पातीं, जिससे असमान विकास की स्थिति उत्पन्न होती है। यही स्थिति चुंगी कर को लेकर होती है जिससे परिवहन को बाधा पहुँचती है। इसकी विभिन्नता के कारण वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ यात्रियों को भी गंतव्य तक पहुँचने में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय लगता है। इससे अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी पक्ष कमजोर होता है। चूँकि जीएसटी में शामिल करों का संग्रह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, इसलिए काला धन पैदा होने की संभावनाएँ कम होंगी। देश की अर्थव्यवस्था को यह सबसे बड़ा लाभ होगा।

मेक इन इंडिया में बनेगा सहयोगी

भारत में मैन्यूफैक्चरिंग को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। प्रथम, भारत के आंतरिक व्यापार में कर विषमता से आ रही दिक्कतें और द्वितीय, पूंजी की कमी। गौर से देखें तो भारत के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की तमाम कम्पनियाँ विशेषकर ऑटो पार्ट इंडस्ट्री भारत के दूसरे राज्यों को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को पार्ट का निर्यात करती है। लेकिन दुनिया जब फ्री ट्रेड की बात कर रही थी तब भारतीय राज्यों की सीमा पर टैक्स की अलग-अलग दरें कारोबार के लिए नकारात्मक वातावरण पैदा कर रही थीं। इसके कारण इन उद्योगों की घरेलू मांग कमजोर पड़ जाती है। इसके कई नुकसान होते हैं। पहला नुकसान रोजगार क्षेत्र में होता है, दूसरा, पूंजी आकर्षण कम हो जाता है जिससे उत्पादन घटता है फलतः घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयातों का मुँह ताकना पड़ता है और तीसरा नुकसान यह है कि भारतीय विनिर्माता प्रतियोगी नहीं बन पाते। ऐसे में यह जरूरी था कि भारत के अंदर समान कर व्यवस्था हो जिससे भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को प्रतियोगी बनने के लिए ऊर्जा मिल सके।

व्यावसायिक वातावरण बनेगा

जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्स भुगतान करना आसान और सुविधाजनक हो जाएगा, साथ ही इससे दो फायदे होंगे। पहला यह कि अपेक्षाकृत अधिक कारोबारी कर व्यवस्था से जुड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा, कर चोरी रुकेगी क्योंकि अब तक कारोबारी कर व्यवस्था में विद्यमान छिद्रों का लाभ उठाकर कर चोरी करने में सफल हो जाते थे। तीसरा, सरकार की आय बढ़ेगी जिससे राजस्व घाटा शून्य की स्थिति अथवा अधिशेष की स्थिति में पहुँचेगा। चौथा, बिजनेस एथिक्स एवं ट्रांसपेरेंसी में वृद्धि होगी जिससे निवेशक आकर्षित होंगे क्योंकि अब कारोबारी और निवेश कर आतंक से भय खाने या कर की गणित में उलझने के बजाय निश्चिंत होकर अपना व्यवसाय कर सकेंगे। छोटे स्थानीय व्यापारियों एवं रिटेलर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिन्हें प्रायः कर चोरी जैसे मामलों में सरकारी मशीनरी का शिकार होना पड़ता है।

जीएसटी पर केन्द्र और राज्य

वित्त मंत्री का मानना है कि जीएसटी केंद्र व राज्य दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। राज्यों को दूसरे राज्य से आने वाली वस्तुओं के प्रवेश पर शुल्क के हटने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दो वर्ष तक एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने की छूट होगी। हालाँकि जीएसटी को लेकर राज्य सरकारों में चिंता अभी तक बनी हुई है। उनका संशय टैक्स स्लैब को लेकर है और सवाल इससे होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर है। माना जा रहा है कि जीएसटी का सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके अलावा राज्य और केंद्र के बीच टैक्स बँटवारे को लेकर भी सवाल है। टैक्स बढ़ाने या घटाने संबंधी निर्णय कौन करेगा, इस पर भी चिंता है। राज्य अब तक अपनी मर्जी से कर, उपकर एवं अधिभार लगा सकते थे लेकिन अब वह छूट समाप्त हो जाएगी। राज्य न केवल इसका हल निकालना चाहते हैं बल्कि भारी-भरकम मुआवजा भी चाहते हैं। यही नहीं राज्य पेट्रोलियम और एंट्री टैक्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की मांग भी कर रहे हैं। हालाँकि केन्द्र सरकार ने इसे मानने से इन्कार कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार इस नुकसान की भरपाई के लिए राजी हो गई है। बिल में प्रावधान किया गया है कि पहले तीन साल तक केंद्र पूरे नुकसान की भरपाई करेगा। चौथे साल नुकसान के 75 प्रतिशत तो पाँचवें वर्ष में इसके 50 प्रतिशत का भुगतान केंद्र द्वारा किया जाएगा। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों को शराब पर लगाए जाने वाले टैक्स को सरेंडर करना भी कतई मंजूर नहीं है। इस मद में राज्य सरकारें सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं और कई राज्यों की तो अर्थव्यवस्था ही इस टैक्स की मद से होने वाली आय से चलती है। केंद्र सरकार ने इसीलिए जीएसटी से शराब को बाहर रखने का फैसला किया है अर्थात् शराब पर राज्य सरकारें पहले की तरह टैक्स वसूलती रहेंगी।

उपभोक्ताओं को होगा फायदा

जीएसटी का सबसे ज्यादा लाभ आम उपभोक्ता को होने की संभावना अधिक है। इसका एक कारण तो यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद कोई भी वस्तु पूरे देश में एक ही मूल्य पर उपलब्ध होगी, इसलिए उसमें यह प्रवृत्ति विद्यमान नहीं रह जाएगी कि कोई वस्तु किस राज्य में सस्ती मिलती है या महंगी। चूँकि मैन्यूफैक्चरिंग के स्तर पर भी सारा टैक्स वसूल लिया जाएगा तो उसके बाद आपूर्तिकर्ता, दुकानदार या ग्राहक को अलग से टैक्स नहीं देना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाने पर किसी तरह का कोई चुंगी टैक्स नहीं लगेगा। परिवहन

Tax व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, Tax वसूली लागत कम होगी — जिससे सरकार के पास Tax अधिक एकत्रित होगा।

https://t.me/UPSC_Prelims

https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

कठिनाईयाँ :—

i) राज्यों को राजस्व और स्वायत्ता के नुकसान का डर

ii) संघीय वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है। राज्यों की तरफ से सबसे बड़ा विरोध पेट्रोलियम उत्पादों के शुल्क से है क्योंकि राज्यों के आय का 30% इसी से आता है।

iii) GST के Destination based होने से Manufacturing वाले राज्य यह कह रहें हैं कि Consumer state को GST से अधिक फायदा होगा।

iv) सभी राज्यों में एक कर की दर होने से पिछड़े राज्यों के लोगों पर भार बढ़ेगा।

v) GST लागू होने से अधिकतर कर अधिकार केन्द्र के पास होगें।

vi) राज्य GST की दर ऊँची रखने के लिये कह रहे हैं ताकि उन्हें पिछली कर प्रणाली जितना कर मिलता रहे, जबकि केन्द्र ऊँची दर रखने के पक्ष में नहीं है।

vii) दोनों सदनों में और आधी विधानसभाओं में पारित कराना बहुत लंबी प्रक्रिया है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

सहमति :-

i) राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये वादा किया गया है।

ii) राज्य पेट्रोलियम उत्पाद पर 3 साल तक कर वसूल सकेंगे।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

GAAR
[General Anti-Avoidance Rule]

→ इसके जरिये भारतीय, NRIs और विदेशी निवेशकों पर नजर रखी जाएगी जो किसी संधि का गलत लाभ उठाकर Tax चोरी करते हैं।

→ DTAA के तहत निवेश करने वाले निवेशक भी इसके दायरें में आएंगें। जो विदेशी निवेशक मॉरिशस जैसे देश के माध्यम से कर संबंधी DTAA की छूट का फायदा उठाते हैं।

→ भारत के बाहर भी नोटिस दिया जा सकता है।

→ DTAA वाले देशों में भी नोटिस दिया जा सकता है।

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

चुनौतियाँ —

i) आयकर विभाग के अधिकारी इसका प्रयोग निवेशक को परेशान करने हेतु कर सकते हैं।

ii) कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी

iii) निवेशकों द्वारा विरोध।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

सेस (Cess)
उपकर

i) किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही लगाया जाता है।

ii) सेवा कर पर दो तरह के उपकर लागू है लेकिन अधिभार लागू नहीं है।

iii) यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों पर लगाया जा सकता है।

iv) उपकर का उद्देश्य उसी मद में राजस्व बढ़ाने हेतु किया जाता है जहाँ से वह प्राप्त हुआ होता है। अर्थात उपकर की राशि एक निश्चित मद से जुड़ी होती है।

अधिभार (Surcharge)

i) इसके लिए यह जरूरी नहीं है।

ii) संसद सिर्फ अनु० 269, 270 से संबंधित करों पर ही अधिभार लगा सकती है।

iii) आयकर तथा कुछ अन्य करों पर सरकार ने अधिभार लगाया हुआ है।

iv) सामान्यतः अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है।

v) अधिभार से प्राप्त राजस्व भारत की संचित निधि में चला जाता है।

दोनों संसद की विधियों द्वारा आरोपित होते है। दोनों की प्राप्तियों में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता।

केन्द्रीय करों में अपने हिस्से को बढ़ाने के राज्यों के मांग का एक बड़ा आधार यह भी रहा है, क्योंकि 2012-13 में इनसे प्राप्त होने वाली आय का स्तर 12.5% रहा है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

PRODUCTION TAXES :—

- Land Revenew
- Stamp Duties
- Registration Fees
- Tax on Professions

Production Taxes/Subsidies उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं।

TAX EXPENDITURE :— [T·E] राजस्व जिसे छोड़ दिया जाय है।

विभिन्न प्रकार के करों को लगाते समय जो छूट एवं रियायतें दी जाती हैं, उनके अनुमानित मूल्य को Tax Expenditure कहते हैं।

FRBM act के अनुसार वित्त मंत्री को इस संदर्भ में संसद में एक वक्तव्य देना होता है।

T·E के कारण कर की Nominal Rate तथा Effective Rate में अंतर आ जाता है जिससे पारदर्शिता में कमी आ जाती है। भारत में यह काफी ऊँचा पाया गया है।

— सरकार ने सभी प्रकार की सेवाओं पर (सेवा कर – 14%) के अतिरिक्त 0.5% स्वच्छ भारत उपकर लागू कर दिया है। इस उपकर से आने वाले कर का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान में होगा। इसके दायरे में केवल सर्विस, C.A, Cinema, Rail, Hotel, Mobile, हवाई यात्रा महंगे हो जायेंगे।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

14 वाँ वित्त आयोग की रिपोर्ट (2015-20)

अध्यक्ष — [Y.V. Reddy].

i) अनु० - 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया।

ii) सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्षों पर इसका गठन किया जाता है।

iii) सदस्यों की नियुक्ति हेतु योग्यता एवं कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

1 अध्यक्ष + 4 सदस्य, जो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं।

iv) ~~सदस्य~~ आयोग के कार्य —

- करों के कुल प्राप्तियों का केन्द्र एवं राज्यों के बीच वितरण तथा राज्यों के हिस्से का आवंटन
- राज्यों को अनुदान की मात्रा का निर्धारण करना (अनु० - 275)
- राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर पंचायत एवं नगरपालिकाओं की संसाधन आपूर्ति हेतु राज्य संचित निधी की अभिवृद्धि हेतु उपाय सुझाना (73, 74 संविधान संशोधन लागू होने के माध्यम से यह कार्य दिया गया है)
- वित्तीय दृष्टि से हितकर कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति ने सौंपा हो।

v) रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो सलाहकारी प्रकृति की होती है जिसे मानने हेतु सरकार बाध्य नहीं लेकिन सरकार सामान्यतः इसे मान लेती है।

राष्ट्रपति रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का उल्लेख ~~संसद~~ वाला ज्ञापन संसद के दोनों सदनों में रखवाता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

vi) सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा - शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है —— संसद की अनुमति उपरांत।

➡ भारत की संघीय शासन व्यवस्था में केन्द्र - राज्यों के बीच राजकोषीय स्तर पर दो प्रकार के असंतुलन देखने को मिलते हैं ——

i) लंबवत असंतुलन (Vertical Imbalance)
ii) क्षैतिजीय असंतुलन (Horizontal Imbalance)

केन्द्र की राजकोषीय शक्ति राज्यों की तुलना में अधिक है —— लंबवत असंतुलन कहा जाता है।

वित्त आयोग दोनों प्रकार की असंतुलन दूर करने की सिफारिशें देता है।

वित्त आयोग को अपने रिपोर्ट में यह भी बताना होता है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अपनी वित्तीय संसाधनों को बढ़ाए ताकि वे पहले कि तुलना में पंचायत, नगरपालिका आदि को अधिक संसाधन उपलब्ध करा सकें।

➡ <u>मुख्य सिफारिशें</u> —

- संघीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बिना शर्त हस्तान्तरण 32% से 42% कर दी गई है। (जो अभी तक के सभी वित्त आयोग की सिफारिशों में सर्वाधिक है)।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

• क्षेत्र विशेष के लिए सिफारिश नहीं की है।

आधार —

- जनसंख्या — 27.5%. → 17.5% (1971), 10% (2011).
- क्षेत्रफल — 15%.
- वन क्षेत्र — 7.5%.
- आय अंतरण — 50%.

10% (1971), 00%.
47.5%.
Fiscal Discipline – 17.5%.
जनसंख्या – 25%.
25% (1971), 0% (2011).

→ जम्मू-कश्मीर को सेवा कर में हिस्सेदारी नहीं मिलती।

→ ग्राम-पंचायत: 90% / 10%.
नगरपालिका: 80% / 20%.

[क्रमशः मूल अनुदान एवं कार्य निष्पादन].

→ जिस राज्य का क्षेत्रफल एवं वन क्षेत्र अधिक होगा उसे उतना ही केन्द्र से अधिक हिस्सा मिलेगा (केन्द्र करों में)

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

→ आय अंतरण (Income Distance) के अंतर्गत उन राज्यों को प्राथमिकता मिली है जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम होती है। वित्त आयोग द्वारा हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति आय को Reference के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जो राज्य हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय से जितना दूर होगा उसे केन्द्रीय करों में उतना अधिक हिस्सा मिलेगा।

विश्लेषण —

→ अधिक कर हस्तांतरण से राज्यों को वित्तीयन में तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना बनाने में मदद मिलेगी।

→ यह प्रक्रिया **विशेष दर्जे वाले राज्य** व अन्य राज्यों के **भेद** को खत्म करेगी।

→ एक नया आयाम — "**सहयोगात्मक संघवाद**" — राज्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्धता से केन्द्र के साथ उनके संबंध ज्यादा बराबरी के स्तर पर होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि केन्द्र का **हस्तक्षेप कम** हो जायेगा।

15th FC की Report के साथ तुलना करके पढ़ना है

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Balance of Payment (भुगतान संतुलन)

→ एक देश के निवासियों द्वारा शेष दुनिया या अन्य देशों के निवासियों के साथ

→ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन-देन

→ केन्द्रीय बैंक द्वारा पूरा विवरण डॉलर में लिखना होता है।

जो पैसा आया = CREDIT (+)

जो पैसा गया = DEBIT (−)

As per IMF mannual "[redacted]"
"BPm6"

Balance of Trade (व्यापार संतुलन/शेष)

→ यह आयात - निर्यात का संतुलन है

→ यदि निर्यात-आयात से कम है तो व्यापार घाटा

→ निर्यात - आयात से अधिक है तो अनुकूल व्यापार संतुलन / शेष

→ आयात - निर्यात बराबर है तो व्यापार संतुलन कहा जाएगा।

भारत में व्यापार घाटा सिर्फ वस्तुओं में रहता है, सेवाओं में हम लाभ में रहते है। कुल निकाले तो व्यापार Minus (−) में रहता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Balance of Payment के प्रकार

चालू खाता (Current Account)

- दृश्य
  - इसमें आयात-निर्यात दिखाई देता है। (वस्तुओं का)
- अदृश्य
  - इसमें दिखाई नहीं देता है।
    - सर्विस – नौकरी, बीमा परिवहन, उपहार
    - Income → ब्याज, लाभांश
    - Transfer – पैसा
    - गैर सेवा कारक – Software, IT, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।

पूंजी खाता (Capital Account)

वित्तीय लेन-देन का लेखा-जोखा

- ऋण पूंजी
  - Loan, अल्प सहायता, NRI का बैंकों में जमा
- गैर-ऋण पूंजी
  - FDI (स्थिर)
  - FPI/FII (अस्थिर)
  - मुद्रा
  - Bond

Current Account घाटा –

दृश्य - अदृश्य – (Minus) में हो तो इससे रुपया कमजोर होता है (₹)

यह घाटा पूंजी खाता पूरा करता है।

भुगतान असंतुलन हो तो IMF के पास जाना पड़ता है न कि विश्व बैंक के पास।

↳ ये तो विकास के लिए Soft Loan देता है।

स्थिर – अधिक समय तक देश में रहेगा।

अस्थिर – इसे कभी भी निकाल सकते हैं।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

भुगतान शेष में असंतुलन के कारण

- आर्थिक
- राजनीतिक
- सामाजिक

तीनों ही कारणों की वजह से निवेश थम जाता है तथा FDI भी नहीं आ पाता है।

विदेशी विनिमय कोष [Foreign Exchange Reserve].

भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहते हैं।

इसमें —
- विदेशी मुद्रा (1)
- सोना (2)
- SDR (IMF) (3)
- RTP (IMF) (4)
(रिजर्व ट्रान्च पोजिसन)

↓ घटते क्रम में

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

CRF (Contingency Reserve Fund).

- BRICS सदस्यों द्वारा स्थापित कोष
- उद्देश्य — BOP संकट से निपटने हेतु ऋण प्रदान करना
- गैर-सदस्यों को भी ऋण दे सकता है।
- इसे Mini IMF की संज्ञा दी गई है।

(IMF — केवल सदस्य राष्ट्रों को ऋण देता है).

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

विनिमय दर (EXCHANGE RATE) —

दूसरे देश की मुद्रा के रूप में प्रथम देश की मुद्रा की कीमत,

जैसे — 1 डॉलर = 65 रुपये

विनिमय दर में बदलाव होने से विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार, ~~आय~~ व राष्ट्रीय आय एवं रोजगार पर प्रभाव पड़ता है।

इसके प्रकार —

i) स्थिर विनिमय दर —

- केन्द्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को प्रशासनिक निर्णय द्वारा किसी निश्चित स्तर पर स्थिर कर दिया जाता है।
- इसमें बार-बार बदलाव नहीं होने से विदेशी व्यापार आदि को स्थिर आर्थिक वातावरण मिलता है।
- इसके लिए अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होती है (चीन इसका प्रयोग करता है)

ii) लचीली विनिमय दर —

- विनिमय दर का निर्धारण बाजार में की मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है।
- प्रशासनिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

iii) प्रबंधन विनिमय दर —

- विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होता है लेकिन इसके बेहतर प्रबंधन की दिशा में प्रशासन निकाय भी कार्य करे तो प्रबंधन विनिमय दर कहते है।
- इस प्रणाली में विनिमय दर को एक दायरे में लचीला रखा जाता है, लेकिन अगर दायरा टूटे तो केन्द्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है।
- विश्व में मान्यता प्राप्त प्रणाली
- भारत में भी यह लागू है।
- RBI द्वारा विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप किये जाते रहे है। —
  - MSF दर को बढ़ाना
  - अमेरिकन डॉलर को बेचना
  - NRI से जुड़ी योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाना।
  - भारत द्वारा विदेशों में किये जाने वाले FDI (Outward FDI) की सीमा को कम करना।

→ विदेशी विनिमय बाजार — जहाँ करेन्सीयों को व्यापार होता है।

→ Tobin Tax — विदेशी मुद्राओं के लेन-देन पर लगने वाला कर।

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MAT
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

विनिमय दर में परिवर्तन —

i) विनिमय दर में वृद्धि — ⊙ जब बाजार के आधार पर विनिमय दर में वृद्धि होती है या मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। (Appreciation) (लचीली विनिमय दर).

⊙ प्रशासनिक निर्णय द्वारा की गई वृद्धि जिसे —— अधिमूल्यन कहते है। → स्थिर विनिमय प्रणाली में (अवमूल्यन के विपरीत)

ii) विनिमय दर में गिरावट — ⊙ बाजार के आधार पर विनिमय दर में गिरावट या मुद्रा के मूल्य में गिरावट (Depreciation)

⊙ प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में कटौती या मूल्य को कम करना —— अवमूल्यन कहलाता है।

Depreciation और Devaluation के प्रभाव एक समान होते है।

↓

अवमूल्यन (Devaluation)

जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा के सामने पहले की तुलना में कम कर दिया जाता है, तो —— अवमूल्यन कहा जाता है।

इसमें आंतरिक मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ बाहरी मूल्य कम कर दिया जाता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

- भारत में आजादी के बाद 4 बार ₹ का अवमूल्यन किया गया है — Sept. 1949
  June. 1966
  1 July 1991
  3 July 1991 .

⊡ अवमूल्यन से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव —

→ उद्देश्यपरक होता है
→ आयात महंगे हो जाते हैं जिससे आयात कम हो सकता है, क्योंकि लोग आयातित वस्तुओं को कम खरीदेंगे।
→ निर्यात सस्ता हो जाने से निर्यात में वृद्धि होती है तथा लाभ बढ़ता है।
→ व्यापार घाटा कम होता है जिससे व्यापार संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
→ घरेलू वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं।
→ FDI, FPI निवेश की मात्रा में वृद्धि होती है

भारत में विनिमय दर बाजार द्वारा तय होती है लेकिन RBI अपने क्रय-विक्रय (हस्तक्षेप) द्वारा बाजार में स्थिति को विनियमित रखता है ताकि एक हद से ज्यादा मुद्रा के मूल्य में असंतुलन न हो और बाजार में Volatility बनाई रखी जा सके।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

विनिमय दर निर्धारण (12th NCERT)

i) बाजार मांग व पूर्ति द्वारा (आयात-निर्यात)
ii) सट्टेबाजी (मूल्य बढ़ने की अपेक्षा से | जैसे – डॉलर का मूल्य बढ़ने की संभावना है तो डॉलर अपने पास रखेगा)
iii) ब्याज दर विभेदक (अर्थात देशों के बीच ब्याज दरों में अंतर) — ऊँची ब्याज प्राप्त करने के लिए मुद्रा का संचलन पूरे विश्व में होता है।)
iv) क्रय क्षमता सिद्धांत (दिर्घकाल).

→ सामान्यतः भारत में बैंक विनिमय दर को प्रभावित करने वाला कोई काम नहीं करता लेकिन सरकार अवमूल्यन के द्वारा विनिमय दर में परिवर्तन करती है।

प्रभावी विनिमय दर (Effective Exchange Rate) —

यह किसी राष्ट्र के मुख्य व्यापारिक साझेदार राष्ट्र की मुद्राओं का भारित औसत है।

NEER
[Nominal Effective Exchange Rate]

REER
[Real Effective Exchange Rate]

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

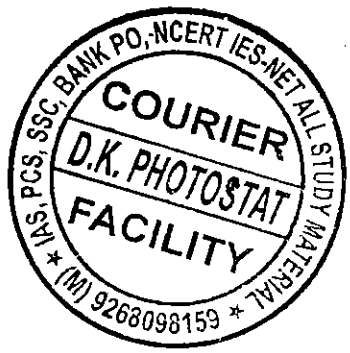
- NEER — चालू कीमतों पर देशी मुद्रा के बदले प्राप्त विदेशी मुद्रा की औसत मात्रा।
- REER — स्थिर कीमतों पर

NEER के मामले में किसी राष्ट्र एवं उसके साझेदार (व्यापारिक) राष्ट्रों के बीच में पाए जाने वाले कीमत स्तर को ध्यान में नहीं रखा जाता, जबकि REER के मामले में इन अंतरों को ध्यान नहीं रखा जाता है —— इसलिए REER को NEER की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है।

RBI अपने आंतरिक नीतिगत विश्लेषण के लिए NEER और REER का प्रयोग करता है और REER

↓

RBI (2014) द्वारा इसकी गणना के लिए CPI—New Series प्रयोग करेगा।



https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

मुद्रा की परिवर्तनीयता/परिवर्तनशीलता —

→ व्यापारीकरण से जुड़ी एक अवधारणा है।

→ इसमें मुद्राओं के प्रयोग संबंधित प्रतिबंधों में छूट दी गई है ताकि लोग भुगतान संतुलन से जुड़े लेन-देन के लिए स्वदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को स्वदेशी मुद्रा में स्वतंत्रतापूर्वक बदल सकें।

भारतीय ₹ की परिवर्तनीयता —

→ 1994 से Current A/c में ₹ को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है।

→ भारत में Full Capital A/c Convertibility नहीं है, सिर्फ Partial है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति Capital A/c में पूर्णतः परिवर्तनीयता के अनुकूल नहीं है।

→ Capital A/c में परिवर्तनीयता के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था ($\frac{1st}{1996}$, $\frac{2nd}{2006}$)

[इसमें स्वदेशी - विदेशी वित्तीय संपत्तियों को आपस में बदलने की छूट]

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

→ Current A/C परिवर्तनीयता का असर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर सकारात्मक रहा है।

Capital A/C परिवर्तनीयता को लागू करने में विभिन्न चुनौतियाँ —

i) यूरो ज़ोन का आर्थिक संकट
ii) अमेरिका की अस्पष्ट मौद्रिक नीति
iii) भारतीय बैंकों का बढ़ता NPA, और
iv) चीन की अर्थव्यवस्था।

पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लाभ

- पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता का प्राथमिक रुप से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ घरेलू परियोजनाओं में पूंजी का तीव्र गति से होने वाला प्रवाह है।
- फार्मों के लिए उधार लेने की लागत कम हो जायेगी।
- विविध प्रकार की मुद्राओं की उपलब्धता उद्योगपतियों और निवेशकों लिए लाभकारी रहेगीं।

पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के नकारात्मक प्रभाव

- बड़ी मात्रा में पूंजी के देश से बाहर निकल जाने पर अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है।
- पूंजी खाते में परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध के कारण ही सन् 2008-09 के वित्तीय संकट का भारत पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा था।

FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT [FEMA]

तारापोर समिति की सिफारिश पर

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) के स्थान पर लागू किया गया है।
- फेरा की तुलना में फेमा में कई तरह के उदारीकृत प्रावधान किये गए हैं।
- फेमा के उल्लंघनकर्ताओं को अब केवल मौद्रिक दंड का ही भुगतान करना होगा जो कि संबद्ध राशि का अधिकतम तीन गुना तक होगा।
- फेमा के तहत यदि कोई दंडित व्यक्ति अर्थदण्ड चुकाने में असफल रहता है तो उसे जेल भेजने की भी कार्रवाई की जा सकेगी। इस दशा में भी जेल में उसकी स्थिति एक सिविल अपराधी की होगी।
- फेमा के अंतर्गत दोषसिद्धि का दायित्व प्रवर्तन एजेंसी पर होगा जबकि फेरा के अंतर्गत यह दायित्व व्यक्ति पर था।

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

FDI

i) किसी कंपनी में 10% से अधिक निवेश

ii) Long-term होता है (स्थिर)

iii) निदेशक मंडल (कंपनी) में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकता है जिससे उसे नियंत्रणकारी शक्ति प्राप्त हो सकती है।

iv) विदेशी मुद्रा भंडार, तकनीकी, बेहतर ज्ञान-प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास लेकर आते हैं।

v) Govt. Security ट्रेज़री बिल में लागू नहीं है।

vi) RBI (FEMA)

vii) Foreign Investor Promotor Board (FIPB) ↓ मंजूरी देना

viii) DPIP - द्वारा नीति निर्धारण।

FPI / FII

i) 10% से कम

ii) Short-term होता है (अस्थिर)

iii) नहीं — हितों का धुड़ाव नहीं हो पाता।

iv) नहीं

v) ट्रेज़री बिल में नहीं है लेकिन Govt. Security, 30 बिलियन बांड खरीद सकते हैं।

vi) SEBI

vii) वित्त बाजारों के अंतर्गत प्रवेश करता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
https://t.me/UPSC_Mains

FDI के प्रकार

Green Field FDI

नई कंपनी की स्थापना के समय किया जाने वाला FDI

Brown Field FDI

पहले से चल रही कंपनी की 10% या इससे ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदना।

- भारत में Green Field FDI अधिक उपयोगी
- भारत में FDI से ज्यादा पैसा FPI के माध्यम से आता है।

बंद अर्थव्यवस्था – अन्य देश के साथ व्यापार बहुत ही कम

खुली अर्थव्यवस्था – अन्य देशों के साथ व्यापार हेतु खुलापन।

3000 करोड़ तक के FDI के स्थान पर 5,000 करोड़ तक के FDI की अनुमति FIPB देगी। इसके बाद प्रस्ताव पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली CCEA लेगी।

वित्त मंत्रालय के तहत वित्त सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय समूह।

49% (रक्षा) पर FIPB फैसला करेगा और इसके बाद सुरक्षा पर फैसला Cabinet Committee on Security (Head - Prime Minister) करेगा।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

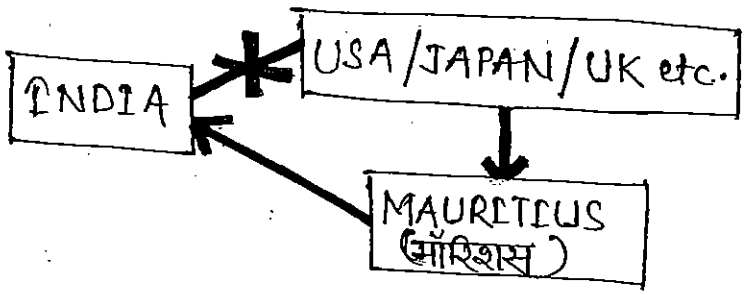
https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Round Tripping — (पुनः लौटना)

जब कोई भी विदेशी निवेशक भारत में अन्य राष्ट्रों के मार्ग से FDI करता है तो Round Tripping कहलाता है।

ऐसा मार्ग प्रदान करने वाले राष्ट्र को Tax-haven (मॉरिशस)

Round Tripping का कारण दोहरे कराधान से बचने से जुड़े समझौते का लाभ उठाना होता है।



→ भारत में उत्पन्न कालेधन को पुनः विदेशी निवेश के जरिये लौटा दिया जाये।

→ विदेशी निवेश के संदर्भ में अब OCI, PIO और NRI द्वारा किये गए निवेश को घरेलू निवेश माना जाएगा।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

भारत का FDI सेवा क्षेत्र आधारित है (सेवा क्षेत्र में FDI अधिक आता है जबकि चीन का FDI विनिर्माण क्षेत्र आधारित है। इसलिए चीन में भारत की तुलना में FDI से अधिक रोजगार पैदा होते है।

दूसरी तरफ विनिर्माण क्षेत्र का कारोबार सेवा क्षेत्र के कारोबार क्षेत्र से अधिक होता है। इसलिए चीन के विनिर्माण क्षेत्र के FDI का आकार भी भारत के FDI से अधिक है।

जिन क्षेत्रों में FDI नहीं —

- परमाणु ऊर्जा (बुनियादी सुविधाओं को छोड़कर)
- रेलवे (बुनियादी सुविधाओं को छोड़कर)
- लॉटरी, सट्टेबाजी
- चिट फंड, निधि कंपनी
- तंबाकू उत्पाद
- कृषि (बागवानी, पशुपालन को छोड़कर)
- आवास व रियल एस्टेट

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

अनुमति वाले क्षेत्र —

- रक्षा, बीमा — 49%
- सिंगल ब्रान्ड — 100%
- मल्टी ब्रान्ड (51%)

राज्य की Permission (छोटे कारोबारियों पर असर न हो)

30% सामान स्थानीय विक्रेताओं से खरीदना।

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

Current affairs में डाटा बदलता रहता है

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

भारत में निर्माण क्षेत्र में कम FDI के कारण —

i) विश्व स्तरीय आधारित संरचना की कमी
ii) श्रम सुधारों से संबंधित समस्याएँ

इसी कारण भारत प्राथमिक क्षेत्र से सीधा सेवा क्षेत्र की ओर चला गया।

भारत में FDI किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ?

i) आधारभूत संरचना का विकास
ii) श्रम सुधार को लागू करना
iii) भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को सुलझाना।
iv) विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना
v) Single Window Clearance System को लागू करना
vi) Ease of doing business में Ranking सुधारना।
vii) केन्द्र - राज्य समन्वय

विभिन्न कदम जो वैश्विक निवेश के लिए भारत को आकर्षक बना सकते हैं

1) कराधान व्यवस्था में स्थिरता। वोडाफोन, केयर्न और शैल जैसे कर विवाद फिर से न हों।
2) भारत में व्यापार करना सरल बनाना (विश्व बैंक के व्यापार करने की आसानी के सूचकांक में 189 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर है)
3) सरकार कराधान, श्रम, भूमि, कौशल विकास और बिजली क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई सुधार लायी है।
4) बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाना, प्राकृतिक संसाधनों का पारदर्शी और निष्पक्ष आवंटन करना, जल्द से जल्द जीएसटी लागू करना और बिजली वितरण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना।
- देश के अवसंरचना क्षेत्र में भारी निवेश की जरूरत है और इसके लिए विदेशी निवेश अच्छे संसाधन साबित हो सकते हैं।
5) डिजिटल भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनायें मुख्यतः उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लायी गयी हैं। इस क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, बाजार और व्यापार के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर एकीकरण की आवश्यकता होगी।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का सुदृढ़ीकरण – नवाचार और निवेश आकर्षित करने के लिए।
6) प्रस्तावित राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) निवेश

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains



https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

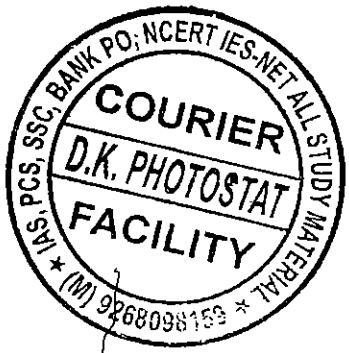
https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

भारत के लिए FDI, FPI की प्रासंगिकता —

i) FPI से भारत के वित्त बाजार में तरलता बढ़ती है।
ii) भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन में मदद मिलती है।
iii) Current a/c घाटा के वित्तीयन में मदद करता है।
iv) GDP की दर और आकार बढ़ता है।

→ निवेश निर्भर करता है —

i) ब्याज दर पर
ii) अर्थव्यवस्था की स्थिति
iii) सब्सिडी



https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

कम से कम ... संपत्ति हो।

Angel Investors ⟹ • किसी व्यवसाय को चलाने का 10 वर्ष का अनुभव हो।

SEBI द्वारा लागू की गई इस अवधारणा में ऐसे निवेशक होते हैं जो **Start-up** में निवेश करते हैं।

↓

ऐसी कंपनियाँ जो पहली बार किसी व्यवसाय को शुरू करती हैं।

अमेरिका की तरह भारत में समावेशी विकास के लिए विशेषकर तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में Start-up पर ज़ोर दिया जा रहा है।

विकसित राष्ट्रों की मौद्रिक नीति और Currency Depreciation —

हाल के वर्षों में Growth Rate को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर वाली मौद्रिक नीति का प्रयोग कर रहे हैं। इसके कारण भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर विकसित राष्ट्रों से Capital Inflow बढ़ रहे हैं।

प्रभाव

- विकसित राष्ट्रों की मुद्राओं का भारत जैसे राष्ट्रों में Depreciation हो रहा है।
  - ↓
  - विकसित राष्ट्रों के निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है।
- भारत जैसे विकासशील देशों के निर्यातों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

आयोजन के प्रकार

आयोजन क्या है?

राज्य के नेतृत्व में राष्ट्र के संसाधनों का कुशलतम एवं अनुकूलतम राष्ट्र हित में उपयोग सुनिश्चित करना ताकि विकास के माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया जा सके।

भारत में आयोजन क्यों जरूरी है?

व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, निम्न उपभोग स्तर, कौशल एवं वित्त का अभाव आदि के कारण।

आयोजन का वर्गीकरण —

आदेशात्मक आयोजन (Imperative Planning)	निदेशात्मक आयोजन (Indicative Planning)
i) केन्द्रीय व्यवस्था है।	i) विकेन्द्रीकृत व्यवस्था
ii) राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक तथा प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है।	ii) राज्य एवं संस्थाओं का सांकेतिक हस्तक्षेप
iii) समाजवादी देश; रूस, चीन	iii) निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी
iv) प्रशासनिक ढाँचे को सक्रिय रखने के लिए दंड विधि का प्रयोग किया जाता है।	iv) सरकार केवल नीतियाँ बनाने तक ही अपने आप को सीमित रखती है।
v) वितरण प्रणाली में प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका होने के	v) बाजार क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

1980 के दशक से पूरी दुनिया के देशों में निदेशात्मक आयोजन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भारत में 1991 से पहले लगभग आदेशात्मक आयोजन की स्थिति थी लेकिन 1991 के आर्थिक सुधार के बाद हम निदेशात्मक के ज्यादा करीब है।

हमारी आयोजन व्यवस्था में समाजवादी तथा पूंजीवादी, सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया है।

अर्थव्यवस्था की केन्द्रीय समस्याएँ

i) क्या उत्पादन किया जाये
ii) कैसे उत्पादन किया जाये
iii) श्रम से या मशीन से ।

→ **आर्थिक एजेंट** —

जो आर्थिक निर्णय लेते है ।

उपभोक्ता, उत्पादक, बैंक, निगम, सरकार आदि हो सकते है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

अंतिम वस्तुएँ —

जिसका अंतिम उपयोग होता है, अर्थात उन्हें उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता।

चायपत्ती अंतिम वस्तु है। कोई वस्तु प्रकृति के कारण नहीं उपयोग की आर्थिक प्रकृति से अंतिम वस्तु मानी जाती है। केवल अंतिम वस्तु की मूल्य की गणना की जाती है, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी सामिल होता है।

सामान्य वस्तुएँ —

i) जिनका उपयोग अधिकतर उपभोक्ता करता है।
ii) आय बढ़ेगी तो वस्तु की मात्रा बढ़ेगी।
iii) आय कम होगी तो वस्तु की मात्रा कम होगी।

निम्न स्तरीय वस्तुएँ —

i) ये उपभोक्ता आय के विपरित है।
ii) आय बढ़ी तो मांग घटी } [खाद्य पदार्थ —
iii) आय घटी तो मांग बढ़ेगी } मोटे अनाज].

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

पंचवर्षीय योजनाएं

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

प्रथम —

- 1951-56
- हेरॉल्ड डोमर संवृद्धि मॉडल पर आधारित
- भूमि सुधार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से खाद्य संकट का समाधान और कृषि क्षेत्र का विकास करना।

दूसरी — (1956-61)

- महालनोबिस मॉडल और उद्योगों को प्राथमिकता।

तीसरी — (1961-66)

- खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना।

योजना अवकाश — (1966-69)

- चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई जिसके कारण तीन 1 वर्षीय योजनाएँ बनाई गई।

चौथी — (1969-74)

- कुछ खास नहीं लेकिन परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू करना।

पांचवी — (1974-79)

- गरीबी उन्मूलन का नारा

अनवरत योजना (Rolling Plan)

- जनता पार्टी की सरकार ने 5th FYP को 1 वर्ष पूर्व 1978 में ही समाप्त कर दिया और 1983 तक अनवरत योजना बनाई गई लेकिन नई सरकार ने 1980 में ही इसे समाप्त कर दिया।

छठी — (1980-85)

सातवीं — (1985-90)

नई आर्थिक नीति — (1990-91)

अपनाने के कारण —

i) भुगतान असंतुलन
ii) राजकोषीय घाटे में वृद्धि
iii) विदेशी विनिमय कोष में कमी
iv) सार्वजनिक उद्योगों का खराब प्रदर्शन
v) खाड़ी संकट के कारण पेट्रोल के दाम में वृद्धि

किये गये कार्य —

i) उदारीकरण — उद्योग एवं व्यापार के लिए उदार नीति
ii) निजीकरण —
iii) वैश्वीकरण — आयात & निर्यात को मान्यता प्रदान करना।

पहली पीढ़ी के सुधार — (1991-96)

i) 6 उद्योगों (शराब, सिगरेट, औषधि, रक्षा उपकरण, विस्फोट एवं खतरनाक रसायन) को छोड़कर सभी उद्योगों में Licence की समाप्ति।
ii) FII को अनुमति iii) कर प्रणाली को सरल बनाया गया।
iv) निर्यात को बढ़ावा देने के लिये रुपये का अवमूल्यन।

आठवीं — (1992-97)

1990-92 तक राजनीतिक अस्थिरता व आर्थिक संकट के कारण 2 एक वर्षीय योजनाएँ बनाई गई। इसलिए 1992 से 8वीं FYP की शुरुआत हुई।

9वीं — (1997-2002)

10वीं — (2002-07)

11वीं — (2007-12) → राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा किसानों के लिए ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

12वीं FYP —

i) उद्देश्य – तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करते हुए 8% विकास दर प्राप्त करना निर्धारित की गई है।

ii) कृषि क्षेत्र में 4% एवं विनिर्माण क्षेत्र में 10% औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य।

iii) लिंग समानता एवं महिला सशक्तीकरण पर बल

बाज़ार-अर्थव्यवस्था का दूसरा दौर: बाज़ार-अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहतर नज़रिया भी अपनाया जा सकता है। ऊँची वृद्धि दर ज़रूरी है, पर केवल इसी से गरीबी, वंचना, अवसरों की कमी और भेदभाव जैसी पुरानी समस्याओं से नहीं निपटा जा सकता। वृद्धि अभिमुखी नीतियों के साथ-साथ ऐसे कदम उठाने भी ज़रूरी हैं, जो समावेशी विकास, पूरी आबादी की न्यूनतम ज़रूरतों की पूर्ति और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकें।

1991 के बाद हुए प्रमुख सुधार

- विदेश व्यापार की नई नीति: जुलाई 1991 से मॉर्च 1992 के बीच कई कदम उठाए गए। आयात और निर्यात से संबंधित तमाम निषेधों, अवांछित निर्देशों, शंकाओं और अस्पष्टताओं को दूर किया गया। आयात और निर्यात को नियंत्रित करने वाला कार्यालय बंद कर दिया गया। वस्तुओं के मुक्त आयात-निर्यात की घोषणा की गई।
- औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति: इससे उद्योगों को क्षमता, तकनीक और कीमत पर नियंत्रण से मुक्ति मिल गई और प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन मिला।
- जुलाई 1991 में निश्चित विनिमय दर से हटने और बाज़ार द्वारा निर्धारित विनिमय दर की तरफ बढ़ने की शुरुआत हुई। 'फेरा' कानून रद्द किया गया और 'फेमा' कानून ने उसकी जगह ली, जो 'नियंत्रण' से 'नियमन' की तरफ बढ़ने का संकेत था।
- भारत के पूंजी बाज़ार ने आकार लेना शुरू किया। कैपिटल इश्यूज़ के नियंत्रक का कार्यालय बंद कर दिया गया और सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड) का गठन किया गया।
- एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act–MRTP Act) के प्रमुख प्रावधान रद्द कर दिये गए। प्रतिस्पर्द्धा आयोग अधिनियम, 2002 लागू

दूसरी पीढ़ी के सुधार (1996 से)

- दूसरी पीढ़ी के सुधारों के अंतर्गत कृषि सुधार, बुनियादी ढाँचा सुधार जिसमें आर्थिक बुनियादी ढाँचे के अंतर्गत सिंचाई एवं जल निकास, परिवहन, संचार, विद्युत आपूर्ति, वित्तीय ढाँचे के विस्तार पर बल दिया।
- सामाजिक बुनियादी ढाँचे के तहत निवास ढाँचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, मनोरंजन के विकास पर बल दिया।
- स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाया गया।
- व्यवहारपरक विदेश नीति अपनाई गई।
- अवसर की समानता तथा हितों की रक्षा के लिये अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, महिला आयोग तथा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।

2017 के बाद से FYP बंद कर दी गयी हैं इसकी जगह NITI AYOG का action agenda चल रहा है

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims

बेरोज़गारी

https://t.me/UPSC_Mains

- जनगणना रिपोर्ट
- रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ।

जब एक व्यक्ति रोज़गार की तलाश करता है लेकिन वह काम पाने में सफल नहीं हो पाता — इस अवस्था को बेरोज़गारी कहा जाता है।

सामान्यतः 15-59 वर्ष आयु वर्ग को आर्थिक रूप से सक्रिय माना जाता है। यदि इनके पास काम नहीं है तो इन्हें ही बेरोज़गार माना जाता है।

भारत में बेरोज़गारी के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक रोज़गार है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम, जिससे अत्यधिक अंतर राज्य श्रमिक प्रवसन होता है।

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

बेरोज़गारी को बढ़ाने वाले कारक —

- बढ़ती हुई technology
- मंदी
- मुद्रास्फीति
- कार्यस्थल पर भेद-भाव, आदि ।

बेरोज़गारी के कारण —

- बढ़ती जनसंख्या
- सीमित भूमि संसाधन
- कृषि की मौसमी बेरोज़गारी
- दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली — शिक्षित बेरोज़गारी
- विनिर्माण का पिछड़ापन

https://t.me/UPSC_Prelims

https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

बेरोजगारी के प्रकार —

i) पूर्ण एवं अर्द्ध बेरोजगारी —

वार्षिक रोजगार आकलन

95 से कम दिन रोजगार है तो — पूर्ण बेरोजगारी
95 से 195 " " " " — अर्द्ध बेरोजगारी
195 से अधिक " " " " — पूर्ण रोजगार.

ii) प्रच्छन्न बेरोजगारी —

किसी काम को जरुरत से ज्यादा लोगों द्वारा करना जबकि उतने लोगों की जरुरत नहीं होती। इसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है।

इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है।

इसके कारण -

- बढ़ती जनसंख्या
- गैर-कृषि रोजगारों की कमी

iii) संरचनात्मक बेरोजगारी —

दीर्घकालीन समस्या

इस बेरोजगारी का संबंध अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष से होता है। देश की उत्पादक संस्थाओं की संख्या में कमी के कारण अवसर सीमित रह जाते हैं। दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ती रहती है। इसके कारण —

- औद्योगिकरण का अभाव
- कुशलता विकास की कमी।

भारत जैसे देश में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। बचत, निवेश, उत्पादन को बढ़ाकर इसमें

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

iv) चक्रीय बेरोजगारी —

यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था / बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। यह मुख्य रूप से पूंजीवादी / विकसित देशों में देखने को मिलती है, जो मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी अल्पकालिक होती है, इसलिए इसे मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों द्वारा मांग को बढ़ाकर सुलझाया जा सकता है।

v) अनैच्छिक बेरोजगारी —

प्रचलित दर पर काम करने की इच्छा होते हुए भी काम की उपलब्धता न होना।

vi) मौसमी बेरोजगारी —

- कृषि में देखने को मिलती है
- फसल उगाना, निराई, कटाई के समय काम मिलता है।
- ये काम खत्म होने पर कामगार बेरोजगार हो जाते हैं।

vii) अस्थायी बेरोजगारी —

जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं।

नियोक्ता कामगारों की खोज में रहते हैं और कामगार रोजगार की तलाश में रहते हैं। जब तक यह दोनों नहीं मिलते तब तक बेरोजगारी बनी रहती है। सूचना का अभाव तथा भौगोलिक दूरी इस स्थिति को और भी जटिल बना देती है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

भारत में बेरोजगारी की स्थिति (NSSO) —

→ भारत में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं लेकिन उनके बढ़ने की दर श्रम बल बढ़ने की दर से कम है। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि भारत में Jobless Growth है।

भारत में रोजगार की सोच लगातार गिरती जा रही है।

कार्यबल का व्यवसायिक वितरण निम्न प्रकार पाया गया —

a) कृषि — 49%
b) उद्योग — 24%
c) सेवाएँ — 27%.

स्पष्ट है कि भारत में लोगों का व्यवसायिक बदलाव ठीक से नहीं हुआ है। कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है और यह निर्भरता ऐसी स्थिति में है जब राष्ट्रीय आय में कृषि की भूमिका कम है।

भारत में GDP की त्वरित वृद्धि दर को सुनिश्चित करना और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना जो रोजगार के अच्छे अवसर उत्पन्न करते हैं।

कुशलता विकास पर ध्यान देना तथा निर्धनों, आशिक्षित लोगों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण को सुनिश्चित

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

करना ताकि उनकी रोज़गार प्राप्त करने की क्षमता बढ़े। इससे संवृद्धि की प्रक्रिया को भी उच्च गुणवत्ता युक्त रोज़गार देने में आसानी होगी।

भारत के श्रम कानूनों में इस प्रकार से बदलाव करना की वे श्रम के अपशोषण को बढ़ावा दें न कि श्रम के बहिष्करण को।

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

गरीबी

गरीबी अवसरों एवं विकल्पों से वंचित रहने की वो एक स्वस्थ, स्वतंत्र, गरिमापूर्ण, आत्मसम्मान जीवन जीने के लिए आवश्यक है।

वह सामाजिक और आर्थिक स्थिति जिसके अंतर्गत जब लोगों द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं ; जैसे - **रोटी**, **कपड़ा** और **मकान** तक की भी पूर्ति नहीं हो पाती उसे गरीबी कहते हैं।

गरीबी के प्रकार

निरपेक्ष गरीबी

↓

इसमें मनुष्य की **बुनियादी** आवश्यकताएँ ; जैसे - भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा, सूचना का अभाव होता है।

विकासशील देशों में पाई जाती है।

सापेक्ष गरीबी

↓

समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय और संपत्ति का अभाव जिसके कारण संबंधित लोगों की आय या जीवन स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है।

→ गरीबी केवल धन का अभाव ही नहीं बल्कि एक मानसिक दशा भी है। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक बेहतरी और राष्ट्र कल्याण हेतु भी नहीं सोच पाता।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

गरीबी रेखा निर्धारण — (NSSO द्वारा)

भारत में गरीबी मापने के लिए **उपभोग अथवा खर्च विधि** का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा तर्क दिया जाता है कि गरीबी को मापने के लिए आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

विश्व बैंक का भारतीय गरीबी पर अनुमान —

रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है। **विश्व बैंक** द्वारा 1.9 **अमेरिकी डॉलर** आय को एक मानक के रूप में प्रयोग किया गया है जो पहले 1.25 $ (2005) था।

MPI (Multi-Dimensional Poverty Index) – 2010

1. **Education**
   - कौशल में कमी
2. **Health**
   - कुपोषण
3. **Living Standard.**
   - आवासीय सुविधा का अभाव और सामाजिक

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

गरीबी के कारण :—

i) **कृषि पर निर्भरता** —

अधिकांश विकासशील देश में लोग कृषि पर निर्भर हैं और वर्तमान में कृषि अलाभकारी होती जा रही है।

ii) **रोजगार के अवसरों का अभाव** —

iii) **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा** —

शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गरीबी और बढ़ती है।

iv) औपनिवेशिक प्रशासन — पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य नष्ट हुई।

v) भूमि सुधार की असफलता —

vi) बढ़ती जनसंख्या और आय के कम स्रोत।

गरीबों की संख्या अधिक होने से उनकी मजदूरी दर कम हो जाती है, क्योंकि माँग की तुलना में आपूर्ति दर कम हो जाती है। मजदूरी दर कम होने से आय कम हो जाती है। इस वजह से परिवार के बच्चे श्रम कार्य में लगाये जाते हैं — इससे बाल श्रम की समस्या भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार गरीबों की अगली पीढ़ी भी गरीबी और मजदूरी में रह जाती है।

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

गरीबी कम करने के सुझाव / उपाय

i) जनसंख्या नियंत्रण

ii) कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना —

- कृषि आधारभूत ढांचे का विकास ; जैसे – सिंचाई आदि |
- विपणन संबंधी सुधार |
- MSP
- तकनीक को बढ़ावा देना |

iii) रोजगार के अवसरों का सृजन —

- निर्माण, विनिर्माण – श्रम सुधार, प्रशासनिक भार को कम करना, बाजार की विकृतियों को दूर करना,

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

iv) मूलभूत सेवाओं ; जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय-जल में सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना।

(M) 9268098159
D. K. PHOTOSTAT
Old N.C.E.R.T. Available All Subject
(Courier Facility)
(IAS/PCS) All Study Materials Available
701, Shop No. 2,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

Trickle – down और गरीबी —

इसके अंतर्गत

↓

i) ब्याज दरों में कटौतियाँ की जाती है।

ii) तरलता का विस्तार किया जाता है।

iii) करों में छूटें दी जाती है।

iv) विभिन्न प्रकार की सब्सीडियाँ दी जाती है।

⇓

ताकि औद्योगीकरण, सेवा क्षेत्र आदि को बढ़ावा मिल सके।

नवीनतम अनुसंधान में Trickle – down आय की विषमताओं को बढ़ा रहे हैं और गरीबी को कम करने में इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा इन छूटों का लाभ उठाया जा रहा है।

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा Trickle – down को निष्प्रभावी बताया गया जिसके निम्न कारण हैं —

i) उदारीकरण की नीतियों में कृषिक क्षेत्र की उपेक्षा करना

ii) गैर-कृषि गतिविधियों के विकास पर ध्यान नहीं देना।

iii) MSMEs क्षेत्र की उपेक्षा करना

iv) कुशलता विकास पर ध्यान नहीं देना

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains
CONTACT ME FOR ANY QUERY DOUBT AND GUIDANCE RELATED TO THIS NOTE AND UPSC STUDY (9898140145)

मनरेगा

→ ग्रामीण विकास मंत्रालय
→ 2005 में संसद द्वारा पारित कानूनी अधिकार
→ 2 Feb 2006 से आंध्रप्रदेश से लागू
→ काम के बदले अनाज + संपूर्ण ग्रामीण रोजगार को मिलाकर बनाया
→ 2009 में नरेगा से मनरेगा
→ प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक व्यस्क को जो अकुशल श्रम के लिये तैयार हो — 100 दिनों के रोजगार की गारंटी (1 वर्ष में).
→ 33% महिलाओं को आरक्षण
→ रोजगार पाने वाले को आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जायेगा (5 Km. के अंदर) वर्ना बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
→ रोजगार गारंटी कोष बनाया गया है।
→ क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा
→ वित्त ⟶ केन्द्र : राज्य :: 90 : 10 .
→ ग्रामीण अवसंरचना के विकास से संबंधित क्षेत्र, जैसे - जल संग्रहण, सड़क निर्माण, सिंचाई, हॉस्पीटल इत्यादि में रोजगार प्रदान किया जाता है।
→ राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को सूखा घोषित करने ही रोजगार दिवसों की संख्या 100 से 150 दिन हो जाती है।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

→ स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया है।
→ देय मजदूरी को DBT Scheme से जोड़ा गया है।

मनरेगा से लाभ

- गरीबी कम की है।
- न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित जिससे क्रय शक्ति क्षमता बढ़ी है।
  - जिससे मांग बढ़ी एवं ग्रामीण खपत ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी की चपेट में आने से रोका।
- वित्तीय समावेशन जिससे साहूकारों पर निर्भरता कम हुई।
- महिला सशक्तीकरण
- रहन-सहन के स्तर में सुधार
- प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि एवं संरक्षण।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

जनसंख्या

विधिवत जनगणना - 1881
अभी 2011 - 15वीं थी।
1911 से 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि इसमें गत की जनसंख्या में कमी हुई थी।

→ 121 करोड़ (2011)
→ चीन के बाद दूसरा स्थान
→ विश्व की जनसंख्या का 17.5 %.
→ विश्व के कुल भू-भाग का 2.4 %.
→ 2001 - 2011 औसत वार्षिक वृद्धि 1.77 %.
→ शहरी जनसंख्या 31.16% और ग्रामीण 68.84 %.
→ जनसंख्या घनत्व 2001 - 324 था और 2011 - 382 (प्रति वर्ग किलोमी.

- अशोधित जन्म दर — प्रति हजार जनसंख्या पर किसी विशेष वर्ष में जन्में पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या।
- अशोधित मृत्यु दर — इसका उल्टा है (मृत्यु दर).
- जनसंख्या की वृद्धि दर — किसी रूक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर के अंतर तथा इसमें निवल Migration दर को जोड़ दिया जाये तो इसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहा जाता है।
- मातृत्व मृत्यु दर — प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर प्रसव के दौरान या गर्भ नष्ट होने के 42 दिनों में मरने वाली महिलाओं की संख्या। (174).
- लिंगानुपात — प्रति हजार पुरुषों की संख्या के अनुपात में स्त्रीयों की संख्या। (940).
- शिशु मृत्यु दर — प्रति हजार जीवित जन्में शिशुओं के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या।
- बाल मृत्यु दर — 1000 जन्में जीवित बच्चों की संख्या के अनुपात में 5 वर्ष तक के मृत बच्चों की संख्या।
- संपूर्ण प्रजनन दर — किसी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल (15-49) में पैदा हुए बच्चों की संख्या।
- शिशु लिंग अनुपात — 6 वर्ष तक के आयु समूह में प्रति हजार बालकों के समूह में बालिकाओं की संख्या। (914).

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

जनसंख्या नीति-2000 — इस नीति के अनुसार भारत 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर लेगा लेकिन अब इस लक्ष्य को 2070 कर दिया गया है।

संपूर्ण प्रजनन दर को 2.1 पर लाना।

आशा :—

- जननी सुरक्षा योजना से संबंधित ग्रामीण कार्यकर्ता।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन से जुड़ी है।
- आशा द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल की जाती है तथा गर्भावस्था के दौरान पोषण तथा स्वास्थ्य के विषय में सलाह देती है।
- इनका कार्य प्रसव कराना नहीं है।

- सी.पी. ब्लेकर द्वारा जनसंख्या में परिवर्तन की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं-

1. **प्रथम अवस्था:** इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही ऊँची होंगी। जनसंख्या वृद्धि का आकार स्थिर या बहुत धीमा होगा।
2. **द्वितीय अवस्था:** यह अवस्था विकास की ओर अग्रसर देशों में पाई जाएगी। इसके अंतर्गत जन्म दर में तेजी परन्तु मृत्यु दर में कमी होगी, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनेगी।
3. **तीसरी अवस्था:** औद्योगिक तथा कृषि विकास के चरण में प्रवेश करने वाले देशों में जनसंख्या की इस अवस्था की स्थिति होगी। जिसके अंतर्गत जन्म दर में कमी होगी परंतु मृत्यु दर उससे अधिक तेजी से घटेगी। जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी होगी, परंतु जनसंख्या की भयावह स्थिति बनी रहेगी।
4. **चौथी अवस्था:** यह अवस्था उच्च विकास के दौर में पहुँचे हुए विकसित देशों में होगी जिसमें जन्म दर नियंत्रित तथा नीची, साथ ही मृत्यु दर भी नियंत्रित तथा नीची ही होगी। इस स्थिति में जनसंख्या तेजी से गिरती है।
5. **पाँचवीं अवस्था:** पूर्ण विकास की दर को प्राप्त किये हुए विकसित राष्ट्रों में ऐसी अवस्था पाई जाती है। इसमें जन्म दर अत्यंत नीची तथा मृत्यु दर से भी कम होती है। साथ ही मृत्यु दर भी नीची होती है।

भारत में जन्म दर में संतोषजनक कमी न आने के कारण

- कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था
- गरीबी
- शिक्षा का निम्न विकास स्तर
- कम उम्र में विवाह होना
- सामाजिक अंधविश्वास-पुत्र की प्रधानता
- नगरीकरण की धीमी प्रक्रिया

भारत में मृत्यु दर में कमी लाने के लिये सहायक कारक

- स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
- अकाल की समाप्ति
- हैजा, प्लेग, चेचक आदि महामारियों की समाप्ति
- शुद्ध पेयजल उपलब्धता, प्रसव के दौरान अच्छी चिकित्सा सुविधा आदि।

जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय —

- शिक्षा
- विवाह की न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा
- औद्योगिकरण को बढ़ावा देना
- सामाजिक मानसिकता में बदलाव
- आय में वृद्धि
- 1952 राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया गया था। (विश्व का पहला)

लिंगानुपात :—

- हरियाणा - 877
- केरल - 1084
- J&K - 889
- तमिलनाडु - 996

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष)

- संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में जुलाई 1944 में आयोजित 44 देशों के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.वी.आर.डी.) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की स्थापना की गयी थी।
- वर्तमान में 188 राष्ट्र आई.एम.एफ. के सदस्य हैं।
- भारत आई.एम.एफ. का संस्थापक सदस्य है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अग्रलिखित है:- वृहद आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, गरीबी कम करना, आर्थिक स्थिरता बनाये रखना, विकासशील देशों के लिए नीतिगत सलाह और वित्त पोषण, मौद्रिक प्रणाली में सहयोग के लिए मंच प्रदान करना, विनिमय दर स्थिरता तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना।
- 1993 के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई वित्तीय सहायता नहीं लिया है। आई.एम.एफ. से लिए गए सभी ऋणों का भुगतान 31 मई 2000 को कर दिया गया।

→ स्थापना 27 Dec 1945
→ BOP संकट से निपटने के लिए सदस्य देशों को ऋण देना
↓
(अल्पकालीन)
वर्ल्ड बैंक सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण सहायता।

— IMF अपने सदस्य देशों के कोटा प्रतिशत या अधिकारों (SDR) की प्रत्येक 5 साल में समीक्षा करता है।

क्या है कोटा प्रणाली?

आईएमएफ एक बहुपक्षीय ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डी.सी में अवस्थित है। यह विकसित व दूसरे समर्थ सदस्य देशों से वित्तीय सहायता लेता है और ज़रूरत पड़ने पर विकासशील एवं गरीब सदस्य देशों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। इस क्रम में प्रत्येक सदस्य देश का कोटा, तीन मापदंडों विश्व व्यापार में भागीदारी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास दर को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जाता है। 'कोटा प्रतिशत' के आधार पर संबंधित देश को आईएमएफ में मताधिकार दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली चुनिंदा विकसित देश हमेशा से इस संगठन के दिशा-निर्देशों को प्रभावित करते आ रहे हैं।

कोटा प्रणाली में विकासशील देशों की स्थिति

आईएमएफ के सदस्य देशों में विकासशील देशों की संख्या बहुलता में है, लेकिन संस्था के दिशा-निर्देशों को तय करने में उनकी भूमिका न्यून है। ऐसी स्थिति निश्चित रूप से इस संस्था के लिये घातक है, क्योंकि यह सहभागिता को लोकतांत्रिक या तार्किक प्रक्रिया नहीं है। फिलहाल, इस संगठन में कोटा प्रतिशत की समीक्षा प्रत्येक पाँच साल में की जाती है, लेकिन संगठन का 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' कभी भी विकासशील देशों का कोटा प्रतिशत नहीं बढ़ाता है। इसके लिये, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि चूँकि विकासशील देश आईएमएफ से ऋण तो लेते हैं, लेकिन 'रिवॉल्विंग फंड' में उनका अंशदान न्यून या न के बराबर होता है। लिहाज़ा, उनके कोटा प्रतिशत में इजाफा करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

* व्यवहारिक स्तर पर IMF एक लोकतांत्रिक संगठन नहीं है।

जहाँ सभी सदस्य देशों को मताधिकार समान रूप से हासिल नहीं है, वहीं अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश हमेशा से आईएमएफ में किसी भी मुद्दे पर मताधिकार, नीति-निर्माण, दिशा-निर्देश आदि को शुरू से ही प्रभावित करते आए हैं। यही देश यह तय करते हैं कि किस सदस्य देश को ऋण दिया जाए और उसकी शर्तें क्या हों? बीते सालों में आईएमएफ के शक्तिशाली सदस्य देशों द्वारा कर्ज़दार देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने के मामले भी देखने में आए हैं।

विश्व अर्थव्यवस्था में आईएमएफ की प्रासंगिकता

मौजूदा समय में विश्व अर्थव्यवस्था में आईएमएफ की भूमिका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर वह अपनी आंतरिक खामियों को दूर करते हुए एक लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू करने में सफल रहता है तो निश्चित रूप से विश्व में गरीबी के उन्मूलन एवं समावेशी विकास को

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

आईएमएफ में व्याप्त खामियाँ

आईएमएफ की कार्यप्रणाली के स्तर पर विकसित देशों की दादागीरी पर नियंत्रण करना आईएमएफ के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें सफलता हासिल करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ, 1973 के विश्वव्यापी तेल संकट (Oil Crisis) के बाद ऐसा महसूस किया जा रहा है कि आईएमएफ विकासशील देशों की वित्तीय जरूरतों का सही आकलन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण विकासशील देश ऋण का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आईएमएफ विकासशील देशों को तार्किक ढंग से तकनीकी सहायता भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। ऐसा भी देखने में आया है कि आईएमएफ की नीतियों के दोषपूर्ण होने के कारण विकासशील देश ऋण का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार एवं अन्य समस्याएँ पनप रही हैं।

आईएमएफ की नीतियों का भोजन एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव

देखा गया है कि आईएमएफ की नीतियों से विकासशील देशों में दो वक्त के भोजन की उपलब्धता एवं कृषि गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल, आईएमएफ द्वारा ऋण की शर्तों या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों से विकासशील देशों की नीतियों को प्रभावित करने के कारण संबंधित देश की कृषि गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे फसलों की उत्पादकता में कमी आती है। इस बात की पुष्टि भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिये गए अपने भाषण में की थी। 2009 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किये गए एक अध्ययन में भी पाया गया कि आईएमएफ ने जिन 21 विकाशसील देशों को ऋण दिया था, वहाँ विकास होने की बजाय, टीबी से हुई मौतों में 16.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2009 में ही प्रसिद्ध लेखक 'रिक रोडेन' ने अपनी किताब "द डेडली आइडियाज़ ऑफ नियोलिबरलिज़्म" में लिखा था कि आईएमएफ विकासशील देशों में अपनी आर्थिक नीतियों जैसे, निम्न मुद्रास्फीति और निम्न बजट घाटा आदि के माध्यम से स्वास्थ्य एवं एड्स के विरुद्ध जारी लड़ाई को कमज़ोर करने का काम कर रहा है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि भले ही आईएमएफ एक लंबे समय से अस्तित्व में है, लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा करने में यह पूरी तरह से नाकाम रहा है। वस्तुत: इसका मुख्य मकसद था- सदस्य देशों को आर्थिक रूप से सबल बनाना, गरीबी उन्मूलन करना, विकास को गति देना, रोज़गार सृजन में सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल व सुगम बनाना आदि, लेकिन यह ऐसा करने में असफल रहा है। आईएमएफ के अंदर लोकतंत्र का अभाव है। किसी भी कार्य को पारदर्शी तरीके से अंजाम नहीं दिया जाता है, विकसित और विकासशील देश नदी के दो छोर बन गए हैं। देखने में यह भी आया है कि आईएमएफ की आड़ में विकसित देश विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे विकासशील देशों को एक बड़े बाज़ार और प्रयोगशाला के रूप में देख व इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पष्ट है कि सभी देशों को बराबर मताधिकार देने से ही विकसित देशों की आईएमएफ में चल रही दादागीरी को खत्म एवं इसकी सार्थकता को बरकरार रखा जा सकता है।

■■■

सुधार संबंधी विवाद :-

1) IMF की कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक नहीं माना गया है। विकासशील देश IMF में कोष और मताधिकार बढ़ाने की माँग कर रही है। इसका वितरण असंतुलित ढंग से विस्तृत राष्ट्रों के पक्ष में है। अमेरिका के पास 16.5% भाग के साथ वीटो Power है।

11) IMF के Executive Board की संरचना भी प्रजातांत्रिक नहीं

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

मानी गई है। इसमें कुल २५ सदस्य होते हैं। जहाँ अमेरिका जैसे राष्ट्र अकेले एक सदस्य को भेजते हैं, वहाँ भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश मिलकर एक सदस्य को भेजते हैं।

iii) भारत का यह भी कहना है कि भारत के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो, क्योंकि अमेरिका ~~का~~ और यूरोपीयन राष्ट्रों के बीच एक सहमति बनी हुई है कि IMF का प्रबंध निदेशक कोई यूरोपीयन होगा जबकि विश्व बैंक का अध्यक्ष कोई ~~यू~~ अमेरिकन होगा।

* IMF के सुधार ; Jan 2016

मताधिकार:

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के गवर्नेंस संरचना में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रभाव में में अधिक वृद्धि हुई है।
- इन सुधारों के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के हिस्से से 6 प्रतिशत से अधिक कोटा उभरते और विकासशील देशों को प्राप्त होंगे।
- नए प्रावधानों के तहत भारत का मताधिकार वर्तमान 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत और चीन का 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया है।
- रूस और ब्राजील भी इन सुधारों से लाभान्वित हुए हैं।
- इन सुधारों के कारण यू.एस., जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, चीन और रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शीर्ष 10 सदस्यों की सूची में भारत और ब्राजील भी शामिल हो गए हैं।
- इस सुधार प्रक्रिया के कारण कनाडा और सऊदी अरब शीर्ष दस देशों की सूची से बाहर हो गए हैं।
- BRICS समूह की चार उभरती अर्थव्यवस्थायें -ब्राज़ील, चीन, भारत और रूस- प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 10 सबसे बड़े सदस्य देशों के समूह में शामिल होंगी।

आई.एम.एफ. की वित्तीय ताकत में वृद्धि:

- इन सुधारों ने आई.एम.एफ के स्थायी पूंजी संसाधनों को दुगुना कर इसे 477 बिलियन एस.डी.आर (विशेष आहरण अधिकार) (659 बिलियन डॉलर) कर दिया है, जिससे इसकी वित्तीय ताकत में भी वृद्धि हुई है।

आई.एम.एफ. कार्यकारी बोर्ड:

- इन सुधारों का एक पहलू यह भी है कि आई.एम.एफ के कार्यकारी बोर्ड के लिए कुछ कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति (अपॉइंटमेंट) के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब

- आई.एम.एफ के 14वें 'जनरल कोटा रिव्यु' के प्रभावी होने के बाद अब मुख्य ध्यान 15वें जनरल कोटा रिव्यु पर कार्य करने की दिशा में केंद्रित होगा। पुनः एक नया कोटा फार्मूला पर कार्य करने के अतिरिक्त सर्वसम्मति के व्यापक सिद्धांत को हासिल करने पर भी काम किया जाएगा।
- ये सुधार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और वैधता को सुदृढ करेंगे।

भारत को लाभ —

अधिक वोटिंग अधिकार और अधिकारी दमता। निर्णय निर्माण में भारत का ज्यादा दखल।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims

[अंतर्राष्ट्रीय रिज़र्व संपत्ति]

https://t.me/UPSC_Mains

SDR (Special Doing Right) —

Global liquidity को बढ़ाने के लिए 1969 में IMF द्वारा SDR को शुरू किया गया। इसे 'Paper of Gold' भी कहते हैं।

SDR के माध्यम से सदस्य बिना किसी भौतिक हस्तानान्तरण के परस्पर भुगतान के लिये स्वीकार की जाती है। निजी व्यापारिक व्यवहारों के लिये नहीं किया जाता है।

इसमें —

- डॉलर — U.S.A — 41%
- यूरो — यूरोपीय यूनियन — 31%
- पौंड — U.K — 8.09%
- येन — जापान — 8.5%
- युआन [(रेनमिनबी)-2016] — चीन — 10.9%

SDR में सम्मिलित होने की अनिवार्यता —

i) संबंधित राष्ट्र में एक Capital a/c convertibility हो।

ii) मुद्रा की विनिमय दर लोचशील हो, लेकिन इनमें से चीन में कोई नहीं है। लेकिन हाल ही में चीन के द्वारा युआन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए BRICS Bank में सर्वाधिक योगदान, AIIB की स्थापना, अनेक देशों के साथ Currency Swap जैसे समझौते किये गये थे।

→ SDR में भारत कुछ ₹ के रूप में जमा करवा सकता है। SDR में जमाकर्ता देश को ब्याज मिलता है लेकिन BOP के लिए अधिक ब्याज देना पड़ता है। कोटे का 25% SDR के रूप में रखना अनिवार्य।

→ Federal Reserve Bank of America डॉलर का निर्माण नहीं करता। डॉलर का निर्माण United State Department of the Treasury करता है।

https://t.me/UPSC_Prelims

https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

(सदस्य - 57)

AIIB - बीजिंग

[Asian Infrastructure Investment Bank].

+ अधिकृत पूंजी 100 अरब डॉलर और प्रदत्त पूंजी 50 अरब डॉलर
+ एशियाई देश कुल पूंजी का 75% योगदान करेंगे।
+ प्रत्येक देश को उसके शेयर का कोटा उसके आर्थिक आकार के आधार पर दिया जायेगा।
+ चीन — मत कोटा
  - चीन → 26%, 30%
  - भारत → 7%, 8%
  - रूस → 5%, 6%
+ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, U.K इसमें शामिल है। अमेरिका, जापान इसके सदस्य नहीं है।
+ AIIB अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए फंडिंग देगा। इसलिए इसे विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक के प्रतिद्वन्दी की तरह देखा जा रहा है।

ADB—

एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

- एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 22 अगस्त 1966 को एशिया के आर्थिक विकास में सहायक होने के लिए की गई थी। फिलिपिन्स के मनीला में इसका मुख्यालय है।
- एडीबी को विश्व बैंक के मॉडल पर बनाया गया है। इसकी मतदान प्रणाली भी समान है जहाँ मताधिकार सदस्यों के पूंजी अंशदान के अनुपात में वितरित किये गए हैं।
- वर्तमान में जापान 15.67% के साथ सबसे बड़ा अंशधारक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंशधारिता 15.56%, चीन की 6.47%, भारत की 6.36%% और ऑस्ट्रेलिया की 5.81% है।
- उद्देश्य: एशिया के देशों के आर्थिक विकास में सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाना। साथ ही इसका लक्ष्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्त कराना है।

सदस्य:

- वर्तमान में इसमें 67 सदस्य देश हैं, जिनमें से 48 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं।

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स

- इसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक प्रतिनिधि होता है। बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स बैंक के प्रतिनिधि का चुनाव भी करता है, जो कि, निदेशकों के बोर्ड का चेयरमैन होता है और एडीबी का प्रबंधन करता है।

ऋण: यह मुख्य मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करते हुए कठोर तथा उदार ऋण दोनों उपलब्ध कराता है। ये क्षेत्र हैं;अवसंरचना, जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण, क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकरण, वित्तीयक्षेत्रक विकास और शिक्षा।

मौजूदा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान

- वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिकी नेतृत्व में बनाया गया था।
- अमेरिका, यूरोप और जापान, अपनी अर्थव्यवस्थाओं के गिरावट के बावजूद, इन संस्थानों में अपना प्रभाव बनाये हुये हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका के पास अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों पर वीटो का अधिकार है।
- साथ ही साथ ये संस्थान चीन और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मान्यता देने में नाकाम रहे हैं।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

विश्व बैंक *(World Bank)*

- विश्व बैंक समूह में पाँच संगठन शामिल हैं-

(i) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association – IDA)

- इसकी स्थापना 1960 में हुई।
- आईडीए को विश्व बैंक की रियायती खिड़की (Soft Loan Window) भी कहा जाता है।
- आईडीए द्वारा निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को ऋण दिया जाता है। (Long term)

(ii) आईबीआरडी (International Bank for Reconstruction and Development)

- इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई।
- इसके द्वारा गरीब तथा अल्पविकसित देशों को विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों जैसे- गरीबी निवारण, अवसंरचना विकास आदि के लिये ऋण प्रदान किया जाता है। (Long term)

(iii) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation-IFC)

- इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी।
- IFC विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के उद्यमों के लिये पूंजी जुटाने की व्यवस्था करता है।
- 1961 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण बना।

(iv) बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था (MIGA)

- मिगा की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी।
- इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था- गैर व्यापारिक अवरोधों को कम करके समता निवेश (Equity Investment) तथा अन्य प्रत्यक्ष निवेशों को प्रोत्साहित करना।

(v) आईसीएसआईडी (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID): इसकी स्थापना 1966 ई. में की गई थी।

- विश्व बैंक से अभिप्राय सामान्यत: IBRD तथा IDA से है। उपर्युक्त पाँचों संस्थाओं को मिलाकर विश्व बैंक समूह कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है।

इसका मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों में होने वाले निवेश को Political Risk के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें आतंकवादी हमले, गृह युद्ध, राष्ट्रीयकरण आदि के कारण होने वाली हानियों को सम्मिलित किया गया है। यह Commercial Based के कारण होने वाली हानि को सुरक्षित नहीं करता।

इसका मुख्य कार्य विदेशी निवेश से जुड़े अनुबंधों से संबंधित विवादों के लिए समाधान करना है। भारत इसका सदस्य नहीं है।

ब्रिक्स क्या है ? (BRICS)

ब्राजील, रुस, भारत और चीन के वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक समूह के अर्थशास्त्री जिम ओ नील के द्वारा 'ब्रिक' शब्द का प्रयोग इन देशों के लिए संयुक्त रुप से किया गया।

- ब्रिक देशों ने वर्ष 2009 मे पहली बैठक की। इस समूह मे दक्षिण अफ्रीका बाद में शामिल हुआ। अत: ब्रिक अब ब्रिक्स (BRICS) का रुप ले चुका है।
- ब्रिक्स देशों में विश्व की कुल जनसंख्या की 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इन देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था 16 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। यद्यपि यह संयुक्त रुप से विश्व की अर्थ-व्यवस्था का 1/5वा भाग है किंतु उन्हें (IMF) में 11 प्रतिशत मत ही प्राप्त है। जबकि अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड तथा फ्रांस 40 प्रतिशत मतदान शक्ति का प्रयोग करते है।
- ब्रिक्स बैंक में संस्थापक सदस्यों का बराबर मताधिकार होगा।

ब्रिक्स (BRICS) बैंक क्या है?

- जुलाई 2014 में ब्रिक्स देश एक ऐसे विकासशील देश की स्थापना पर सहमत हुए जिसका उद्देश्य न सिर्फ ब्रिक्स देशों बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी आधारभूत ढाँचे और सतत् विकास संबंधी संशोधनों को गतिशील करना है। बैंक यह कार्य सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं में ऋण, गारंटी और इक्विटी के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराकर करना चाहता है।
- बैंक 50 बिलियन डॉलर की अभिदत्त पूंजी से प्रारंभ होगा यह पाँच संस्थापक सदस्यों में बराबर-बराबर बाँटा जाएगा। जिसमें ये देश 10 बिलियन डॉलर अगले सात वर्षो में नगद के रुप में तथा 40 बिलियन डॉलर गारंटी के रुप में मुद्रा विनिमय भंडार स्थापित करने पर भी सहमत हुए है। इसका उपयोग सदस्य देशों के द्वारा भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं से निपटने में किया जायेगा।
- इन सभी देशों में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भण्डार वाला देश चीन, मुद्रा भंडार में सबसे ज्यादा योगदान करेगा। ब्राजील भारत रुस में से प्रत्येक देश 18 बिलियन डॉलर का योगदान करेगा जबकि दक्षिण अफ्रीका 5 बिलियन डॉलर का योगदान करेगा।

यूरोपीय संघ

- वर्ष 1958 में स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) को ही बाद में यूरोपीय संघ का नाम दे दिया गया।
- इसमें 28 सदस्य देश हैं।
- यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों पर लागू होने वाले मानकों के द्वारा एकल बाजार का विकास किया है।
- यह कॉमन मार्केट का उदाहरण है।
- इसकी अपनी मुद्रा यूरो है जिसे 19 सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया गया है।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

विश्व व्यापार संगठन *(World Trade Organisation-WTO)*

- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी, 1995 को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते (General Agreement on Tariff and Trade-GATT) के स्थान पर हुई थी।
- WTO का गठन उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-93) के सफलतापूर्वक होने के बाद किया गया था।

विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य

- आयात प्रशुल्क तथा अन्य व्यापार बाधाओं को समाप्त करने या उनमें कमी लाने हेतु वार्ता करना।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाले नियमों पर सहमति बनाना।
- वस्तु एवं सेवा व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के सहमति प्राप्त नियमों को लागू करने संबंधी निगरानी एवं प्रशासन करना।
- विश्व व्यापार संगठन की अन्य प्रमुख गतिविधियों हेतु आवश्यक आर्थिक अनुसंधान करना तथा आँकड़ों का संग्रह एवं प्रसार करना।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) स्वतंत्र, स्वायत्त तथा एक वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग या अभिकरण नहीं है।

गैट (GATT) समझौता, जो वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, के साथ WTO में दो नए समझौते जोड़ दिये गए हैं:

(i) सेवाओं से संबंधित व्यापार के संबंध में सामान्य समझौता (General Agreement on Trade in Services-GATS)

(ii) जनरल एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड रिलेटेड आसपेक्ट्स ऑफ इन्टलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (TRIPS)

ट्रिप्स *(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*

बौद्धिक सम्पदा अधिकार विचारों, आविष्कारों तथा सृजनात्मक अभिव्यक्तियों तथा उनको संपत्ति का दर्जा दिये जाने के संबंध में जनता की सहमति तथा उसके स्वामित्वधारी को अधिकार दिये जाने से संबंधित हैं।

- ट्रिप्स के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले बौद्धिक संपदा अधिकार हैं-
  - कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार
  - ट्रेडमार्क
  - भौगोलिक संकेतक
  - औद्योगिक रूपरेखा
  - पेटेन्ट
  - इन्टिग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा
  - व्यापार संबंधी गुप्त सूचना

TRIMS (Trade Related Investment Measures) — 1994

- सदस्य राष्ट्रों में विदेशी निवेश को राष्ट्रीय दर्जा देना तथा QRs (Quantitative Restrictions — मात्रात्मक प्रतिबंध) हटाने को अनिवार्य करता है।
- विदेशी निवेशकों पर स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय श्रम और आयात-निर्यात के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को पारित करता है।

SSM (ए विशेष सुरक्षा उपाय) —

आयात में अप्रत्याशित वृद्धि या कीमतों में गिरावट की स्थिति में यह तंत्र विकासशील देशों में कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को अस्थायी रूप से बढ़ाने की अनुमति देता है।

दोहा सम्मेलन

- दोहा की वार्ता को दोहा विकास दौर कहा गया।
- दोहा दौर की वार्ता में कृषि, गैर कृषि बाज़ार पहुँच (NAMA), सेवाएँ नियम, बौद्धिक संपदा एवं इससे जुड़े भौगोलिक संकेतक एवं जैव विविधता, व्यापार एवं पर्यावरण, एंटी डम्पिंग आदि मुद्दे शामिल थे।
- दोहा दौर की वार्ताएँ मुख्यतया गतिरोध में ही चलती रहीं। इसमें विकसित तथा विकासशील देशों जैसे- भारत, चीन, ब्राजील आदि के बीच मुख्यतया कृषि संबंधी मुद्दे, व्यापार सुधार आदि को लेकर संशय की स्थिति बनी रही।
- कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडी दोहा मुद्दे का मुख्य विषय रहा है।
- कृषि सब्सिडी के समर्थक यानी विकासशील देश कृषि सब्सिडी को विश्व व्यापार संगठन के नियमों में बांधने के पक्ष में नहीं हैं।
- दोहा मुद्दे में व्यापार सरलीकरण ऐसा मुद्दा है जिस पर काफी प्रगति हुई है। 2013 की बाली बैठक में WTO के अंतर्गत व्यापार सरलीकरण हेतु समझौता हो गया है।

गैर कृषि बाज़ार पहुँच *(Non-Agricultural Market Access-NAMA)*

- नामा संबंधी वार्ता को वर्ष 2001 में दोहा दौर की वार्ता में शामिल किया गया था।

IAS, PCS, SSC, BANK PO, NCERT IES-NET ALL STUDY MATERIAL
COURIER
D.K. PHOTOSTAT
FACILITY
(M) 9268098159

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

TRADE BARRIERS

TARIFF

- कर लगाकर विदेशी माल को महंगा करना।

NON-TARIFF

- कोटा, गुणवत्ता, सब्सीडी

कोटा → विदेशी माल का कोय निर्धारित करना

गुणवत्ता में कमी निकालना

ताकि विदेशी माल कम आ सके।

- सब्सीडी से घरेलू माल सस्ता करना ताकि विदेशी माल टिक न सके।

इनको हटाना उदारीकरण कहलाता है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

नई विदेश व्यापार नीति [2015-20]

- निर्यात को 450 बिलियन डॉलर (2013-14) से बढ़ाकर 2019-20 तक **900 बिलियन डॉलर** करना।
- विश्व **निर्यात** में भारत के योगदान को **2%** से **बढ़ाकर 3.5%** करना।
- पहले से निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली चल रही योजनाओं के स्थान पर **भारत से वस्तु निर्यात योजना MEIS** और भारत से **सेवा** निर्यात **योजना SEIS** की शुरुआत की है।
- Duty Credit Slip को **हस्तान्तरणीय** (किसी को भी बेचना) बनाना है।



https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (2011)

→ यह नीति औद्योगिक विकास में राज्यों के साथ भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है।

→ 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी **25%** करना और **10 करोड़ रोजगार** के अवसर पैदा करना।

आरक्षित क्षेत्र —

इसका मतलब है कि ~~अब~~ विनिर्माण हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को औद्योगिक लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं वहीं किसी अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लघु उद्योग के लिए **आरक्षित** क्षेत्रों में **विनिर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस** लेना **अनिवार्य** है और उन्हें अपने वार्षिक उत्पादन का **50%** निर्यात करने का **दायित्व निभाना** होगा। इसमें शामिल **उद्योग** (लघु) के 20 क्षेत्र हैं —

- **अचार, सरसों का तेल, मूंगफली** का तेल, ब्रेड
- **माचिस, अगरबत्ती, पटाखे, मोमबत्तियाँ**
- **कपड़े धोने का साबुन**
- लकड़ी का फर्नीचर और फिक्सचर
- कांच की चूड़ियाँ
- स्टील के बर्तन, एल्युमीनियम के घरेलू बर्तन।



कयर उद्योग — कृषि आधारित परंपरागत उद्योग, उत्पत्ति केरल में हुई, हाल ही में तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, असम आदि जैसे **नारियल उत्पादक राज्यों** में फैला हुआ है। यह निर्यात उन्मुखी उद्योग है और वातावरण अनुकूलित होने के कारण तेजी से फैल रहा है और पूरे विश्व का 80% भारत में है।

https://t.me/UPSC_Prelims
https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

मछली उत्पादन —

- अंतर्देशीय — 63%
- समुद्री — 37%

नवीकरण ऊर्जा लक्ष्य —

* 1 लाख 75 हजार मेगावाट 2022 तक (अमृत महोत्सव) —
- सौर ऊर्जा — 1 लाख मेगावाट
- पवन ऊर्जा — 60,000 मेगावाट
- बायोमास — 10,000 मेगावाट
- लघु पनबिजली — 5,000 मेगावाट

भारत के कोर उद्योग — (40%)

i) कोयला ii) कच्चा तेल iii) प्राकृतिक गैस
iv) पेट्रोलियम रिफाइनरी v) बिजली
vi) खाद vii) स्टील viii) सिमेंट

नवरत्न उद्योग — (संख्या — 17)

स्वतंत्र होते हैं। 1 करोड़ रुपये तक का निवेश करने के लिए

महारत्न उद्योग — 10

5 करोड़ रुपये तक का निवेश करने हेतु स्वतंत्र।

i) BHEL ii) GAIL iii) CIL iv) SAIL
v) NTPC vi) ONGC vii) IOC

→ महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न की उपाधियाँ Department of Public Enterprises (Ministry of Heavy Industry) द्वारा दी जाती है।

https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains

https://t.me/UPSC_Prelims

NCERT

खाद्य सुरक्षा

- शहरी – प्रतिदिन २१०० कैलोरी
- ग्रामीण – प्रतिदिन २४०० कैलोरी

https://t.me/UPSC_Mains

खाद्य सुरक्षा

→ शरीर के लिये आवश्यक न्यूनतम पोषण स्तर ।
→ खाद्य उपलब्धता – देश में स्टॉक होना चाहिए ।
→ पहुँच – खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे ।
→ लोगों के पास खरीदने की क्षमता हो (सामर्थ्य)

घटक –

i) **बफर स्टॉक** – सरकार FCI के माध्यम से MSP पर अनाज खरीद कर स्टॉक करती है।

ii) **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (PDS) – इसके माध्यम से गरीब वर्ग में वितरण ।

→ शरीर द्रव्यमान सूचकांक – व्यस्क पोषण मापन ।

→ PDS में **खाद्यान्नों** के अलावा **खाद्य तेल**, **मिट्टी का तेल**, **कोयला और कपड़े** का वितरण भी किया जाता है तथा PDS में किसी **विशेष वर्ग** को ही **सम्मिलित नहीं** किया है **बल्कि संपूर्ण जनसंख्या** को शामिल किया गया है।



https://t.me/UPSC_Prelims https://t.me/UPSC_Mains